RNI NO. DELHIN/2012/48369
वर्ष 8 अंक 26
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 28 नवंबर, 2019
पृष्ठ 16 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

स्पॉटलाईट अवॉर्ड से सम्मानित होंगी जेनिफर लोपेज

विविध-16

शिव तीर्थ में शपथ लेंगे उद्धव

- शिवाजी पार्क में भव्य समारोह का आयोजन- विशिष्ट मेहमानों, दोस्तों, हजारों समर्थकों की मौजूदगी में प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री बनेंगे उद्धव
- ठाकरे संग महाराष्ट्र विकास अघाडी के तीनों दलों शिवसेना, राकांपा व कांग्रेस के दो-दो मंत्री ले सकते हैं शपथ, उपमुख्यमंत्री राकांपा का और स्पीकर कांग्रेस का होगा : प्रफुल्ल पटेल

मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। साथ में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई/नई दिल्ली

महाराष्ट्र की राजनीति और ठाकरे परिवार के इतिहास में नया अध्याय जोड़ते उद्धव ठाकरे गुरुवार को शिवसैनिकों के पवित्र स्थान-शिवाजी पार्क में शाम (6.40 बजे) को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रदेश के शीर्ष राजनीतिक पद पर पहुंचने वाले उद्धव, ठाकरे परिवार के पहले सदस्य होंगे। महाराष्ट्र को भी किसी शिवसैनिक मुख्यमंत्री के लिए बीस साल तक इंतजार करना पड़ा है। मौका भी है और दस्तूर भी लिहाजा शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के 17वें मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए युद्धस्तर पर तैयारी की गई है। अति विशिष्ट मेहमानों की मौजूदगी और महाराष्ट्र विकास अघाडी (शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस गठबंधन) के नेताओं-कार्यकर्ताओं की जबर्दस्त भीड़ को ध्यान में रखकर शिवाजी पार्क के भीतर और आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

दादर स्थित शिवाजी पार्क के साथ शिवसेना का भावनात्मक लगाव रहा है। यहीं पर हर साल वह अपनी दशहरा रैली करती है और इसी पार्क के एक कोने में मुंबई के शेर-बाला साहब ठाकरे का अंतिम संस्कार किया गया था। शिवसैनिक उस स्थान को शिवतीर्थ कहते हैं। कल के शपथ ग्रहण समारोह से ऐन पहले तीनों दलों के नेताओं के बीच मंत्रिमंडल को लेकर अंतिम दौर की चर्चा हुई। बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेसी नेता अहमद पटेल और सी वेणुगोपाल समेत अन्य मौजूद थे। लगभग छह घंटे की चर्चा के बाद वरिष्ठ राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि नई सरकार में एक ही उपमुख्यमंत्री होगा और वह भी राकांपा से। विधानसभा स्पीकर कांग्रेस से होगा। (शेष पेज 10)

भाजपा के साथ सरकार बनाना विद्रोह नहीं था: अजित पवार

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अजित पवार ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जो किया उसे विद्रोह नहीं कहा जा सकता। अजित, अपनी पार्टी और परिवार को झटका देते हुए शनिवार को भाजपा से हाथ मिलाकर देवेन्द्र फडणवीस नीत सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वह राकांपा के साथ ही रहेंगे और पार्टी प्रमुख शरद पवार जो कहेंगे वह उसका पालन करेंगे। अजित ने यहां पत्रकारों से कहा, यह विद्रोह नहीं था। मैं राकांपा का नेता था। क्या राकांपा ने मुझे हटाया? क्या आपने (मुझे राकांपा से बाहर निकालने के बारे में) कहीं पढ़ा? उन्होंने कहा, मैं सभी को बता रहा हूं कि मैं राकांपा में था, राकांपा में हूं और राकांपा में ही रहूंगा।

वित्त मंत्री का दावा-रफ्तार सुस्त लेकिन मंदी नहीं

अर्थव्यवस्था पर घिरी सरकार

- रास में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा, विपक्ष ने गंभीर संकट के प्रति केंद्र को किया आगाह

निर्मला सीतारमण

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बुधवार को राज्यसभा में सरकार पर जमकर निशाना और इस गंभीर संकट के प्रति उसको आगाह किया। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीडीपी दर में भले ही गिरावट आई है, लेकिन यह मंदी नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर आप अर्थव्यवस्था को समझदारी से देखें तो आप पाएंगे कि विकास दर में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी तक मंदी का माहौल नहीं है और मंदी आने का खतरा भी नहीं है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि उनके द्वारा पेश पहले बजट के बाद उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है और ऑटोमोबाइल समेत कुछ सेक्टरों में सुधार होना शुरू हो गया है। बहरहाल, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल यह कहते हुए सदन से वॉकआउट कर गए कि वह अर्थव्यवस्था के सामने पेश चुनौतियों के समाधान पर बात न करके अपना बजट भाषण दे रही हैं। अर्थव्यवस्था में नकदी की कमी होने की बात को खारिज करते हुए सीतारमण ने कहा कि लोन मेले में बैंकों ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे। बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी दी गई, इससे सिस्टम में नकदी बढ़ी।

अर्थव्यवस्था पर सरकार को नाकाम बताने के आरोपों पर वित्त मंत्री ने कहा कि देश की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 2009-2014 के अंत में 6.4 फीसदी रही, जबकि 2014-2019 के बीच यह 7.5 फीसदी पर रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि राजग सरकार में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने सफलतापूर्वक महंगाई पर नियंत्रण किया है। उन्होंने कहा कि साल 2009-14 के दौरान 189.5 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया, जबकि राजग की सरकार में महज पांच वर्षों में 283.9 अरब डॉलर का निवेश आया। चर्चा पर वित्त मंत्री के जवाब देने के दौरान कांग्रेस के वॉकआउट पर सीतारमण ने कहा, 'विपक्ष की साल 2014 से आदत बन गई है कि पहले वह चर्चा की मांग करती है और जब सरकार को जवाब देने की बारी आती है तो वह वॉक आउट कर जाती है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।'

इससे पहले कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब मोदी सरकार को नींद से उठने, वास्तविक आंकड़ों पर गौर करने तथा समस्याओं को दूर करने का सही वक्त आ गया है। कांग्रेस के नेता एवं सांसद राजीव गौड़ा ने कहा, 'ग्रामीण भारत को मोदी सरकार ने रसातल में पहुंचा (शेष पेज 10)

मौसम

अधिकतम	27.4°C (+2)
न्यूनतम	14.5°C (+5)

बाजार

सेंसेक्स	41,020	↑	199
निफ्टी	12,100	↑	63
सोना	38,503	↓	35 /10g
चांदी	45,345	↓	147 /kg

क्विक न्यूज

चारधाम श्राइन बोर्ड को कैबिनेट की मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को उच्च हिमालई क्षेत्रों में स्थित चारधाम सहित प्रदेश के 50 से अधिक प्रसिद्ध मंदिरों के संचालन के लिए चारधाम श्राइन बोर्ड के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के अतिरिक्त उत्तराखंड में मौजूद 47 अन्य मंदिर भी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। बोर्ड के गठन के प्रावधान वाले उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड प्रबंधन अधिनियम, 2019 को मंजूरी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। वैष्णोदेवी और तिरुपति बालाजी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर गठित किए जाने वाले चारधाम बोर्ड को अनिवार्य रूप से वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी। बोर्ड का कार्य मंदिरों की मरम्मत और तीर्थ पुरोहितों के हकों को संरक्षित रखते हुए उसके संचालन के लिए जरूरी कदम उठाएगा।

समय-समय पर सांभर झील के पानी की होगी जांच

जयपुर। सांभर झील के आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासी व अन्य पक्षियों की मौत के मद्देनजर अब झील के पानी की समय-समय पर जांच होगी और इसका समुचित डेटा रखा जाएगा। जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बुधवार को यहां जिला पर्यावरण समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। यादव ने कहा कि वर्तमान त्रासदी में यहां एल्गी टॉक्सेनिटी नहीं थी लेकिन इसकी आशंका को देखते हुए अब समय-समय पर झील के पानी की बायलॉजिकल एवं कैमिकल जांच कर इसका डेटा भी रिकॉर्ड एवं शेयर किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सांभर झील इलाके में हाल ही में हजारों की संख्या में प्रवासी व अन्य पक्षियों की मौत हुई है। बैठक में क्षेत्रिय वन अधिकारी क्षेत्रिय वन अधिकारी (डीएफओ) कविता सिंह ने बताया कि मंगलवार तक झील के जयपुर क्षेत्र में 9358 मृत पक्षियों के अवशेष हटाए जा चुके है, 632 पक्षियों को बचाया गया है एवं 143 को रिंग पहनाई गई है।

कांग्रेस को एक परिवार की चिंता केंद्र को पूरे देश की फिक्र : शाह

- गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने पर कांग्रेस का तीखा विरोध, संशोधन बिल पारित

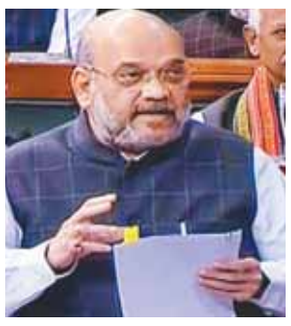

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

एसपीजी कानून में संशोधन पर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विपक्षी दल को केवल एक परिवार की चिंता है, जबकि मोदी सरकार को पूरे देश की जनता की चिंता है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी परिवार को जेड प्लस सीआरपीएफ कवर, एएसएल और एम्बुलेंस के साथ सुरक्षा दी गई है।

वही लोकसभा ने आज कांग्रेस के वाकआउट के बीच विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। निचले सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी सुरक्षा कर्मी को वहां से कम नहीं किया गया है। बल्कि सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि पहले एसपीजी अधिनियम में संशोधन एक ही परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे जबकि इस बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, इन्हें एसपीजी सुरक्षा चाहिए जो प्रधानमंत्री के लिए होती है। लोकतंत्र में जो फैसले जनता करती है उसे स्वीकारा करें, अब आप (सत्ता में) नहीं हैं।

उन्होंने कहा बदले की भावना के तहत कार्रवाई करना कांग्रेस का संस्कार है, हमारी पार्टी का नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। शाह ने कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों की उन चिंताओं को बेबुनियाद बताया जिसमें कहा गया था कि गांधी परिवार की सुरक्षा के संबंध में राजनीतिक बदले की भावना के तहत काम किया गया है। शाह ने कहा, ऐसी भी बात देश के सामने लाई गई कि गांधी परिवार की सरकार को चिंता नहीं है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सुरक्षा हटाई नहीं गई है। सुरक्षा बदली गई है। उन्हें सुरक्षा जेड प्लस सीआरपीएफ कवर, एएसएल और एम्बुलेंस के साथ दी गई है। उन्होंने कहा, इस (शेष पेज 10)

चिदंबरम की हिरासत 11 तक बढ़ी, राहुल और प्रियंका ने तिहाड़ जाकर की मुलाकात

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया था। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को तिहाड़ जेल पहुंच कर आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि दोनों ने करीब 45 मिनट की मुलाकात में पूर्व वित्त मंत्री के प्रति एकजुटता प्रकट की। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले, ईडी ने कहा कि जांच जारी है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की।

मस्जिद की पांच एकड़ जमीन पर दावा कर सकता है शिया वक्फ बोर्ड

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

वसीम रिजवी

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पांच एकड़ जमीन नहीं लेता है तो वह खुद इसके लिए दावा पेश कर सकता है।

शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने गत नौ नवम्बर के अपने फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। अगर बोर्ड यह जमीन नहीं लेता है तो शिया वक्फ बोर्ड इस पर दावेदारी कर सकता है। बोर्ड की आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस सवाल पर कि जब अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने को कहा है। अगर वह जमीन नहीं लेता है तब शिया वक्फ बोर्ड किस हैसियत से दावा पेश कर सकेगा, रिजवी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने खुद माना है कि बाबरी मस्जिद बाबर के शिया कमांडर मीर बाकी ने बनवाई थी, लिहाजा विवादित स्थल शिया वक्फ सम्पत्ति मानी जानी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड विवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए इसी आधार पर सरकार से जमीन मांग सकता है और उस पर जनहित में एक अस्पताल बनाए जाने का प्रस्ताव ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने नौ नवम्बर को अयोध्या में विवादित रहे स्थल पर दावेदारी की शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी है और बोर्ड इस निर्णय (शेष पेज 10)

अयोध्या मामले में जमीयत अगले सप्ताह दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अगले कुछ दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है। मौलाना अरशद मदनी की अगुवाई वाले जमीयत की ओर से जारी बयान के मुताबिक याचिका का मसौदा तैयार हो गया है। सूत्रों का कहना है कि जमीयत की ओर से दो या तीन दिसंबर को याचिका दायर की जा सकती है। मदनी ने कहा, पुनर्विचार याचिका दाखिल करके उनका इरादा देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। अदालत ने हमें जो हक दिया है पुनर्विचार विचार याचिका दाखिल करके, उस हक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उसने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय (शेष पेज 10)

भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर विवादों में

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

लोकसभा में भाजपा सदस्य प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को तब एक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया जब द्रमुक सदस्य ए. राजा अदालत के समक्ष नाथूराम गोडसे द्वारा दिए गए उस बयान को उद्धृत कर रहे थे कि उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा। ठाकुर की टिप्पणी को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध जताए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एसपीजी (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान सिर्फ द्रमुक नेता का बयान ही रिकॉर्ड में जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने बाद में एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ठाकुर की टिप्पणी दर्ज नहीं की गई है। राजा ने कहा कि गोडसे ने स्वीकार किया था कि गांधी की हत्या का फैसला करने से पहले 32 सालों तक उसके मन में गांधी के प्रति द्वेष पनप रहा था। राजा ने कहा कि गोडसे ने गांधी को मारा क्योंकि वह एक खास विचारधारा में विश्वास रखता था। विपक्षी सदस्य जहां ठाकुर द्वारा टोकाटाकी के खिलाफ विरोध जता रहे थे वहीं भाजपा सदस्यों ने उनसे बैठ जाने का अनुरोध किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ ए राजा का बयान रिकॉर्ड में रखा जाएगा। बाद में विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी ठाकुर की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मांग की कि उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इसबीच संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को कहा कि ठाकुर ने पार्टी को बताया कि उन्होंने नाथूराम गोडसे का समर्थन नहीं किया बल्कि वह क्रांतिकारी ऊधम सिंह के बारे में बोल रही थीं।

कैंसर से एक साल में छह करोड़ लोग हो गए बर्बाद

टाटा मेमोरियल सेंटर के प्रतिनिधियों ने संसद की स्थायी समिति को दी जानकारी

अर्चना ज्योति। नई दिल्ली

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) ने हाल ही में संसद की स्थायी समिति को बताया कि हर साल करीब छह करोड़ भारतीय कैंसर जैसी बीमारी के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। टीएमसी ने कहा कि यह जानलेवा बीमारी पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों के लिए एक भारी आर्थिक बोझ साबित हो रही है जो बेहतर इलाज के लिए ट्रेन से तीन-चार दिन का सफर तय कर के टीएमसी आते हैं।

देश में कैंसर के इलाज की सुविधाओं को लेकर निराशाजनक तस्वीर पेश करते हुए टीएमसी ने समिति से कहा 'इस मसले (कैंसर के इलाज) से निपटने में मौजूदा बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। यहां तक कि आयुष्मान भारत के पिछले एक साल के रिकॉर्ड को हमने देखा और पाया कि कैंसर के इलाज में दो तिहाई निजी क्षेत्र की भागीदारी है जिसका परिणाम यह है कि भारत की छह करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे चली जाती है क्योंकि कैंसर के इलाज का खर्चा भारी भरकम है। राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश की अध्यक्षता वाले पैनल ने यह रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में टीएमसी के प्रतिनिधियों के बयान का हवाला काफी विस्तृत में दिया गया है। टीएमसी देश के 11 संस्थानों में से एक है जिसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा मदद दी जाती है। यह देश में कैंसर के इलाज और शोध में शामिल है।

टीएमसी ने बताया कि पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के असमान वितरण के कारण मरीजों को कैसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैंसर के इलाज में देश के इस अग्रणी केंद्र ने छह महीने के दौरान पूरे देश से इलाज के लिए संस्थान में आने वाले 75,000 कैंसर मरीजों की जियो टैगिंग की और पाया कि इसमें पूर्वोत्तर से आने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है उसके बाद उत्तर और पूर्व भारत का स्थान है।

टीएमसी प्रतिनिधियों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश से मुंबई का सफर दो से तीन दिन का होता है। यह मरीजों पर आर्थिक बोझ भी डालता है क्योंकि आमतौर पर वे अपने परिवार के एक सदस्य के साथ आते हैं। इससे पूरे परिवार के जीविकोपार्जन पर असर पड़ता है। टीएमसी ने कहा, 'हमें यह भी कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा पर कुल खर्च का करीब दो तिहाई जेब से जाता है, जो निजी खर्च होता है और केवल एक तिहाई सरकारी मदद होती है और यह तब और कम हो जाता है जब इलाज निजी क्षेत्र में हो। कैंसर पर शोध कर रही अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ग्लोबोकैन के मुताबिक भारत में 2018 में कैंसर के 13 लाख मामले सामने आए हैं, जो 2035 में बढ़कर 17 लाख तक हो जाएंगे। कैंसर के बढ़ते मामलों से चिंतित पैनल ने केंद्र को सलाह दी है कि इसके इलाज के लिए राज्य और जिले में केंद्र स्थापित किए जाए। समिति ने पूर्वोत्तर में बड़ी संख्या में कैंसर के मरीजों पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण संवाद की कमी और कैंसर केंद्रो तक पहुंच न हो पाने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है।

बकाया जमा नहीं कराने पर सरकारी ऑफिस होंगे सील

19 संस्थानों को प्राधिकरण भेज चुका है नोटिस

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

राजस्व बढ़ाने और आर्थिक संकट से उबरने के लिए नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन बकायेदार प्राधिकरण का भुगतान करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में प्राधिकरण को मजबूरन कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाना पड रहा है। अब स्थित सीलिंग तक आ चुकी है। सीलिंग की कार्रवाई कब शुरू होगी इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन नोटिस के बाद मियाद पूरी होने पर रिपोर्ट तैयार कर लेखा जोखा विभाग द्वारा बैठक में प्रस्तुत कर दिया गया है। **-इंदु प्रकाश सिंह, ओएसडी, नोएडा प्राधिकरण**

प्राधिकरण की ओर से 19 सरकारी संस्थानों को बकाया वसूली का नोटिस जारी किया गया था जिसकी मियाद 22 नवंबर को पूरी हो चुकी है। अब प्राधिकरण अपना बकाया वसूल करने के लिए कार्यालयों को खाली कराने के साथ ही सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर सकता है। इस मामले को लेकर प्राधिकरण कार्यालय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी 19 सरकारी संस्थाओं को जारी नोटिस के बाद जमा रकम और आपत्तियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

अधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया कि बकाया रकम जमा कराने के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा उनके अपने मुख्यालयों को डिमांड भेजी गई है और इसकी जानकारी प्राधिकरण को दी गई है। कुछ संस्थाओं की ओर से यह भी कहा गया है कि वह बकाया राशि में केवल मूल धन ही वे चुका सकेंगे। चूंकि वह भी सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं ऐसे में प्राधिकरण द्वारा बकाया राशि पर लगाया चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाए। बकाएदारों का कहना है कि वे प्राधिकरण का बकाया जमा करने को तैयार है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की ओर से उनके प्रतिनिधियों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बकाया राशि में ब्याज माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में इस मामले में जो भी फैसला मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि इस मामले पर देर शाम तक चली बैठक में इन बकायेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई का निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन सामान्य प्रशासन के अधिकारियों की ओर से रिपोर्ट का लेखा-जोखा सीईओ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

नोएडा में तीन तलाक में पहली गिरफ्तारी

नोएडा। सेक्टर 24 थाना पुलिस ने तीन तलाक मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 22 चौड़ा गांव से उसे पकड़ा गया। एसएचओ रामफल सिंह ने बताया कि नोएडा में ट्रिपल तलाक केस में यह पहली गिरफ्तारी है।

आरोपित की पहचान बिहार के मधेपुरा निवासी हैदर के तौर पर हुई है। पीड़ित महिला ने 6 अगस्त को शिकायत दी थी। आरोप है कि उसका पति हैदर किसी अन्य महिला के साथ राजस्थान में रह रहा है। इसकी जानकारी घरवालों को हुई तो समझौता कराया। फिर 15 दिन हैदर उसके साथ रहा। बाद में घर से जेवरात और 15 हजार नकद लेकर उसी महिला के पास भाग गया। मंगलवार को हैदर के चौड़ा गांव आने की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया है।

पार्षद ने किया जीडीए में 10 करोड़ के घोटाले का खुलासा

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

● जीडीए वीसी ने कहा कमेटी बनाकर कराई जाएगी मामले की जांच

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ईडब्यूएस योजना में भवनों के आवंटन में हुए घोटाले को लेकर खुलासा करते भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी।

नगर निगम में भाजपा पार्षद दल के नेता राजेंद्र त्यागी ने जीडीए में ईडब्लूएस भवनों के आवंटन के 10 करोड़ रुपए के आवास घोटाले का खुलासा एक प्रेस कांफ्रेंस में बुधवार को किया और मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने कहा है कि मामले की कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी।

पार्षद त्यागी ने बताया कि इंदिरापुरम के न्यायाखंड में करीब 400 मकानों की पत्रावलियों में हेराफेरी करते हुए मूल आवंटी की जगह नए आवंटियों को मकान दे दिए गए। जिन मकानों का आवंटन फर्जी तरीके से किया गया उनमें 273 की पत्रावलियां 1998 में आग में जल गई थीं। उन्होंने कहा कि आग लगने की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, इसके उलट 273 की बजाय 400 मकानों के दस्तावेजों में हेराफेरी करते हुए मकान की रजिस्ट्री कर दी गई। इस वजह से प्राधिकरण को लगभग दस करोड़ की चपत लगी है।

राजेंद्र त्यागी ने कहा कि अगर इस मामले की तह तक जाएं तो घोटाले की जद में कई अधिकारी और कर्मचारी आएंगे। उन्होंने बताया कि जीडीए ने अपनी आवासीय योजना इंदिरापुरम के न्याय खंड एक, दो एवं तीन में 10360 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण किया। गरीब जनता के लिए बनाए गए इन भवनों का आवंटन 1989 और 1993 के बीच किया गया।

इन आवंटनों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। धांधली को छुपाने के लिए जिस स्थान पर इन मकानों की फाइल रखी गई थी। वहां पर 9 सितंबर 1998 में आग लग गई। इनमें कुछ कागज पूरे जल गए, जबकि कुछ कागजात अधजले मिले। इसमें तत्कालीन उपाध्यक्ष ने जांच कमेटी गठित कर जली हुई फाइलों की सूची बनाने को कहा था। उस दौरान 273 फाइलों की सूची बनाई गई। इन मकानों की रजिस्ट्री कराने के बाद उनके कागजात सूची के साथ संलग्न करने का भी आदेश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जीडीए के बाबुओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर यहीं से खेल शुरू किया। बाबुओं ने सूची में ओवर राइटिंग कटिंग कर दर्ज मकानों के स्थान पर नए मकानों की रजिस्ट्री कर दी।

स्वच्छता सर्वेक्षण पर तीस को होगी मेगा रैली

गाजियाबाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर नगर निगम की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा और मुरादनगर से विधायक अजीत पाल त्यागी की उपस्थिति में एक आवश्यक बैठक की गई।

बैठक में मेयर के साथ निगम आयुक्त दिनेश चंद भी मौजूद रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण के नोडल अधिकारी अरूण कुमार मिश्रा ने बताया कि बैठक में मेगा रैली का आयोजन करने पर चर्चा हुई। रैली में स्कूली बच्चों के अलावा सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन एवं अन्य संस्थाओं की भागेदारी सुनिश्चित की गई है।

एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने वाले तीन गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

थाना ईकोटेक-3 पुलिस ने तीन अंतरर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। ये लोगों की मदद करने के बहाने उनके एटीएम कार्ड के पिन नंबर प्राप्त कर एटीएम कार्ड ही बदल देते थे और बाद में उससे मोटी रकम निकाल लेते थे। एसएसपी ने बताया कि थाना ईकोटेक-3 पुलिस ने बुधवार को एक सूचना के आधार पर इमरत उर्फ इमा, सैफ अली उर्फ सफल तथा मुकीम को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि एटीएम मशीन से पैसा निकालने वाली महिलाएं, बुजुर्ग तथा सीधे-साधे लोगों को ये लोग अपना निशाना बनाते थे। जब इन लोगों से एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकालता तो, आरोपी मदद के बहाने उनसे उनका एटीएम कार्ड का पिन नंबर आदि प्राप्त कर लेते थे, तथा धोखाधड़ी करके उन्हें दूसरा एटीएम पकड़ा कर, उनका असली कार्ड अपने पास रख लेते थे। बाद में ये लोग उक्त एटीएम व पिनकोड के आधार पर बैंकों से पैसा निकाल लेते थे।

हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नेता की ग्रेनो में गोली मारकर हत्या

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नेता संदीप की ग्रेटर नोएडा में गोली मार कर हत्या कर दी गई है। हत्या की जानकारी मिलते ही इलाके के लोगों में सनसनी मच गई है।

मिली जानकारी के अनुसार मृतक संदीप नागर दनकौर क्षेत्र के अट्टा गुजरान गांव का निवासी था। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि गोली किसी अपने ने ही उसे मारी है। मंगलवार रात को कुछ लोग संदीप की मौसी का जमाई और एक परिचित उसे लेने आया था। घर से करीब 100 मीटर दूर बांध के पास उसका शव मिला। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

हालांकि अभी हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में हर कोण से जांच कर रही है। किसी घर वाले या फि र राजनीतिक दृष्टि से उसकी हत्याह हुई है यह भी जांच की जा रही है। संदीप हिंदू युवा वाहिनी को छोड़कर हाल में ही जिला पंचायत का पर्चा भरा था मगर उसका पर्चा किसी कारणवश निरस्त हो गया था। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार उसे जो युवक लेने आए थे वह फार्चूनर गाड़ी में सवार थे। पुलिस अब उस गाड़ी की खोजबीन कर रही है।

फेसबुक पर दोस्ती कर ठग लिए 40 लाख

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● एसएसपी से पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग

फेसबुक पर दोस्ती कर एक महिला ने इंजीनियर से 40 लाख रुपए ठग लिए। पीडित ने बैंक से लोन लेकर आरोपी के खाते में पैसा ट्रांसफ र किया था। ठगी विदेश से कीमती आभूषण व भारतीय करेंसी का पार्सल भेजने के नाम पर की गई। इसकी शिकायत एसएसपी से भी की है।

मूलरूप से जिला मुजफ्फरनगर निवासी मनोज उपाध्याय सेक्टर अल्फा-टू में रहते हैं तथा एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं। फेसबुक पर उनकी दोस्ती एक महिला से हुई थी। महिला ने बताया कि वह लंदन में रहती है। दोस्ती होने के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बीते मई माह में महिला मित्र ने इंजीनियर को बताया कि उसने एक पार्सल भेजा है जिसमें 15 लाख रुपए के आभूषण और 35 लाख रुपए की भारतीय करेंसी है। पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर अंकिता नामक महिला के पास है। वह उनसे संपर्क करें वह उसे सौंप देगी।

आरोप है कि 20 मई को अंकिता ने पीड़ित इंजीनियर मनोज के पास फोनकर पार्सल के बारे में जानकारी दी और डिलीवरी की प्रोसेसिंग चार्ज के लिए 35 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफरर करा लिए। कुछ दिनों बाद जब पार्सल नहीं पहुंचा तो उसने अंकिता से संपर्क किया तो उसने बताया कि कुछ अन्य कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 65 हजार रुपए और चाहिए। पीडित ने यह रकम भी उसके खाते में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद भी पार्सल नहीं पहुंचा तो इंजीनियर मनोज ने अंकिता को फोन किया तो उसने बताया कि पार्सल में कीमती आभूषण और नगदी है, जिससे मनी लांड्रिंग का केस हो सकता है। अंकिता नाम की महिला ने 40 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करने को कहा। महिला ने विश्वास दिलाया कि पार्सल एयरपोर्ट से रिलीज होने के बाद आपकी रकम लौटा दी जाएगी। लालच में आकर पीड़ित ने बैंक से लगभग 24 लाख रुपए का कर्ज लेकर महिला द्वारा बताए गए खाते में ट्रांसफ र कर दिए, लेकिन पार्सल नहीं मिला। इसके बाद से अंकिता का मोबाइल बंद है।

ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने फेसबुक मित्र से बात की तो उसने कहा कि वह उसके खाते में 40 लाख ट्रांसफर करे तो वह कुछ कर सकती है। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. चंद्रमोहन का धौलाना के गांव नंदपुर में स्वागत करते भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवोम तोमर

भाजपा कार्यकर्ता होना भी गौरव की बात : डॉ चंद्रमोहन

धौलाना। गांव नंदपुर में आयोजित भाजपा मंडल की पहली बैठक को संबोधित करने पहुंचे भाजपा वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉ चंद्रमोहन ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का पदाधिकारी ही नहीं कार्यकर्ता होना भी गौरव की बात है। भाजपा की बूथ कमेटी एक मजबूत इकाई है, जिसके कारण भाजपा निरंतर सफलता प्राप्त कर रही है। बैठक में पार्टी संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अन्य महापुरुषों के चित्र नदारद होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष को पार्टी के प्रति निष्ठा और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहां बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव नियमित एवं लोकतांत्रिक ढंग से कराए जाते हैं। सभी पदाधिकारी पूर्ण निष्ठा और निष्पक्षता से दायित्व निभाएं। किसी का चेला और किसी की अगुवाई में रहकर कार्य करना और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शहीद प्यारेलाल शर्मा को दी श्रद्धांजलि

गाजियाबाद। शहर के पूर्व विधायक शहीद प्यारेलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर मालीवाड़ा स्थित शहीद प्यारेलाल शर्मा पार्क में उनके पुत्र, पूर्व विधायक एवं सपा के वरिष्ठ नेता सुरेन्द्र कुमार मुन्नी ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहां लोगों ने उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सुरेन्द्र कुमार मुन्नी के पुत्र प्रशांत कौशिक, बिजेन्द्र यादव, राहुल चौधरी, दिनेश शर्मा, बबली नागर, वीर सिंह चौधरी, विजय चौधरी, वीके अग्निहोत्री, हरेन्द्र अग्रवाल, राशिद मलिक, अजयवीर एडवोकेट, बीके शर्मा हनुमान, श्यामवीर चौधरी, मनमोहन गामा, रमेश यादव एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाराशर, चौधरी तेजपाल सिंह, पार्षद मोहम्मद कल्लन, पार्षद जाकिर अली सैफी, रविन्द्र यादव, हिमांशु पाराशर, ओम त्यागी, दिलीप कोरी, रियासुद्दीन सलमानी, दिनेश कौशिक, श्रीचंद दिवाकर, जब्बार मलिक, दिलशाद इस्लाम, आदेश शर्मा आदि मौजूद रहे।

सपा नेता संग सात फेरे लेंगी पंखुड़ी पाठक

नोएडा। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट पंखुड़ी पाठक और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव जल्द ही विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। सियासी गलियारों में यह रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ है। नोएडा के नवादा गांव के निवासी अनिल यादव का पिछले साल अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। अब वह पंखुड़ी के साथ एक दिसंबर को दिल्ली कैंट स्थित वसुंधरा वाटिका में सात फेरे लेंगे। यह दोनों का प्रेम विवाह है जिसमें परिवार की रजामंदी है। इन चर्चाओं की पुष्टि करते हुए अनिल यादव ने कहा कि दोनों परिवारों में तैयारियां चल रही हैं। छात्र जीवन से राजनीति में आने वाली पंखुड़ी पाठक ने 2010 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। सपा ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वर्तमान में वह कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट हैं।

सेना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

● 55 हजार नकद मोबाइल व कार बरामद

सेना में भर्ती के नाम पर ठगने वाले आरोपियों की जानकारी देते एसएसपी।

बादलपुर थाने की पुलिस ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को बुधवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक सेना का सेवानिवृत्त जवान भी शामिल है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया, थाना बादलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सेना में भर्ती कराने के नाम पर बेरोजगार नवयुवकों से लाखों की ठगी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच की और मुखबिर की सूचना पर आदेश कुमार, लव कुमार और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया। वैभव कृष्ण ने बताया, पुलिस ने उनके पास से करीब 55,000 रुपए नकद, तीन मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है।

एसएसपी ने बताया, पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि आदेश कुमार सेना का सेवानिवृत्त जवान है और लव कुमार एवं प्रमोद कुमार के साथ मिलकर बेरोजगार युवकों को सेना में भर्ती कराने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करता है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने दर्जनों युवकों से ठगी की बात स्वीकार की।

निर्माण कार्यों पर रोक लगने से परेशान हैं दिहाड़ी मजदूर

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते दिहाड़ी मजदूरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। निर्माण कार्यों पर रोक लगने से दिहाड़ी मजदूरों के लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी चुनौती बन गई है।

बढ़ते प्रदूषण स्तर पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया था। साथ ही तमाम निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई थी। इससे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद होने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है।

आंखों में आंसू लिए एक मजदूर ने बताया कि वो अपने परिवार का पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई मजदूरी करके चलाता था, लेकिन लंबे समय से काम ना मिलने के कारण बच्चों का स्कूल जाना छूट गया है।

हिरासत में हुई मौत पर दो पुलिसकर्मी धरे गए

पायनियर समाचार सेवा। हापुड़

कोर्ट में पेश पर जाते दोनों आरोपी।

कोर्ट ने भेजा जेल

हिरासत में थर्ड डिग्री से युवक प्रदीप की मौत के मामले में दो सिपाहियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपी सिपाहियों को जेल भेज दिया।

बता दें कि बीते 13 अक्टूबर को थाना पिलखुवा क्षेत्र के गांव लाखन निवासी प्रदीप तोमर को पुलिस ने हत्या के केस में पूछताछ करने के लिए उठाया था। इसमें प्रदीप की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मृतक प्रदीप के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी थे। परिजनों ने पुलिस पर पीट-पीटकर निर्मम हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस हिरासत में मौत होने पर प्रदेश में हापुड़ पुलिस की खासी किरकरी हुई थी। मामला में कई राजनीति दलों ने भी दोषी पुलिसकर्मियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की थी।

बताया जा रहा है कि प्रदीप तोमर की हत्या का मामले में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद हरकत में आई पुलिस ने बुधवार को दो हत्यारोपी पुलिसकर्मियों मनीष व सोनू को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामले में एक आरोपी इंस्पेक्टर अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है। इस दौरान कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

व्यापारियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों का पुतला फूंका

गाजियाबाद। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर छूट दिए जाने का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। बुधवार को एक और व्यापारी संगठन ने ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

गाजियाबाद उद्योग व्यापारी वेलफेयर एसो. से जुड़े व्यापारियों ने ई-कॉमर्सका पुतला फूंककर विरोध जताया। व्यापारियों ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों के कारण भारतीय खुदरा बाजार चौपट हो रहा है। इनके द्वारा दी जा रही छूट से देश के पांच करोड़ छोटे-मझौले दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

ई-कॉमर्स कंपनियों का पुतला फूंकते गाजियाबाद के व्यापारी।

रंग लाई टीबी विभाग की मुहिम, 90 बच्चों को लिया गोद

जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के तीन हजार सदस्य एक-एक बच्चा अपनाने को तैयार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेतीं सीडीओ अस्मिता लाल।

टीबी यानी क्षय रोग विभाग की मुहिम रंग ला रही है। विभाग के आह्वान पर अब तक जनपद के विभिन्न संगठन और उनसे जुड़े लोग 18 वर्ष से कम आयु वाले टीबी पीड़ित 90 बच्चों को गोद लेने की घोषणा कर चुके हैं। 21 नवंबर को एमएमजी अस्पताल में जिले के केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के साथ विभाग की मीटिंग में इस मुहिम की शुरुआत हुई थी। जिसमें एसो. अध्यक्ष हृदेश कंसल व जिला औषधि निरीक्षक ने दस-दस टीबी पीड़ित बच्चों को गोद लेने की घोषणा की थी।

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में हुई जिला टीबी फोरम की बैठक में आईएमए की ओर से 30, रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से 25, स्वयं सेवी संस्था आईएमडीटी की ओर से 10, आरएनटीसीपी की सहयोगी संस्था से डा. ताहिर ने पांच टीबी पीड़ित बच्चों को गोद लेने की घोषणा की।

जिला क्षय रोग अधिकारी डा. जेपी श्रीवास्तव ने जनपद गाजियाबाद की आरएनटीसीपी की उपलब्धियों, जैसे पब्लिक, प्राइवेट टीबी नोटिफ़िकेशन, सीबीनॉट मशीन टेस्टिंग, डीआर टीबी वार्ड में भर्ती एमडीआर और एक्सडीआर मरीजों और इन मरीजों के लिए आई नई दवा बीडाकुलीन की उपलब्धता से अवगत कराया।

सीएमओ डा. नरेंद्र कुमार गुप्ता ने नि:क्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजो को डीबीटी के माध्यम से दी जा रही पांच सौ रुपए प्रतिमाह की धनराशि के बारे में बैठक में मौजूद सभी सदस्यों को अवगत कराया। सीएमओ के आग्रह पर रेडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्ष डा. किरण गर्ग ने सहर्ष 25 बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाने के लिए गोद लेने की घोषणा की।

इसी प्रकार आईएमए के अध्यक्ष डा. वीबी जिंदल ने 30 बच्चों को गोद लेने का ऐलान किया। ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हृदेश कंसल और जनरल सेक्रेटरी राजीव त्यागी ने घोषणा की है कि हमारी एसोसिएशन के तीन हजार सदस्य हैं, और सभी एक-एक बच्चे को गोद लेने को तैयार हैं।

फैक्टरी में चोरी करने वाला पूर्व कर्मचारी इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

भाजपा के महानगर कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता की मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित कूलर फैक्टरी से चोरों ने लाखों रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद फैक्टरी का पूर्व इलेक्ट्रीशियन मनोज ही वारदात को अंजाम देता हुआ मिला। पीड़ित कारोबारी ने इलेक्ट्रीशियन व उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

गुप्ता ने बताया कि गत 23 नवंबर की रात को वह फैक्टरी बंद करके आए थे। 24 नवंबर को छुट्टी थी लिहाजा 25 नवंबर की सुबह कर्मचारी फैक्टरी पहुंचे तो गेट की ग्रिल कटा हुआ था। इसके बाद वह फैक्ट्री पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो चोरी करने वाले तीन लोगों में मनोज भी शामिल था, जो आठ साल पहले उनकी फैक्टरी में इलेक्ट्रीशियन था।

संजीव गुप्ता ने बताया कि तीनों फैक्टरी में घुसे और एक घंटे के भीतर करीब पांच लाख रुपये कीमत का 10 कुंतल तांबा चोरी कर ले गए। उनका कहना है कि फैक्टरी के गेट पर कैमरा न लगा होने के कारण यह पता नहीं लग सका कि तांबा किस वाहन में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि अगस्त 2018 में भी उनकी फैक्टरी में चोरी हुई थी जिसमें पुलिस ने मनोज को जेल भेजा था।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

केंद्र पर बरसे मुख्यमंत्री- रोकी प्याज आपूर्ति, बढ़े दाम

● मोदी सरकार से सप्लाई फिर शुरू करने का करेंगे लिखित आग्रह

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सीएम केजरीवाल। फोटो रंजन डिमरी

प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र रोजमर्रा के काम आने वाले प्याज को दिल्ली सरकार को सस्ते दाम पर मुहैया नहीं करा रहा। पिछले तीन-चार दिनों से राजधानी को प्याज की आपूर्ति रोक दी गई है जिसके चलते कीमत में उछाल आ गया है।

इन दिनों में प्याज की कीमत 40 रुपये से बढ़कर 90 से 100 रुपये तक पहुंच चुकी है। केंद्र से मिले प्याज को ही दिल्ली सरकार कई जगहों पर स्टॉल लगा कर बेचती है। इसके लिए वह मोदी सरकार को पत्र लिख कर प्याज की सप्लाई जारी रखने के लिए अनुरोध करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने प्याज की बढ़ती कीमतों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की ओर से सस्ती दरों पर प्याज की सप्लाइ बंद कर दी है। यह बहुत दुखद है कि केंद्र की ओर से ऐसा किया जा रहा है। उसकी ओर से रियायती दरों पर मिलनेवाली प्याज को दिल्ली सरकार कई जगहों पर स्टॉल लगाकर बेच रही थी। इससे लोगों को काफी राहत मिली थी। प्याज की कीमत में तेजी देखी जा रही है। खुदरा मंडियों में प्याज 100 रुपये में बिक रहा है।

दुकानदारों का कहना है कि पहले वे एक दिन में 30 से 50 किलो प्याज बेच देते थे। आज उन्हें 10 किलो प्याज भी बेचना मुश्किल हो गया है। गत तीन दिनों में प्याज की कीमत में 20 से 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ओनियन ट्रेडर्स ऑफ आजादपुर मंडी के सचिव श्रीकांत मिश्रा के अनुसार गत दिनों कर्नाटक, नासिक, गुजरात में लगातार बारिश होने की वजह से नवंबर-दिसंबर में निकलने वाली प्याज की फसलें खराब हो गई हैं। यही कारण है कि लगातार प्याज की कीमतों में उछाल आ रहा है। फिलहाल इस समय प्याज की आवक अलवर से हो रही है।

केवल दो-तीन राज्यों से प्याज की सप्लाई होने के कारण मांग पूरी नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि लगातार कीमतों में उछाल आ रहा है। पहले इस सीजन में हर साल नासिक, गुजरात और अलवर से 4 से 5 हजार मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति होती थी। इस समय 1200 से 2 हजार मीट्रिक टन ही प्याज आ रहा है।

तीन दिनों में 20 से 30 रुपये बढ़ी कीमतें। प्याज व्यापारियों के मुताबिक 15 दिसंबर से पहले प्याज की कीमतों में कमी आने की कोई संभावना नहीं है। विधानसभा चुनाव 2020 नजदीक आते ही दिल्ली में हर मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। अनाधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं करें वर्ना फिर धोखा मिलेगा। केंद्र 100 लोगों को रजिस्ट्री देने की बात कह रहा है जो गलत है। हम कहते हैं कि सभी को रजिस्ट्री दो।

आम आदमी पार्टी से पहले की सरकार की नियत खराब थी। वह विकास करना नहीं चाहती थीं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2015-19 तक 8147 करोड़ रुपये खर्च कर इन कॉलोनियों का कायापलट कर दिया। यह काम पहले भी हो सकता था। लेकिन पहले की सरकारों की नियत साफ नहीं थीं। वर्ष 2009 से 2014 तक कच्ची कालोनियों पर महज 1186 करोड़ रुपये खर्च हुए। जबकि आम आदमी पार्टी ने लगभग आठ गुना अधिक खर्च कर कच्ची कालोनियों में विकास कराया है।

पार्टी ने बता दिया कि सत्ता ईमानदारी से भी चल सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है। वहीं अब दिल्ली में विकास की राजनीति होने लगी है। केजरीवाल के अनुसार गत पांच साल में कच्ची कालोनियों का कायापल्ट हुआ है। अब एक दो महीने से भाजपा चर्चा कर रही है कि कालोनियों को पक्का कराएगी। वह पांच साल नाली, सड़क बनवा रहा था तब कहां थी केंद्र सरकर। कच्ची कालोनी में इतना काम हुआ कि भाजपा वोट मांगने लायक नहीं।

कॉलोनियों में सबसे अधिक काम कराया : केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां लोग काम धंधे के सिलसिले में आते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऊपर लोगों को आवास मुहेया करने की जिम्मेदारी थी। मगर आवास उपलब्ध नहीं कराए गए। यही वजह है कि अनधिकृत कॉलोनियां बन गई गई। आप सरकार आई तब से बहुत काम इन कॉलोनियों में हुए हैं। पानी, सीवर की लाइनें डाली गई हैं। सड़कें व नालियां बड़े स्तर पर बनाई गई हैं। दिल्ली सरकार वर्ष 2015 में कैबिनेट से पास कर प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था। केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रही। अब चुनाव नजदीक आता देख तो भाजपा को अनधिकृत कॉलोनियों की याद आ रही हैं। पिछले 5 सालों में कच्ची कॉलोनी के विकास और उसका पक्का करने के लिए हमने काम किया है। जिस तरह पांच साल में कच्ची कालोनियों में विकास हुआ उतना सत्तर साल में कभी नहीं हुआ।

कई इलाकों में ओले-बारिश, धुला प्रदूषण

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के शहरों में नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। गाजियाबाद और हापुड़ में ओले भी पड़े। पानी बरसने से मौसम में काफी बदलाव आया है।

तेज हवा चल रही है, ठंड बढ़ गई है और प्रदूषण में काफी कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को फिर कहीं-कहीं वर्षा हो सकती है। इससे जहां तापमान में और गिरावट आएगी, सुबह के समय कोहरा भी परेशान कर सकता है।

पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों बारिश होने से राजधानी की वायु गुणवत्ता में बुधवार को मामूली सुधार आया है। अब यह 'मध्यम' श्रेणी में है जबकि पिछले दो दिन से वायु गुणवत्ता का स्तर खराब श्रेणी में था। एक्यूआई सुबह 7 बजकर 45 मिनट पर 175 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (सफर) ने मंगलवार को बताया कि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजकर 42 मिनट पर 254 रात में यह 272 तक चढ़ा। वहीं, बुधवार शाम छह बजे एक्यूआई 109 पर रहा।

यह मॉडरेट श्रेणी में है यानी अच्छी श्रेणी से नौ प्वाइंट ऊपर। वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी सफर के लगभग सभी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर रही जबकि धीरपुर में यह अच्छी स्थिति में दर्ज की गई। नोएडा में जहां पीएम 2.5 का स्तर शाम छह बजे 89 दर्ज किया गया, एयरपोर्ट, मथुरा रोड, लोधी रोड, आईआईटी, पूसा में 93 के आसपास रहा। चांदनी चौक में 189 और डीयू में 158 तो आया नगर और गुरुग्राम में यह 107 तक पहुंचा। मंगलवार शाम इसी वक्त ज्यादातर केंद्रों पर एक्यूआई 260 से ऊपर था। हवा साफ होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। मौसम विभाग का कहना है कि अफगानिस्तान और आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है।

बृहस्पतिवार की रात से फिर से तेज उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी बर्फीली हवा दिल्ली की तरफ आएंगी, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी।

अगले 24 घंटों में फिर हल्की बारिश दिल्ली में हो सकती है। मौसम में बदलाव के कारण सुबह के समय कई इलाकों में कोहरा छाएगा।

मीडिएशन सेंटर बनेंगे रोल मॉडल

● सीएम ने छह नए सेंटरों का किया उद्घाटन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मोहल्ला क्लीनिक दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। उसी तर्ज पर दिल्ली के मीडिएशन सेंटर को भी रोल मॉडल बनाएंगे। जिससे लोगों के आपसी विवादों का निपटारा बगैर पैसा खर्च किए व समय बर्बाद किए हो सके। पूरे भारत में मीडिएशन सेंटर खोले गए लेकिन हर जगह सेंटर एक-दो साल चलकर बंद हो गए।

वहीं राष्ट्रीय राजधानी में मीडिएशन सेंटर ने दस साल पूरे कर लिए। साथ ही लोगों का विश्वास इसमें इतना बढ़ा कि आज 6 नए मीडिएशन का उद्घाटन कर रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली डिस्प्यूट रिज्योल्यूशन सोसायटी (डीडीआरएस)के स्थापना के दस साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि दिल्ली डिस्प्यूट रिज्योल्यूशन सोसायटी (डीडीआरएस)ने दस साल में काफी कुछ किया है। इन सालों में देश में मीडिएशन सेंटर खोलने की कई कोशिश हुई लेकिन अन्य राज्यों में सब बंद हो गए।

लेकिन दिल्ली में इसने कई सफलता हासिल की। लोगों को इसके लिए बधाई। दिल्ली में सेंटर बंद नहीं हो रहे बल्कि नए खुल रहे हैं। सीएम ने बताया कि मीडिएशन सेंटर से उन्हें गांधी के जीवन की एक घटना याद आती है। वह वकील थें। साउथ अफ्रीका के फार्म में वह नौकरी कर रहे थें। उन्हें पहला केस मिला। केस बहुत बड़े आदमी का था। उन्होंने केस में दोनों पार्टी को बैठाकर समझौता करा दिया। फार्म नाराज हो गया। उसे केस चलने से बहुत पैसा मिलने वाला था। मीडिएशन सेंटर भी इसी कांसेप्ट पर हैं। यह बहुत पावरफूल आइडिया है। मोहल्ला क्लीनिक को दुनिया के लिए मॉडल बनाया। वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल बने हैं।

केजरीवाल पर अब लोग भरोसा नहीं करते : भाजपा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अनाधिकृत कॉलोनयों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के मुद्दे पर आप और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कच्ची कॉलोनियों को नियमिति करने के लिए दूसरी सरकारों के सीर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। केजरीवाल झूठ की मशीन है। अनधिकृत कालोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने में सबसे बड़ी बाधा केजरीवाल खुद थे। उन्होंने इन कॉलोनियों में कोई काम नहीं किया। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजधानी को नरक से भी बदतर करार दिया है। अब लोग मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते है।

मनोज तिवारी के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनधिकृत कालोनियों में न पानी की पाइप लाइन डलवायी है और न ही सड़कें बनवाई हैं। उन्होंने जिन कालोनियों में नई पाइपलाइन डलवाने और साफपानी आपूर्ति करने का दावा किया था भाजपा के रियल्टी टेस्ट में उनके दावों की पोल खुल गई है।

जेएनयू छात्रों ने बनाई मानव श्रृंखला

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जेएनयू में फीस वृद्धि के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में बुधवार को दिल्ली के विभिन्न संस्थानों के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई। जेएनयू छात्रसंघ ने सस्ती और सुलभ शिक्षा के लिए देशभर के विश्वविद्यालयों और छात्रों से 27 नवंबर को राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी।

कनॉट प्लेस के भीतरी सर्किल में सेंट्रल पार्क के चारों ओर छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई। वे ढपली बजा रहे थे और हल्ला बोल का नारा बुलंद कर रहे थे। उनके हाथों में नई शिक्षा नीति का विरोध करो, चरमपंथियों ने दिखा दिया-हाथों में किताब लेने वाली लड़की से वे सबसे अधिक डरते हैं, फीस को कम करो जैसे नारे लिखी तख्तियां थीं। जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आईसी घोष ने कहा कि फीस कम करने का आंदोलन सिर्फ जेएनयू के लिए नहीं है, यह पूरे देश के संस्थानों के लिए है। हमारे समर्थन में पश्चिमी बंगाल में जेएनयू एल्युमनी ने बुधवार को मार्च निकाला है। इससे छात्र काफी खुश हैं। यह अब देशव्यापी आंदोलन बन चुका है।

कूड़े को अलग-अलग करने की जिम्मेदारी निभाएं लोग: बैजल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● यह समय कूड़े से सोना बनाने का है : श्रीश्री

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ और हरित दिल्ली के बारे में लोगों को जागरूकता बनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग और एनडीएमसी ने प्रति दिन 1 टन गीले कचरे को संसाधित करने के लिए हाथ मिलाया है। उन्होंने अपनी तरह का पहला स्वच्छ कंपोस्टिंग प्लांट लॉन्च किया है जो 100 प्रतिशत जैविक खाद का उत्पादन करेगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट (आर्ट ऑफ लिविंग) के सहयोग से संयंत्र की स्थापना की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा नागरिकों को अपने घरों से ही कूड़े को अलग-अलग करने की आदत डाल कर, इसमें सहयोग करना होगा। बैजल यह भी कहा कि समाज को अपनी सोच बदल कर ज्यादा कूड़ा उत्पन्न नहीं करना चाहिए और इसको इस प्रकार घर में ही अलग-अलग करना चाहिए।

इस अवसर पर रविशंकर ने कहा कि यह समय कूड़े सोना बनाने का है और प्रदूषित वातावरण को सुंगधित उद्यानों में बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

खुले में कूड़ा व सीवेज डालने पर सख्त कार्रवाई के आदेश

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में हॉकर द्वारा कूड़ा और सीवेज डालकर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में एनजीटी ने रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसडीएमसी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, जल बोर्ड और द्वारका एसडीएम को इस मुद्दे पर तथ्यात्मक और एटीआर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। डीपीसीसी को इस मामले में नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

मामले की सुनवाई आगामी 28 जनवरी को होगी। एनजीटी ने कहा कि यदि उसके आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित पक्षों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। फेडरेशन ऑफ विकास नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिंचाई विभाग की खाली पड़ी जमीन पर हॉकरों द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है। यहां आए दिन कूड़े में आग लगा दी जाती है। इससे प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा नजफगढ़ ड्रेन में सफाई से निकला सीवेज भी यहीं डाला जाता रहा है।

अक्षरधाम के विस्तार में नियमों का उल्लंघन नहीं : एनजीटी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● यमुना के तटीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है मंदिर, जुर्माने से भी मिली छूट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को कहा कि यहां अक्षरधाम मंदिर के विस्तारित ढांचे को पर्यावरण मंजूरी देने में एसईआईएए द्वारा कोई गलती नहीं की गई और यह यमुना के तटीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मंदिर प्रबंधन किसी जुर्माने के लिए जिम्मेदार नहीं है। शीर्ष न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि यह इलाका यमुना के तटीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। पीठ ने कहा कि हम इस अर्जी को स्वीकार करते हैं और हमारा कहना है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। साथ ही, परियोजना के प्रस्तावक किसी उल्लंघन को दर्शाए जाने के अभाव में कोई राशि जमा करने के जिम्मेदार नहीं है। अधिकरण ने कहा कि जब कोई उल्लंघन ही नहीं हुआ तो कोई राशि क्यों जमा कराई जाए। ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। इस तरह, उच्चतम न्यायालय के फैसले और इस अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आलोक में एसईआईएए द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी में कोई त्रुटि नहीं है।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए एसपीएमआईएल से किया समझौता

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बेहतर कचरा प्रबंधन और कचरे के निष्पादन के लिए आज वेस्ट टू वंडर पार्क में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग इण्डिया लिमिटेड के साथ समझौता किया। इस प्रस्तावित प्लांट द्वारा 700 घनमीटर बायो गैस बनेगी। जिससे लगभग 1400 यूनिट बिजली और 600 जैविक खाद का उत्पादन होगा। इस प्लांट द्वारा बनाई गई जैविक खाद का प्रयोग निगम के पार्कों में किया जाएगा। एसडीएमसी के आयुक्त ज्ञानेश भारती ने बताया की कॉरपोरेट सोशल रेसपोंसिबिलिटी के तहत इस प्रोजेक्ट को शुरु करने के लिए 2.94 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है जिसमें 5 वर्ष तक संचालन और रखरखाव की लागत भी शामिल है। वैसे इस प्रोजेक्ट की लागत 1.44 करोड़ है। इस प्लांट में वेस्ट टू वंडर पार्क की 5 किमी की सीमा में आने वाले निगम के 250 पार्कों के हरित कचरे का प्रयोग किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बिहार को स्वर्ण, असम को रजत और आंध्र प्रदेश को कांस्य पदक मिला

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विजेताओं को पुरस्कृत करते केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल।

राजधानी के प्रगति मैदान मे 14 दिन तक चला अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला बुधवार को समन्न हो गया। अंतिम दिन मेले को दिखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी।

वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने अपने सामानों पर भारी छूट दी। इसमें गर्म कपड़ों से लेकर जूतों पर अधिक छूट देखने को मिली। गर्म कपड़ों की खरीदारी को लेकर 50 फीसद तक छूट देकर लोगों को आकर्षित किया गया। हालांकि इस बार व्यापार मेले में खरीदारी को लेकर लोगों में उदासनीता देखी गई मगर अंतिम दिनों में कुछ भरपाई भी दिखने को मिली। समापन समारोह में कुछ राज्यों के मंडपों और अन्य देशों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। गोयल ने व्यापार मेले की सफलता पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह मेला एशिया में एक प्रतिष्ठित इंवेट है। इस बार मेले में करीब चार लोगों ने शिरकत की। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी वर्ष में 15 लाख दर्शक व्यापार मेला देखने पहुंचेंगे।

2020 के लिए थीम ईज ऑफ लिविंग होगा, जहां आईटीपीओ में सभी हितधारकों के साथ-साथ व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विविध क्षेत्रों में भारत की सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक होगा। उन्होंने युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने स्टार्ट अप और स्टैंडअप पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

इस दौरान गोयल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार प्रदान किया। व्यापार मेले में सहयोगी पार्टनर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, फोकस कंट्री रिपब्लिक ऑफ कोरिया और फोकस स्टेट्स बिहार और झारखंड को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के श्रेणी में बिहार को स्वर्ण, असम को रजत और आंध्र प्रदेश को कांस्य पदक मिला। वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल को जूरी अनुशंसा प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

इस अवसर सीएमडी आईटीपीओ एल.सी. गोयल तथा राजेश अग्रवाल, संजय चड्ढा, शशांक प्रियांक, भारत और विदेशों से प्रतिभागी, राजनयिक वाहिनी के सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित थे।

चोरी के सामान समेत दो शातिर पकड़े गए

नई दिल्ली। चोरी के कई मामलों को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तीन लाख की नकदी और ज्वैलरी जब्त की गई है। आरोपियों की पहचान रवि और सौरभ के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि एक अटैची से तीन लाख नकदी व अन्य सामान चोरी हो गया है।

मामले में जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी को खंगाला गया। इस दौरान दोनों आरोपियों की पहचान हुई। इन्होंने चोरी की ज्वैलरी को पास के ही डीडीए पार्क में छिपा दिया था।

इनके पास से पुलिस को 38 कानों की रिंग, चांदी की पायल, सोने की चेन और एक सोनी का लॉकेट बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

संक्षिप्त समाचार

शहीदी पर्व की तैयारियों को लेकर मीटिंग

नई दिल्ली। गुरु तेग बहादुर का शहीदी पर्व की तैयारी पूरी हो चुकी है। पर्व एक दिसंबर को मनाया जाना है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वरिष्ठ बीबी रणजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि क गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ मीटिंग लेकर उन्हें दिल्ली कमेटी द्वारा 1 दिसंबर को शहीदी पर्व संबंधी निकाले जा रहे नगर कीर्तन में बच्चों को शामिल किए जाने के साथ-साथ यह भी विचार किया गया कि बच्चों को पूरे अनुशासन में रखने के लिए विशेष प्रयास किये जायें। प्रिंसिपलों को यह भी हिदायत दी गई कि बच्चों को गुरु साहिब की बाणी सलोक महला 9 की बाणी की तैयारी करवाई जाये इस मीटिंग में डा. सुखवंत कौर प्रिंसीपल जी.एस.पी.एस वसंत विहार, हरप्रीत कौर हरगोबिंद एन्कलेव, सतबीर सिंह लोधी रोड, हरप्रीत कौर कालका जी एवं प्रकाश सिंह गिल, जगजीत सिंह शामिल हुए।

सीलिंग को लेकर कैट ने लिखा हरदीप पुरी को पत्र

नई दिल्ली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को भेजे गए एक पत्र में कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग की मार से बचाने के लिए एक आम माफी योजना लाने की आग्रह की है। कैट ने अपने पत्र में ने दिल्ली में व्यापार के सुनियोजित विकास की विफलता के लिए पिछली सरकारों द्वारा पूर्व मास्टर प्लान के विभिन्न प्रावधानों के समय पर कार्यान्वयन न करने एवं में अधिकारियों के लापरवाह रवैये को जिम्मेदार ठहराया है जिसके कारण दिल्ली के व्यापारी सीलिंग के दुष्चक्र में फंस गए है। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों को वर्ष 2006 से सीलिंग का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, हालांकि केंद्र सरकार ने सीलिंग मुद्दे को सुलझाने के लिए वर्ष 2014 से हर प्रयास किया और काफी विषय बहुत हद तक हल हो गए किन्तु सभी हिस्सों के व्यापारियों पर सीलिंग की तलवार लटकी रहती है।

प्रदूषण पर जारी प्रतिबंध पर व्यापारियों ने जताई चिंता

नई दिल्ली। विशेषज्ञों व व्यवसायियों की निर्माण कार्य से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग को लेकर एक बैठक कॉन्स्टिट्यूशन में संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि निर्माण पर प्रतिबंध होने के कारण हजारों उद्योग बंद हो गए है और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। वहीं लाखों मजदूर अपने गांव को पलायन कर रहे है। किराए के संपत्ति पर काम करने वाले व्यवसायी अपने किराए का भुगतान करने में असमर्थ है। व्यवसाय से जुड़े मालवाहक गाड़ी, जेसीबी, पोकलैंड आदि मशीनों के किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2016 में पहली बार निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा। चेयरमैन भूरे लाल ने प्रदूषण के ग्रैप तैयार किए। पिछले 1 सप्ताह से प्रदूषण का स्तर लगभग सामान्य हो गया है, लेकिन विडंबना यह है कि प्रदूषण का स्तर कम होने के बाद भी हमारा उद्योग प्रतिबंधित क्यों है।

मछली व मखाना, मिथिला संस्कृति की पहचान : कीर्ति

नई दिल्ली। बदरपुर में जगदम्बा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह में दिल्ली प्रदेश काँग्रेस अभियान समिति के चेयरमेन कीर्ति आजाद ने लोगों को संबोधित किया। इस मोके पर उन्होंने मिथिला संस्कृति, लोकभाषा के महत्व व मैथिली भाषा संस्कृति के विकास से जुड़े आयामों पर चर्चा किया। पान, मखाना, मछली, पाग इत्यादि को मिथिला के संस्कृति का मुख्य पहचान बताया। आजाद ने मिथिला संस्कृति के बारे मे बताते हुए कहा कि मिथिला की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार बहुत ही पौराणिक और प्रमाणित है। उन्होंने कहा कि इसका धार्मिक प्रमाण भी है, त्रेता काल में लिखे रामायण में मां जानकी, मां सीता के मायके का वर्णन है। गंगा जी से उत्तर चले जाने पर मिथिला का 22 जिला है जो कि बिहार राज्य का हिस्सा है। बाबा विद्यापति के यहाँ खुद महादेव उगना बन कर रहते थे, उनके स्मृति में हर वर्ष जगदम्बा विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन होता है।

ऑटो मोबाइल क्षेत्र में नई तकनीक, रिसर्च पर करना होगा काम: नितिन गडकरी

पर्यावरण प्रदूषण जैसी स्थिति से बचने को भी नए विकल्प करने होंगे तैयार

पायनियर समाचार सेवा, गुरुग्राम

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऑटो मोबाइल क्षेत्र में भविष्य की जरूरत के अनुरूप निरंतर नई तकनीक व रिसर्च पर काम करना होगा। पर्यावरण प्रदूषण जैसी स्थिति से बचने के लिए भी नए विकल्प तैयार करने होंगे। वे बुधवार को यहां मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में आयोजित तीन दिवसीय न्यूजेन सम्मिट-2019 का शुभारंभ करने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहे नए अनुसंधान व तकनीकों की जरूरत के संबंध बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि ऑटो मोबाइल सेक्टर में सुधार की दिशा में आईकैट सेंटर गुरुग्राम की टीम अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक रूप से मजबूती की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ा आर्थिक शक्ति होगा। इस आर्थिक शक्ति में आटोमोबाइल सेक्टर की अहम भूमिका होगी। देश के सामने कई चुनौतियां भी है, जिन पर सफलता पाने के बड़े स्तर पर प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल के रूप में और भी विकल्प तैयार करने होंगे, ताकि भविष्य की जरूरतों के अनुसार ईधन की जरूरत को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे स्वयं कृषि क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। डीजल व पेट्रोल के विकल्प के रूप में सीएनजी व हाईड्रोजन जैसी तकनीक पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अधिक कॉम्पटीशन है। आटो मोबाइल में मैनुफैक्चरिंग की दृष्टि से भारत काफी अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय क्वालिटी की दृष्टि से अच्छी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन

इससे पहले आईकैट के निदेशक दिनेश त्यागी ने केंद्रीय मंत्री व अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया तथा तीन दिवसीय सम्मिट की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने सम्मिट में भाग ले रही कंपनियों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। संकल्प वेलफेयर सोसायटी के प्रेसीडेंट वासुदेव भसीन को आईकैट की तरफ से पांच लाख रुपये का तथा यूकेबी एग्रोटैक को 51 हजार रुपये की राशि का चेक केन्द्रीय मंत्री द्वारा भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि न्यूजन मोबिलिटी समिट 2019 द्वारा आयोजित सम्मेलन की एक श्रृंखला में पहली है, और लगभग एक साल पहले घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि इसका लाभ देश और दुनिया में लगभग 125 वर्षों से चल रहे आईसी इंजन के लिए उपयुक्त विकल्प खोजने में मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे अधिक ध्यान वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नए तकनीकी समाधान विकसित करने पर है। आईकैट में हमारे इंजीनियर इस दिशा में शोध कर रहे हैं।

प्रतिदिन 30 किमी की गति से सड़क निर्माण का दावा

प्रतिदिन औसतन 30 किलोमीटर की गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है। अनेक नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। दिल्ली के आसपास नए-नए एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं, जिनमें द्वारका एक्सप्रेस-वे, रिंग रोड दिल्ली शामिल हैं। इसी प्रकार, दिल्ली से मुंबई तक एक लाख करोड़ रुपये की लागत से एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा, जो हरियाणा राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र से गुजरेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सरकार ने अनेक नए एक्सप्रेस-वे मंजूर किए हैं, ताकि अच्छे सड़क मार्ग बनें, जिससे वाहनों में ईधन की खपत में भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि देश में बहुत अच्छी गुणवता के रोड बनाए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया का सपना भी तभी पूरा होगा, जब भारत में नई-नई तकनीकी पर काम होगा तथा अच्छे सड़क मार्ग तैयार किए जाएंगे। सरकार का सबसे पहला प्रयास है कि वायु, जल, भूमि प्रदूषण पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। देश में नदियों की सफाई पर भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। भारत में अब वॉटर यातायात पर काम किया जाएगा, जोकि सड़क व रेलवे पर होने वाले खर्च तुलना में बहुत सस्ता होगा।

प्रजापति समाज ने किया डिप्टी स्पीकर गंगवा का स्वागत

गुरुग्राम। हिसार के नलवा से बीजेपी की टिकट पर विजयी हुए विधायक रणबीर सिंह गंगवा को हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर चुने जाने से प्रजापति समाज के लोगों में भारी उत्साह है।

प्रजापति समाज व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रणबीर सिंह गंगवा को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला का आभार प्रकट किया और मिठाई बांट कर एक दूसरे को बधाई दी। बधाई देने वालों में प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल प्रजापति, महाराज दक्ष प्रजापति संघ के चेयरमैन शिवताज प्रजापति, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामसिंह कसनिया, उपाध्यक्ष रामेहर बारावाल, प्रदेश सचिव मनु देव मास्टर, जिला महामंत्री जय भगवान खंडेवला, कुलदीप, रघबीर, ओमप्रकाश फाजिलपुर, सुरत सिंह मुंडाखेडा, विनोद डिघलिया, त्रिलोक चंद आदि ने रणबीर सिंह गंगवा की नियुक्ति करने से न केवल प्रजापति समाज का, बल्कि समस्त ओबीसी समुदाय का सरकार द्वारा मान बढ़ाया है। इसके लिए सभी समाज के लोग सरकार के अभारी हैं।

संक्षिप्त समाचार

बदमाशों ने यात्री को बंधक बनाकर लूटा

सोहना। टैक्सी चालक सहित पांच बदमाशों ने यात्री को बंधक बना हथियार के बल पर नकदी लूटी तथा बाद में एटीएम छीन खाते से 12 हजार रुपये और निकाल लिए। यात्री को बदमाशों ने आंखों पर कपड़ा बांधकर सुनसान जगह पर छोड़ दिया। सोहना सिटी थाना पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जिला नूंह का गांव मुढैता मूल निवासी अलाउदीन पुत्र रमजान ने बताया कि उसका हाल निवास गुरुग्राम में लक्ष्मी गार्डन के पास है। वह रविवार को गुरुग्राम से अपनी ससुराल गांव चाहलका में आया था। जहां से रात करीब नौ बजे अपने घर गुरुग्राम जाने के लिए सोहना बस स्टैंड के बाहर खड़ा वाहन का इंतजार कर रहा था। तभी एक टैक्सी कार उसके पास आकर रुकी। जिसमें चालक के अलावा चार और लोग बैठे हुए थे, जो अपने आपको यात्री ही बता रहे थे। उसे भी चालक ने गुरुग्राम चलने की कहते हुए पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। गुरुग्राम की तरफ कुछ दूरी पर चलने के बाद चालक ने कार को वापस बाईपास की तरफ मोड़ दिया। जब उसने चालक से कारण पूछा तो उसने बताया कि बाईपास पर एक दुकान के अंदर मोबाइल फोन रह गया है। बाईपास आने पर पीछे उसकी सीट पर साथ बैठे तीन लोगों ने उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। चालक टैक्सी कार को नूंह की तरफ लेकर चलने लगा। एक बदमाश ने उसके ऊपर पिस्तौल तान दी। और पर्स, एटीएम कार्ड तथा जेब में रखे 3500 रुपये लूट लिए।

औषधि पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं को बचाने की पहल

सोहना। सोहना के बीडीपीओ कार्यालय परिसर में जैव विविधता समिति सदस्यों को औषधि पेड़-पौधों और लुप्त होते जा रहे पक्षियों व जीव जंतुओं की परवरिश करने का प्रशिक्षण दिया गया। इससे ग्राम पंचायतों में ऐसे जीव जन्तुओं की पहचान करने तथा औषधि पेड़-पौधों को तलाश करने की सलाह भी दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वन्य प्राणियों तथा आबादी क्षेत्र में रहने वाले विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे ही आबादी क्षेत्र तथा आस पास के जंगल में जड़ी-बूटी वाले पेड़-पौधों को भी नजर अंदाज किया जा रहा है। लेकिन औषधि वाले पेड़-पौधों का जीवन में कितना महत्व है, ऐसे पेड़-पौधों को बचाना कितना जीवन में उपयोगी है, मानव जीवन में अपनी सुरीली आवाज तथा रहन-सहन से मनोरंजन करने वाले वन्य प्राणियों से लेकर परिंदों को बचाने के लिए विशेष मुहिम चलाने की पहल कर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्राम पंचायत सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति सदस्यों तथा गणमान्य लोगों को समझाया जा रहा है। जिसको लेकर बुधवार को सोहना के बीडीपीओ कार्यालय परिसर में जैव विविधता समिति सदस्यों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर नवज्योति इंडिया फाउंडेशन से पूनम तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय से आई अंजली ने प्रशिक्षण दिया।

नागरिक अस्पताल में पांच साल से जनरेटर बना शो पीस

सोहना। सोहना के नागरिक अस्पताल में रखा खराब जनरेटर पिछले पांच साल से शो पीस बना हुआ है। यहां के आपातकाल वार्ड और रोगी वार्ड में इन्वर्टर की सप्लाई से जैसे-तैसे काम चलना पड़ रहा है। आंधी, बरसात या बिजली के लगने वाले लंबे कट के दौरान सोहना के नागरिक अस्पताल में अंधेरा छा जाता है। क्योंकि नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी में बिजली सप्लाई के लिए रखा जनरेटर पिछले पांच वर्षों से खराब खड़ा है। जिसको ठीक कराने के लिए उच्चाधिकारियों को मौखिक व लिखित रूप से स्थानीय अधिकारी कई बार कहकर नए जनरेटर की मांग की है, लेकिन अस्पताल प्रभारियों की उक्त मांग को पूरा नहीं किया गया है। बिजली सप्लाई गुल होने के साथ ही रोगियों के वार्ड में अंधेरा छा जाता है। रात के समय में तो रोगियों व उसके रिश्तेदारों को काफी परेशानी होती है। विशेषकर जच्चा-बच्चा वार्ड में परेशानियां होती हैं। जहां पर बिजली गुल होने पर मच्छरों का आतंक एक पल की नींद तक नहीं सोने देता है। ऐसे में मासूम नवजात बच्चों को बीमारियां होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। रोगी वार्ड में तो रात के समय में मोमबत्तियां जलाकर बिजली आने का इंतजार घंटों करना पड़ता है।

बैंकों में नहीं हो सकती नकद सीवरेज-पानी शुल्क की अदायगी

गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के नगर निगम गुरुग्राम के अधीन सेक्टरों के निवासी सीवरेज और पानी के शुल्क की अदायगी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंकों में स्थित नगर निगम खातों में ऑनलाइन बैंकिंग, एनईएफटी, क्रेडिड कार्ड एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। बैंकों में नकद राशि के रूप में अदायगी नहीं की जा सकती। नागरिक घर बैठे नगर निगम गुरुग्राम की वेबसाइट पर पे वाटर बिल आईकॉन को क्लिक करके ऑनलाइन बैंकिंग, एनईएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क की अदायगी करें। इसके अलावा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एमसीजी कंज्यूमर ऐप डाउनलोड करें तथा सीवरेज एवं पानी के बिलों की अदायगी ऐप के माध्यम से भी करने की सुविधा है। इस कार्य के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी एवं सेक्शन ऑफिसर राजेश गुप्ता ने बताया कि नकद राशि के रूप में भुगतान केवल नगर निगम के कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केन्द्रों में ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जानकारी मिली है कि कुछ नागरिक उक्त बैंकों की शाखाओं में जाकर नकद भुगतान करने गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि उक्त बैंकों में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सीवरेज और पानी के शुल्क की अदायगी हेतु खाते खुलवाए गए हैं। इन खातों में केवल नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही शुल्क की अदायगी की जा सकती है। जिन नागरिकों को नकद भुगतान करना है, वे नगर निगम के सेक्टर-34 स्थित कार्यालय, सेक्टर-42 सामुदायिक केन्द्र स्थित कार्यालय तथा सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालयों के नागरिक सुविधा केन्द्रों में जाकर भुगतान कर सकते हैं।

पंचों की सहमति से जीशान बने मल्हाका गांव के सरपंच

नूंह। नूंह जिले के गांव मल्हाका में लंबे संघर्ष के बाद डीसी के आदेशानुसार बीडीपीओ उपमा व ग्राम सचिव तारिफ की मौजूदगी में कार्यवाही सरपंच के लिए मल्हाका गांव के पांच पंचों की सहमति से पूर्व सरपंच सपात खान के भाई के लड़के जीशान को सरपंच पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। जीशान के लिए पांच मेंबरों ने अपनी सहमति जताकर सरपंच पद पर नियुक्त करवाने में अपना पूर्व सहयोग किया। सरपंच पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद 26 वर्षीय युवक जीशान ने कहा कि गांव के विकास कार्यों को तेज गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर काम गांव की भलाई के लिए किया जाएगा।

मारपीट कर चालक से ट्रक छीनने के आरोप में दो गिरफ्तार

नूंह। जिले की पुलिस चौकी आकेड़ा अंतर्गत नूंह मरोड़ा गांव के समीप से गत 11 नवबंर को दो आरोपियों द्वारा एक चालक के साथ मारपीट कर ट्रक छीनकर ले जाने वाले दो शातिर आरोपियों को आकेड़ा चौकी पुलिस ने रोहतक के समीप से गाड़ी में लगे जीपीएस की मदद से आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी प्राप्त कर ली है।

पुलिस ने बताया कि बीते 11 नवंबर को आरोपी आरिफ पुत्र हाकम निवासी पापड़ा थाना पिनगवां व मुस्तकीम पुत्र पहलू निवासी आली मेव थाना बहीन ने नूंह के मरोड़ा गांव के समीप से रात में ट्रक चालक इरसाद निवासी राणीका के साथ मारपीट कर ट्रक छीन लिया। जिसको आरोपी रोहतक की ओर ले गए। चालक इरसाद ने सारी घटना के बारे में अपने मालिक को बताया तो आरोपियों के खिलाफ आकेड़ा चौकी में मामला दर्ज कराया गया।

कौशल विकास क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मान

पायनियर समाचार सेवा, गुरुग्राम

रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (आरएसडीसी) ने नई दिल्ली में वार्षिक पुरस्कार 2019 का आयोजन किया, जिसमें रबर सेक्टर में कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया।

पुरस्कार समारोह के दौरान ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) के वाइस चेयरमैन अंशुमन सिंघानिया, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए) के प्रेसिडेंट वीटी चंद्रशेखरन और मानव रचना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सम्मानित अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे। अपने स्वागत संबोधन में आरएसडीसी के चेयरमैन विनोद साइमन ने पिछले सात वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैन्यूफैक्चरिंग एवं प्लांटेशन सेगमेंट समेत पूरे सेक्टर के लिए नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड (एनओएस) तय किए गए हैं। अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सभी राज्यों में रबर सेक्टर में कौशल की कमी (स्किल गैप) को लेकर विश्लेषण किया गया है। आरएसडीसी ने 11 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त 14 राज्य मिशनों के साथ गठजोड़ किया है। आरएसडीसी ने पहली बार रबर टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज (बी.वोक.) पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इस कौशल विकास अभियान के लिए आरएसडीसी के साथ 950 प्रमाणित प्रशिक्षक, 475 असेसर्स और करीब 150 ट्रेनिंग पार्टनर जुड़े हैं। केमिकल और पेट्रो केमिकल सेक्टर भी अब आरएसडीसी के साथ जुड़ गया है।

एटीएमए के वाइस चेयरमैन अंशुमन सिंघानिया ने कहा, पूर्वोत्तर भारत रबर उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है और अगर यहां कुशल कार्यबल उपलब्ध हो तो यह क्षेत्र इस सेक्टर की कमी को पूरा कर सकता है। नेशनल रबर पॉलिसी 2019 में यह बात सामने आई है कि कुशल रबर टैपर्स की कमी है। हमें भरोसा है कि पूर्वोत्तर में कौशल विकास के मुद्दे को आरएसडीसी उसी गंभीरता से ले रहा है, जिसकी आवश्यकता है। एआईआरआईए के प्रेसिडेंट वी.टी. चंद्रशेखरन ने उद्योग जगत से आरएसडीसी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे कौशल विकास के अवसरों का भरपूर लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा उद्यमों, विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर को आरएसडीसी द्वारा प्रशिक्षित किए गए लोगों को अपने कार्यबल में शामिल करना चाहिए। पिछले साल आरएसडीसी ने रबर सेक्टर से जुड़े 10 लाख लोगों को सशक्त बनाने के लिए सामर्थ नाम से परियोजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य टायर सर्विस एंड मेंटेनेंस, प्लांटेशन एवं देश में रबर मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों में काम कर रहे लोगों का कौशल विकास करना है। देश के विभिन्न हिस्सों में सामर्थ प्रोजेक्ट के तहत अब तक प्लांटेशन के क्षेत्र में 50 हजार से ज्यादा, मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों में 20 हजार और टायर फिटर के रूप में 40 हजार से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया है। वार्षिक पुरस्कार 2019 के दौरान बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर का पहला पुरस्कार फोकल स्किल डेवलपमेंट को दिया गया। एचएलएल अकेडमी के वेणुगोपाल एस. और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के पार्थ देबनाथ को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक चुना गया। मर्सर मेटल को बेस्ट असेसमेंट एजेंसी का पुरस्कार दिया गया। मैटेरियल हैंडलिंग में उत्तराखंड के श्रीराम स्किल द्वारा प्रशिक्षित प्रभाती सिकंदर को मैन्यूफैक्चरिंग में बेस्ट ट्रेनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्लांटेशन में बेस्ट ट्रेनी अवार्ड लेटेक्स हार्वेस्ट टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे और त्रिपुरा के रिग्पा सॉल्यूशंस द्वारा प्रशिक्षित संजॉय दास को दिया गया।

सेव द चिल्ड्रन द्वारा पांच राज्यों के लिए निमोनिया रिपोर्ट प्रकाशित

पायनियर समाचार सेवा, गुरुग्राम

भारत में बचपन में होने वाले निमोनिया के खिलाफ प्रभावी प्रयत्नों की शुरुआत के तहत सेव द चिल्ड्रन ने भारत में निमोनिया के परिस्थिति का विश्लेषण रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। रिपोर्ट का विमोचन केंद्रीय मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. अजय खेरा द्वारा दिल्ली में किया गया, जिसमें पांच उच्च भार वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान का गहराई से मूल्यांकन, चुनौतियों के बारे में पहचान और कार्रवाई करने के लिए आह्वान किया गया है।

इस अवसर पर डॉ. अजय खेरा, आयुक्त, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार की योजना लक्ष्य (लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव गाइडलाइन) के बारे में बताया और समझाया किस तरह ये जन्म के समय देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केंद्रित है जिसमें आशा महिला कर्मचारियों को सुसज्जित करना और महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में एकत्रित करना शामिल है। उन्होंने आगे कहा, स्वास्थ्य प्रणाली में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र नए तौर पर जुड़ा है, जो जमीनी तौर पर लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। सरकार ने बचपन में होने वाली मातृत्व से निपटने के लिए वाकई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है और इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सेव द चिल्ड्रन के डायरेक्टर प्रोग्राम्स अनिंदित रॉय चौधरी ने कहा, बच्चों में आज भी निमोनिया मौत का सबसे प्रमुख कारण है और भारत में 5 साल के कम उम्र के बच्चों में इसकी दर 14.3 फीसदी है, जिसका मतलब है प्रत्येक 4 मिनट में एक बच्चे की मौत। पूरे विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निमोनिया से होने वाली मौतों में भारत का आंकड़ा 17 फीसदी है। बचपन में होने वाले निमोनिया की समस्या से निपटना सेव द चिल्ड्रन के शताब्दी वर्ष की तीन प्रतिबद्धताओं में से एक है और हम रोके जा सकने वाली निमोनिया मौतों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये मौजूदा रिपोर्ट जिसका शीर्षक है भारत में साँस के लिए संघर्ष जिसे हम प्रकाशित कर रहे हैं इसी प्रतिबद्धता की ओर बढ़ाया गया कदम है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों से खुलासा होता है कि : 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अध्ययन किए गए 5 राज्यों में कुल मिलाकर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (एआरआई) का प्रचलन दर 13.4 फीसदी रहा। जहां एक ओर बिहार में प्रचलन दर सबसे ज्यादा (18.2 फीसदी) रहा उसके बाद यूपी (15.9 फीसदी), झारखंड (12.8 फीसदी), मध्य प्रदेश (11.6 फीसदी) और वहीं राजस्थान में सबसे कम प्रचलन दर (8.4 फीसदी) दर्ज किया गया।

बचपन में होने वाले निमोनिया के लिए घर में वायु प्रदूषण जोखिम का एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी जैसे सुधारित ईंधन का इस्तेमाल होता है उसका बचावात्मक प्रभाव देखा गया है।

गुरुग्राम का हर गांव होगा आदर्श

गुरुग्राम। विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि गुरुग्राम विधानसभा का हर गांव आदर्श गांव होगा। किसी भी गांव के किसी भी कोने में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमारी मिलेनियम सिटी के गांव भी शहर जैसे हों, इस पर वे काम कर रहे हैं। यह बात उन्होंने गांव सैनी खेड़ा में सीवरेज, पानी व सड़क के कार्यों का शिलान्यास करने के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही।

विधायक सुधीर सिंगला ने अपने भाषण की शुरुआत में विजयी बनाने पर सभी का स्वागत और धन्यवाद किया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय हर मतदाता व कार्यकर्ता को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व के पांच साल में गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में जो विकास के कार्य करवाए हैं, वे मील का पत्थर हैं। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कभी न तो जातीय भेदभाव और न ही क्षेत्रवाद को लेकर कोई काम किया। हरियाणा में दूसरी बात सरकार में बैठी बीजेपी इस बार भी विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने चुनाव के समय में किए गए वायदों पर कहा कि वे एक-एक वायदे पर गंभीरता से काम करते हुए जनता को राहत पहुंचाएंगे। उन्होंने लोगों और कार्यकर्ताओं से अपील की कि विकास कार्यों को लेकर प्रशासन और सरकार का सहयोग करें।

वार्ड-32 की पार्षद आरती यादव की अध्यक्षता में उन्होंने 16500000 रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरे करने की बात कही।

इस मौके पर पूर्व सरपंच सतीश यादव, भाजपा सरस्वती मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह, भूप सिंह, आरडब्लूए प्रेसिडेंट सत्यप्रकाश सैनी, राकेश कुमार, मांगेराम सैनी, हेतराम, पवन कुमार एक्सईएन एमसीजी, संजोग शर्मा एसडीओ एमसीजी, हिमांशु जेई एमसीजी, नरेंद्र सैनी, पवन सैनी, अनिल यादव, अभिषेक गुलाटी महामंत्री भाजपा सरस्वती मंडल, दीपक यादव, पटेल राव, नरेंद्र सैनी, लक्ष्मी नारायण और गांव के काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे।

नवयुक्त एसएचओ ने हटवाया पिनगवां में अतिक्रमण

नूंह। जिले के पिनगवां थाने में कार्यभार संभालते ही एसएचओ चंद्रभान ने पिनगवां में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ पहले दिन ही जंग छेड़ दी। एसएचओ के सख्त रवैये को देखकर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। लोगों ने अपने सामान को इधर-उधर हटाया और आगे से अतिक्रमण ना करने पर पुलिस को भरोसा भी दिया।

नवयुक्त एसएचओ चंद्रभान ने अतिक्रमण कारियों को सख्त तेवर में कहा कि कस्बे में अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग हटवाने के बाद फिर से अतिक्रमण को करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इलाके में किसी भी तरह के अपराध को नहीं होने दिया जाएगा। कस्बे में बिक रहे नशे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बीएम कॉलेज के फार्मेसी विभाग ने मनाया नेशनल फार्मेसी सप्ताह

गुरुग्राम। बीएम कॉलेज के फार्मेसी विभाग ने नेशनल फार्मेसी सप्ताह की शुरुआत की, जो कि हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। जिसमें बहुत से कार्यक्रम और प्रतियोगिता हुई। शुरुआत हुई स्पीच से जिसमें डॉ. संतोष कुमार पांडा ने फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में बताया। टीना भारद्वाज ने परिदृश्य में भूमिका ओर एक नेएदानिक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी पर एक भाषण दिया।

अगले दिन क्विज प्रतियोगिता हुई, जिसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने जीत हासिल की। इसके बाद पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता की गई, जिसमें स्टूडेंट्स ने एक से बढ़कर एक पोस्टर बनाए। रंगोली जैसे अनेक कार्यक्रम हुए, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपना योगदान दिया। सप्ताह के आखिरी दिन पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया, जिसमें मनीष झा और आनंद मुख्य अतिथि रहे।

द्रोण नगरी की 'अर्जुन' गौरिका नेशनल लेवल पर साधेंगी निशाना

संजय कुमार मेहरा, गुरुग्राम

गुरु द्रोण नगरी में द्रोणाचार्य अकादमी में तीरंदाजी के गुर सीखकर कुशल निशानेबाज बनी गौरिका सांगवान ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लड़ाइयों के नाम से मशहूर पानीपत की धरती पर गौरिका ने निशानेबाजी में अपना जलवा दिखाया और पदक पर निशाना साधा।

गुरुग्राम की गौरिका सांगवान ने डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स-2019 चैंपियनशिप (तीरंदाजी के अंडर-19 गर्ल्स) में पहले ही दिन गुरुग्राम की झोली में सफलता मेडल डाला। गौरिका ने तीरंदाजी के रिकर्व राउंड में कांस्य पदक जीतकर जिला का नाम रोशन किया। पूरे देश से अपने-अपने जोन में जीतकर आई डीएवी स्कूलों की अंडर-19 लड़कियों की यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता बुधवार से पानीपत में शुरू हुई, जो कि 30 नवंबर तक चलेगी। इसी प्रकार की लड़कों की प्रतियोगिताएं दिसंबर में हैदराबाद में होंगी। पानीपत में हुई इस प्रतियोगिता में गुरुग्राम के डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-14 की 11वीं कक्षा की छात्रा गौरिका सांगवान ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में सबसे पहले आर्चरी का रिकर्व ग्राउंड का मुकाबला हुआ। जिसमें खिलाड़ी छात्रा गौरिका सांगवान ने कांस्य पदक हासिल कर जिला का नाम रोशन किया। टीम मुकाबलों में दिल्ली-एनसीआर जोन की टीम को स्वर्ण पदक मिला है, जिसकी गौरिका भी एक सदस्य थी। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स 2019 में पहले चार स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) नेशनल में डीएवी संस्था की तरफ से एक टीम के रूप में भाग लेंगे। इस लिहाज से गौरिका भी एसजीएफआई नेशनल स्पोर्ट्स में खेलने जाएंगी, जो संभवत: जनवरी माह में रांची में आयोजित होंगे। गुरुग्राम से खिलाड़ियों के साथ गई खेल प्रशिक्षका मालती के मुताबिक आर्चरी के रिकर्व राउंड में गौरिका सांगवान ने पहले फरीदाबाद में डीएवी जोनल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया था और उसका डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स के लिए दिल्ली एनसीआर की टीम में चयन हुआ था। उस टीम में गुरुग्राम जिला से अकेली गौरिका ही थी, अन्य तीन खिलाड़ी फरीदाबाद तथा नोएडा से थी।

पानीपत में चल रही डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स 2019 तीरंदाजी स्पर्धा में निशाना साधती गुरुग्राम की गौरिका सांगवान (पीली टी-शर्ट में)।

11वीं में नॉन मेडिकल की छात्रा हैं गौरिका

गौरिका पढ़ाई में भी अच्छी है और 11वीं कक्षा में नॉन मेडिकल संकाय की छात्रा है। पढ़ाई का दबाव होने और प्रेक्टिस के लिए कम समय निकाल पाने के बावजूद भी वह तीरंदाजी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खेल प्रशिक्षक मालती ने बताया कि स्कूल की प्राचार्या अपर्णा ऐरी ने भी इस उपलब्धि पर गौरिका को बधाई दी है।

द्रोणाचार्य अकादमी में अभ्यास करती हैं

गौरिका से जब उसके प्रदर्शन के बारे में बात की गई तो उसने कहा कि हालांकि एसजीएफआई नेशनल बड़ा मुकाबला है, लेकिन वह और ज्यादा मेहनत से अभ्यास करके उसमें भी पदक जीतने की कोशिश करेंगी। वह गुरुग्राम के सेक्टर 45 में आर्चरी कोच कपिल कौशिक द्वारा चलाई जा रही द्रोणाचार्य अकादमी में अभ्यास करती हैं। कोच कपिल ने भी उसे इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

एसआरएस : अनिल जिंदल समेत छह पार्टनर दो दिन के पुलिस रिमांड पर

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

आरोपियों को आज फिर से अदालत में किया जाएगा पेश

लोगों को फ्लैट देने के बदले में करोड़ों रुपये वसूलने के बावजूद उन्हें मकान न देने के आरोप में दर्ज एक मामले में एसआरएस के चेयरमैन अनिल जिंदल और उनके पांच अन्य सांझेदारों को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सभी आरोपियों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

अदालत में पेश मामले के मुताबिक देवेंद्र अधाना और अन्य कई लोगों ने वर्ष 2018 में थाना सेक्टर 31 में एफआईआर नंबर 260 दर्ज करवाई थी, जिसमें पीड़ितों ने कहा था कि एसआरएस के चेयरमैन अनिल जिंदल व उनके सहयोगी नानक चंद तायल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, विनोद मामा और विशन बंसल ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने एसआरएस कंपनी द्वारा बनाए जाने फ्लैट लाखों रुपये देकर अपने नाम से बुक करवाए थे। कंपनी द्वारा मांगे जाने पर वे समय समय बाकी का भुगतान भी करते रहे। इस दौरान वे फ्लैट की पूरी कीमत अदा कर चुके हैं। बुकिंग के समय कंपनी ने उन्हें चार साल के भीतर फ्लैट पर कब्जा देने का वायदा किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी पीड़ितों ने कंपनी को करीब 19 करोड़ 71 लाख 10 हजार 375 रुपये का

भुगतान किया था। उन्हें फ्लैट देना तो कंपनी ने धोखाधड़ी से इन फ्लैटों पर एलआईसी से करोड़ों रुपये का लोन ले लिया, जिसके कारण उन्हें आज तक फ्लैटों का कब्जा नहीं मिल पाया है। अपने खून-पसीने की कमाई से भुगतान करने के बावजूद उन्हें बैंक की किश्त और मकान का किराया भरना पड़ रहा है।

अनिल जिंदल समेत अन्य सभी आरोपी अन्य कई मामलों में पहले से ही नीमका जेल में बंद हैं। इस मामले की तारीख पर आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा के जांच अधिकारी ने अदालत में पेश कर सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजने की मांग की। जांच अधिकारी की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष के वकील शेखर आनंद गुप्ता ने पुलिस पूछताछ के दौरान अधिवक्ता की उपस्थिति की मांग की। जिस पर अदालत ने पूछताछ के दौरान दूर बैठकर जांच देखने की अनुमति दे दी। आरोपियों को बृहस्पतिवार को फिर अदालत में पेश किया जाएगा।

एश्लॉन छात्रों को परीक्षा में शामिल कराने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बुधवार को वाईएमसीए के उप कुलपति प्रो. दिनेश शर्मा से मुलाकात करके एश्लॉन इंजीनियरिंग कॉलेज के 480 छात्रों को दिसंबर में होने जा रहे फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल कराने की मांग की है।

उप कुलपति ने मंच को बताया कि एश्लॉन कालेज प्रबंधन ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 में दाखिल हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन वाईएमसीए में नहीं कराया है और न ही एग्जाम फीस जमा कराई है। इसके अलावा कॉलेज प्रबंधक ने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में कॉलेज के खिलाफ याचिका दायर की है। अब जो भी फैसला उच्च न्यायालय का होगा, उस पर ही आगे की कारवाई निर्भर है। फिर भी उन्होंने मंच को आश्वस्त किया है कि वह बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि छात्र दिसंबर में होने वाले प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम में शामिल हों। कैलाश शर्मा ने कहा है कि वाईएमसीए व एश्लॉन कॉलेज प्रबंधक की आपसी खींचतान में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अगर इस खींचतान में छात्रों को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में नहीं शामिल किया गया, तो छात्रों का भविष्य खराब करने को लेकर दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कॉलेज प्रबंधकों से कहा है कि वह उप कुलपति से मिलकर आपसी मनमुटाव को दूर करें और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके छात्रों को एग्जाम में बैठाने की कार्रवाई करें।

गांजे की तस्करी करने के आरोप में एक गिरफ्तार

फरीदाबाद। अपराध शाखा सेक्टर 48 की टीम ने गांजे की तस्करी करने के आरोप गांव खेड़ी गुजरान के नजदीक से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गांजा भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना धौज में दर्ज मामले के मुताबिक अपराध शाखा सेक्टर 48 के एसआई सतवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम को वह पुलिस टीम के साथ इलाके में अपराध पड़ताल गश्त कर रहे थे। मुखबिर ने सूचना देकर बताया कि खेड़ी गुजरान रोड से एक व्यक्ति गांजा लेकर गुजरने वाला है। पुलिस टीम सूचना के बाद अलर्ट हो गई और खेड़ी गुजरान रोड पर चेकिंग शुरू कर दी। तभी उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की, तो वह घबराकर भागने लगा। टीम ने आरोपित को काबू कर उसकी तलाशी लेकर 570 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी की पहचान मथुरा निवासी महेंद्र सिंह के रूप में हुई।

मंदिर के दान पात्र से चोरों ने उड़ाए हजारों

फरीदाबाद। निकटवर्ती गांव नवादा स्थित एक मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर रात के समय मंदिर में घुस आए और दान पेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपये चुरा कर फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना सदर में दर्ज मामले के मुताबिक नवादा गांव के सरपंच बेगराज ने अपनी शिकायत में कहा है कि गांव में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में गांव के अलावा आईएमटी इलाके के लोग भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। मंदिर में दान पेटी भी रखी हुई है। आरोप है कि सोमवार रात को चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे हजारों रुपये निकाल लिए। मंगलवार सुबह जब लोग पूजा करने गए, तो उन्हें पेटी का ताला टूटा मिला। इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई। जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

पर्यावरण बचाने को मानव रचना में हुआ विचार-विमर्श

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

शहर को को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाणा पर्यावरण संरक्षण फाउंडेशन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान धार्मिक संगठनों और आरडब्लयूए के मेंबर्स के साथ मिलकर अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। यहां मौजूद लोगों ने कचरा प्रबंधन, बायोएंजाइम का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक री-यूज करना, सिंगल प्लास्टिक यूज के खत्म करना, कंपोस्ट बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के डीजी डॉ. एनसी वाधवा ने सभी धार्मिक संगठनों से अपील की कि वह एक साथ आकर समाज के लिए कार्य करें ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। उन्होंने कहा, कचरा प्रबंधन आज के समय में बड़ा मुद्दा, घर में अलग-अलग कूड़ेदान बनाना आसान है, लेकिन उसके बाद उसका प्रबंधन करना मुश्किल है। उन्होंने इस दौरान बंधवाड़ी स्थित लैंडफिल का उदाहरण दिया।

सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन गुप्ता ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। कार्यक्रम में सरला, मानव रचना के ट्रस्टी डॉ. एमएम कथूरिया, समन्वय मंदिर से महेश बांगा, एनके गर्ग, आरएसएस अधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

बाटा पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

फरीदाबाद। बाटा फ्लाईओवर के पास झलानी टूल्स की दुकानों पर निगम द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद शरारती तत्वों ने फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया है। इससे अखबार बेचने वाले हॉकरों को परेशानी हो रही है। हॉकरों ने नगर निगम अधिकारियों से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

नगर निगम ने झलानी टूल्स की दुकानों को तोड़ कर प्राईवेट जगह को खाली करवाया था। अब दुकानदारों ने बाटा पुल के नीचे कंटेनर, मुर्गे की दुकान, कुछ कबाड़ी वालों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। बाकी पुल के नीचे ट्रक खड़े होने शुरू हो गए हैं। हॉकरों का कहना है कि एक बुजुर्ग महिला लड़कों के साथ अपना मकान होने के बावजूद पुल के नीचे पूरे एक पिलर के नीचे कबाड़ा एकत्र करके बैठी रहती है। ऑटो आदि से फर्जी पार्किंग बनाकर रुपए वसूलती है। एक्सईएन ओमवीर सिंह का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी। जो भी कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शहर की निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी के बक्सों की चोरी

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक निजी कंपनी द्वारा शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइटें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों अज्ञात चोर इनके लिए शहर में जगह-जगह लगाए गए कैबिनेट बॉक्सों से लाखों रुपये का माल चुरा कर फरार हो गए। कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

थाना सेक्टर आठ में दर्ज मामले के मुताबिक शिशिर सौरभ ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह शहरों में सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइटें लगाने वाली मुंबई की हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है। उनकी कंपनी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यहां भी कैमरे और ट्रैफिक लाइटें लगवाने का काम कर रही है। कैमरों और लाइटों के संचालक के लिए जगह कैबिनेट बॉक्स भी लगाए गए हैं। इन कैबिनेट बॉक्सों में यूपीएस, नेटवर्क स्वीच, बेट्री, एसएमपीएस और अन्य कीमती उपकरण लगे हुए हैं। गत नौ सितंबर की रात इस थाना क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लगे दर्जनों कैबिनेट बॉक्स से अज्ञात चोर लाखों रुपये का सामान चुराकर फरार हो गए। सुबह पता चलते ही उन्होंने मामले की सूचना अपने अधिकारियों की दी। उन्होंने मौके का दौरा करने के बाद पुलिस आयुक्त कार्यालय को शिकायत दे दी थी। लंबी जांच-पड़ताल के बाद अब पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया है।

PUBLIC NOTICE

Notice to Public at large is hereby given under section 32(3) of The Partnership Act 1932 for retirement of Dr. Kamal Kishore Pandey as a Partner from M/S Galaxy Hospital, V-46, Vivek Vihar-1, Delhi-110095 on 30/10/2019 and released from every liability/responsibility with effect from 30/10/2019.
Dr. K.K. Pandey shall not be liable/responsible for any act or deed done or any liability incurred by the partnership firm or the individual Partner of the partnership firm with effect from 30/10/2019.
Dr. Kamal Kishore Pandey
S/o Laxmi Kant Pandey
Varun Trivedi (Advocate)
28/142, West Patel Nagar, New Delhi-08

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Daya Ram, S/o Ramsamujh Yadav, R/o. B-1/137 Gali No.5, New Ashok Nagar, Delhi-110096 have changed my name to Daya Ram Yadav for all purposes.
PD(8672)A

PUBLIC NOTICE

To be known to all that we, S.ANANTHASUBRAMANIAM and AYATHURAI CHAITANYA are the joint mutatees/allottees of DDA BUILT-UP SFS FLAT NO.15B, GROUND FLOOR, CATEGORY-II, SITUATED AT BLOCK-F, MALVIYA NAGAR EXTENSION (SAKET), NEW DELHI-110017, vide DDA's File No. R(710) 78/SFS. Our original Final Demand Letter of the said flat has been misplaced. An Information Report of this effect has been lodged in Police Station, Crime Branch, Delhi vide LR No.1925749/2019 on 25.11.2019.
Any person(s) claiming any right, interest having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above address/phone 8861204301 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write with Proof/Documents of such claim to:
Dy. Director, LAB (H) or Director (H)-1, D-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023. & to the above named persons.

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के डॉक्टरों ने निकाला पांच किलो का ट्यूमर

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने लैप्रोस्कोपिक तकनीक की मदद से 22 वर्षीय युवती के पेट से पांच किग्रा वजन का एक ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला। टीम का नेतृत्व डॉ. बी डी पाठक, निदेशक-जीआई, मिनीमली इनवैसिव एंड बेरियाट्रिक सर्जरी और डॉ. वीएस चौहान, वरिष्ठ सलाहकार-जीआई, मिनीमली इनवैसिव एंड बेरियाट्रिक सर्जरी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, फरीदाबाद ने किया।

मरीज सरिता को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और ठीक से भोजन भी नहीं कर पा रही थी। जब उन्हें अस्पताल लाया गया, तो पेट में परेशानी हो रही थी और सांस लेने में भी तकलीफ थी। जरूरी जांच कराने के बाद उनके पेट में करीब पांच किग्रा का ट्यूमर पाया गया। उपचार के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद डॉक्टरों ने परिवार को एडवांस लैप्रोस्कोपिक एक्सट्रैक्शन कराने की सलाह दी, क्योंकि इसके बाद सर्जरी का कोई निशान भी नहीं रहता और सुधार में लंबा समय भी नहीं लगता है। प्रक्रिया पूरी होने के दो दिनों में मरीज की तबियत में सुधार हो गया और पूरी तरह ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

अस्पताल के जीआई निदेशक डॉ. बीडी पाठक ने कहा, 'इस तरह की सर्जरी के लिए बड़ा कट लगाने की जरूरत होती है, लेकिन यह मरीज बहुत युवा थीं। उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। इसलिए हमने लैप्रोस्कोपिक तकनीक का इस्तेमाल कर छोटे कट के साथ बड़े ट्यूमर को निकाला गया। मुझे खुशी है कि टीम ने यह सफलतापूर्वक किया। इसलिए जब भी ऐसे मरीज आते हैं, तो हम हमेशा ही मरीजों के सर्वश्रेष्ठ संभव सुधार के लिए सर्जरी का सर्वश्रेष्ठ विकल्प तलाशते हैं।'

वाहनों पर होलोग्राम स्टिकर लगाने के आदेश

फरीदाबाद। एसडीएम कम सचिव आरटीए अमित कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुसार सरकार ने एनसीआर में एक अप्रैल, 2019 से पहले पुराने पंजीकृत वाहनों पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टीकर लगाने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छह माह की समय की अवधि के भीतर अपने वाहनों की विंड शील्ड पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टीकर मैसर्ज लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगवाना सुनिश्चित करें।

एसडीएम ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश अनुसार पैट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए नीले रंग की, डीजल वाहनों के लिए संतरी रंग और अन्य सभी वाहनों के लिए ग्रे रंग की पृष्ठभूमि के स्टीकर लगाने के निर्देश दिये गये हैं।

लायंस क्लब ने बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

लायंस क्लब फरीदाबाद नॉर्थ ने बुधवार को 'ड्रीम इंडिया-टू एजुकेटिड इंडिया' के कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब व जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने के जुनून को देखते हुए इन बच्चों को 120 से ज्यादा स्कूली बैग व अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई।

इस मौके पर लायंस क्लब फरीदाबाद नॉर्थ के प्रधान शंकर साइन ने कहा कि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई एक-दूसरे से आगे बढ़ने की जुगाड़ में लगा हुआ है। वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं, जो अपनी भागदौड़ भरी दिनचर्या में से हर रोज कुछ समय निकालकर गरीब व जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क पढ़ाकर समाज को और बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने इसके लिए 'ड्रीम इंडिया-टू एजुकेटिड इंडिया' के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इसी तरह भविष्य में भी जुटे रहने का आह्वान किया।

संस्था ने बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के उद्देश्य से सेक्टर-11 व बल्लभगढ़ में सेंटर खोले हुए हैं, जहां संस्था के करीब 50 वालिंयटर समय-समय पर हर शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ-साथ अन्य गतिविधियां भी कराई जाती है। इस सेंटर में 180 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

PUBLIC NOTICE

To be known to all that **I, Pawan Kumari W/o Gulshan Kumar** R/o **1 A Ground Floor Janta Flat Ashok Vihar Delhi** Allote/GPA/ Purchaser of Flat No. **1 A Ground Floor Janta Flat Ashok Vihar** Category – Janta in the scheme/area of **Ashok Vihar** has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to freehold vide application Dated **19/09/2019** in DDA. The original **Demand cum Allotment Letter Possession Letter NOC Electricity + Water connection Site position Letter** of above said flat has been lost. An FIR on this effect has been lodged in Police Station
Any person{s} claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write contact with above named person at above address/phone no. **Harish 9999402276** within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can inform or write to Dy. Director {Janta} Housing or Director {Housing} – II, D-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, New Delhi – 110023.

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank **शाखा कार्यालय:** आईसीआईसीआई बैंक द्वितीय तल, वीडियोकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110055

जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गमित की थी जिसमें उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे है अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर दाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है एतद् द्वारा विशेष रुप से कर्जदार एवं जनसाधारण को सम्पत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ खाता क्र.	सम्पति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	टेकमैन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड / पलाश रंजन अग्रवाल / विश्व नाथ अग्रवाल / रमेश चंद अग्रवाल / विनोद कुमार अग्रवाल / असीम आनंद अग्रवाल / विभोर अग्रवाल / उसा अग्रवाल / लक्ष्मी अग्रवाल / नमिता जैन अग्रवाल / मीरा अग्रवाल / नीरव नीमेश अग्रवाल/ 072005001203	1. प्लॉट नंबर - 3/1, ग्राउंड फ्लोर कालकाजी एक्सटेंशन नई दिल्ली- 110019/ 26 नवंबर, 2019	अगस्त 31, 2019 ₹. 1,18,34,038/-	दिल्ली

उपरोक्त दर्शाये गये कर्जदार/सह-कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जायेगी जो पूर्णत: नियम 8 और 9 सुरक्षित ब्याज 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक: नवम्बर 28, 2019
स्थान: दिल्ली एनसीआर
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लि.

Chola Enter a better life
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, 'डेयर हाउस' नंबर 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001
शाखा कार्यालय : प्लॉट नंबर 6, द्वितीय तल, मेट्रो पिलर नंबर 81 के सामने, पूसा रोड, करौल बाग, नई दिल्ली-110005

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिसमें/जिनमें निम्नवर्णित कर्जदार(रों) /**सह-कर्जदार**(रों) से सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) /**सह-कर्जदार**(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक** कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदारों का ध्यान प्रत्याभूत आस्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड** की उपरिवर्णित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों) /सह-कर्जदार(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन	मांग सूचना तिथि एवं राशि	सांकेतिक कब्जा की तिथि
1.	(हमारी दिल्ली शाखा का एल सी नंबर **X0HEELD00001718711 & X0HEDES00002245255**) **रामा रानी** (कर्जदार), **रमेश कुमार अग्रवाल, त्रिनेश अग्रवाल, रमेश कुमार अग्रवाल, मैसर्स रामा डिस्ट्रीब्यूटर्स** (सह-कर्जदार) पता : जी-3/39, भू तल, माडल टाउन थर्ड, नई दिल्ली-110009 अन्य पता : ए-80/1, भू तल, आरजीटी करनाल इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110033	सम्पत्ति परिमाप :- सम्पूर्ण अपर ग्राउण्ड फ्लोर के साथ 1/4 छत का अधिकार, सम्पत्ति जी-3/39, एरिया परिमाप 145.44 वर्ग गज, माडल टाउन, दिल्ली-110009	19-09-2019 रू. 1,02,70,803.03/- (रू. एक करोड़ दो लाख सत्तर हजार आठ सौ तीन तथा पैसे तीन मात्र)	26-11-2019

स्थान: दिल्ली + एनसीआर दिनांक: 28-11-2019 हस्ता./-, (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

डीएवी के छात्रों ने किया राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहरों का दौरा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

एनएच तीन स्थित डीएवी शताब्दी कॉलेज के पर्यटन विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर्यटन विभाग के छात्र-छात्राओं को राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को जानना था। इस यात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर जानकारी हासिल की।

कॉलेज प्राचार्य डॉ. सतीश आहूजा ने बताया कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देकर रोजगार के साथ देश के अर्थ व्यवस्था में अहम योगदान दिया जा सकता है और कॉलेज के पर्यटन के विद्यार्थियों को समय-समय पर देश के विभिन्न स्थ्लों की यात्रा करवा कर जानकारी एकत्रित करना मुख्य उदेश्य होता है।

पर्यटन विभाग के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मुकेश बंसल ने बताया कि पर्यटन विभाग के 33 विद्यार्थियों और चार शिक्षकों को राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक, प्राकृतिक व धार्मिक स्थलों को भ्रमण करवा कर परियोजना यात्रा रिपोर्ट तैयार करवाई गयी, जो पर्यटन कोर्स का हिस्सा है।

पर्यटन विभागाद्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि यात्रा के दौरान विद्यार्थियों ने कई गतिविधियां जैसे ट्रैकिंग, सफारी, कैमल-सफारी, डेजर्ट-सफारी का आनंद लिया। आठ दिनी यात्रा में राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों के साथ धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण किया गया। इनमें पुष्कर का ब्रम्हा जी का मंदिर, अजमेर शरीफ दरगाह, माउंट आबू रोड, रामगढ़ जैसलमेर का किला देखकर जरूरी जानकारी जुटाई।

बल्लभगढ़ में राहगीरी का आयोजन एक दिसंबर को

फरीदाबाद। जिला उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने बताया कि आगामी एक दिसंबर को बल्लभगढ़ में राहगीरी का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे ।

जिला उपायुक्त द्विवेदी ने बताया कि एक दिसंबर को राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर दो के अटल पार्क में किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस राहगीरी कार्यक्रम में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ के साथ मनोरंजन प्रोग्रामों का भी आनंद अवश्य ले।

राहगीरी में भंगड़ा, सड़क सुरक्षा, दुर्गा शक्ति एप, योगा, जुम्बा, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित साईकिलिंग आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साईकिलिंग के लिए अपने साथ साईकिल लेकर आये और साइकिलिंग के साथ खेलों का मजा लें। राहगीरी प्रात: 6.30 बजे से नौ बजे तक आयोजित की जाएगी।

सिर्फ सत्ता के लिए महाराष्ट्र में विरोधी विचारधारा वाले दल एक हुए : शाह

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को धता बताकर धुर विरोधी विचारधारा वाले राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए साथ आए हैं।

एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में लोगों ने स्थाई सरकार के लिए मतदान किया और भाजपा व शिवसेना के चुनाव पूर्व गठबंधन को जनादेश मिला। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए नैतिकता और मूल्यों को ताक पर रखा गया। शाह ने कहा, क्या मुख्यमंत्री पद की पेशकश कर समर्थन लेना खरीद-फरोख्त नहीं है। मैं एक बार फिर सोनिया गांधी और शरद पवार से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पद का दावा करें और उसके बाद शिवसेना का समर्थन लें। मंत्री ने कहा कि भाजपा पर खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगता है जबकि नवगठित शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन ने तो मुख्यमंत्री के पद समेत पूरा अस्तबल ही चुरा लिया। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने शिवसेना को मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया था। यहां तक कि चुनावी रैलियों में भी जब आदित्य और उद्धव ठाकरे मंच पर होते थे हमने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने उस समय विरोध क्यों नहीं किया था?

मंत्री ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश के लोग वोटबैंक की ऐसी राजनीति से भ्रमित नहीं होंगे और वे अब भी भाजपा के साथ हैं। उन्होंने कहा, शिवसेना के सभी विधायकों ने हमारे साथ मिलकर चुनाव जीता है। शिवसेना का एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसने नरेंद्र मोदी के कटआउट न लगाए हों। भाजपा उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र में मोदी के जितने बड़े कटआउट लगाए थे, उससे भी बड़े कटआउट शिवसेना के उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र में लगाए थे। क्या देश और महाराष्ट्र के लोग यह नहीं जानते। शाह ने कहा कि लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के बजाय मोदी सरकार की प्रदर्शन आधारित राजनीति को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि लोग अब परिपक्व हो गए हैं और उन्होंने परिवारवाद, धनबल-बाहुबल की राजनीति को खारिज कर दिया है।

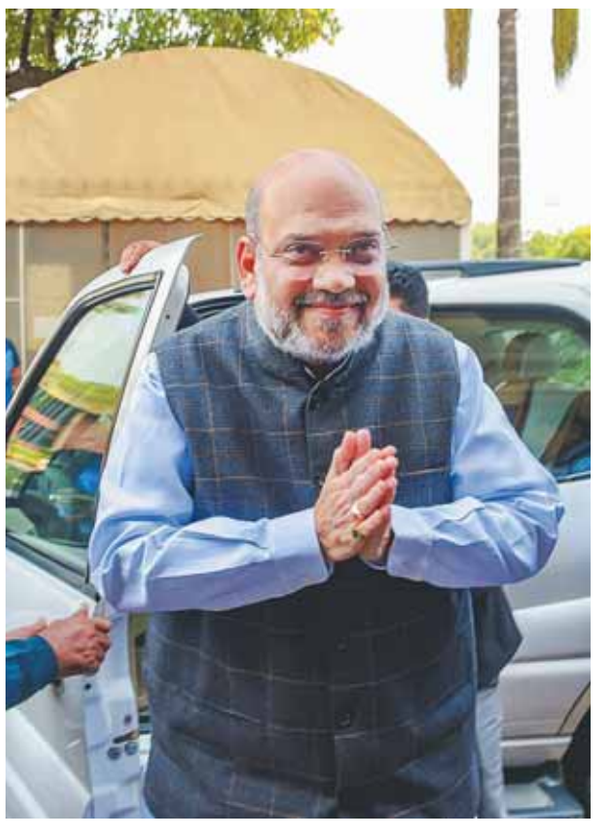

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को नई दिल्ली में चल रहे शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे

गोवा, दादरा नगर हवेली, और दमन दीव की स्वतंत्रता का श्रेय अकेले नेहरू को नहीं दिया जाना चाहिए: शाह

नई दिल्ली (भाषा)। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि दादरा नगर हवेली को 1954 में पुर्तगाली शासन से आजाद कराने में केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं बल्कि बाबासाहब पुरंदरे, संगीतकार सुधीर फड़के, एक सैनिक स्कूल के मेजर प्रभाकर कुलकर्णी आदि युवाओं की भी बड़ी भूमिका थी जिन्होंने जान की बाजी लगाकर इस केंद्रशासित क्षेत्र को मुक्त कराया। लोकसभा में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के प्रावधान वाले एक विधेयक पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय के बयान पर शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासक सालाजार के अधिपत्य में रहे। तब तक उस समय की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद बाबा साहब पुरंदरे, सुधीर फड़के और मेजर प्रभाकर कुलकर्णी जैसे 25 से 30 साल के युवाओं ने आंदोलन चलाया और अपनी जान की बाजी लगाकर दादरा और नगर हवेली को आजाद कराया। उन्होंने कहा कि जब धन की कमी थी तो संगीतकार फड़के ने पुणे में लता मंगेशकर का एक कार्यक्रम कराया और उससे प्राप्त धन से आजादी का आंदोलन चलाया।

मेरे जैसे नेता भाजपा को और सीटें जिता सकते थे : खडसे

मुंबई (भाषा)। भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने बुधवार को कहा कि पार्टी पिछले महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटें और जीत सकती थी अगर वह और कुछ पार्टी नेता चुनाव अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होते। महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 2016 में फडणवीस सरकार से इस्तीफा देने वाले खडसे ने कहा कि उन्हें, चंद्रशेखर बवानकुले, विनोद तावडे और कुछ अन्य नेताओं को जानबूझकर राज्य चुनाव अभियान से अलग रखा गया। यहां विधान भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, इस फैसले की कीमत पार्टी को चुकानी पड़ी। हम लोग और अच्छी तरह चुनाव अभियान में शामिल हो सकते थे और भाजपा को कम से कम 20 से 25 अधिक सीटों पर जीत मिलती। खडसे ने कहा, हमने इस मामले को अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने पहले भी उठाया था। जब यह रेखांकित किया गया कि भाजपा ने पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के पास सबूत होने की बात की थी और हाल में उनके साथ मिलकर सरकार बनाई तब उन्होंने कहा, लगता है कि हमने उसे (सबूतों को) कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को 105 सीटों पर जीत मिली है।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने बुधवार को नई दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की

पांच अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर में 5,000 से अधिक लोगों को ऐहतियातन गिरफ्तार किया गया

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त के बाद से 5,000 से अधिक लोगों को ऐहतियातन गिरफ्तार किया गया और इनमें से 609 लोग अभी भी हिरासत में हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पांच अगस्त से राज्य में पुलिस की गोलीबारी में किसी की मौत नहीं हुई लेकिन कानून व्यवस्था संबंधी घटनाओं में 197 लोग घायल हुए हैं।

गौरतलब है कि विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से हटाते हुए सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था। दोनों केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आ गए हैं। रेड्डी ने बताया शांति भंग न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पांच अगस्त के बाद से कश्मीर घाटी में 5,161 लोगों को ऐहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया। इनमें पथराव करने वाले, असामाजिक तत्व, अलगाववादी और राजनीतिक कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। इनमें से 609 लोग अभी भी हिरासत में हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हिरासत में रह रहे लोगों में से करीब 218 लोग पथराव करने वाले हैं।

हिरासत में लिए गए लोगों में जम्मू कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्री - फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। रेड्डी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं शांति के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने खबर दी है कि घाटी में आवश्यक सेवाएं सामान्य तरीके से काम कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार से मिली सूचना के अनुसार, पांच अगस्त 2019 के बाद से किसी भी व्यक्ति की कानून व्यवस्था की घटनाओं के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मौत नहीं हुई। उन्होंने बताया इस अवधि के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी घटनाओं में 197 व्यक्ति घायल हुए। इसी अवधि में आतंकवाद संबंधी घटनाओं में तीन सुरक्षा कर्मी और 17 नागरिक मारे गए तथा 127 व्यक्ति घायल हुए।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रेड्डी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई दशकों से सीमा पार से मिल रहे समर्थन से चल रहे आतंकवाद एवं अलगाववाद से पीड़ित थे। उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 और कुछ अन्य संवैधानिक प्रावधानों के चलते इस क्षेत्र के लोग भारत के संविधान के तहत प्रदत्त पूर्ण अधिकारों एवं देश के अन्य नागरिकों को मिलने वाले लाभों से वंचित थे। यही वजह थी कि बीते 70 साल से जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र का समुचित आर्थिक विकास भी नहीं हो पाया। रेड्डी ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इन मुद्दों का समाधान हो गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देश के दूसरे हिस्सों के नागरिकों की तरह ही अधिकार एवं लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया।

मंत्री ने कहा हाल ही में लिए गए इन फैसलों की वजह से कुछ ऐहतियाती कदम शुरू में उठाए गए जिनमें बाद में ढील दे दी गई। ए कदम अल्पकालिक थे और इनकी वजह से किसी तरह का नुकसान होने की कोई विशेष रिपोर्ट जम्मू कश्मीर सरकार से नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

श्रीनगर में किराएदारों और घरेलू सहायकों की पृष्ठभूमि की जाँच के आदेश

श्रीनगर (भाषा)। श्रीनगर में अधिकारियों ने पुलिस से कहा है कि आपराधिक गतिविधियों और आतंकी हमलों को रोकने के लिए किराएदारों और घरेलू सहायकों की पृष्ठभूमि की जाँच करनी होगी। श्रीनगर जिलाधिकारी ने हाल ही में जारी किए गए एक आदेश में पुलिस को किराएदारों और घरेलू सहायकों की पृष्ठभूमि की जाँच कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रविरोधी, असामाजिक और आपराधिक तत्वों के किराएदार एवं घरेलू सहायक के रूप में पनाह ले सकने की आशंका है। थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि कि वे शहर के सभी पुलिस थानों में किराएदारों और घरेलू सहायकों का अलग रजिस्टर बनाएं। अधिकारियों ने कहा, यह आदेश श्रीनगर शहर में राष्ट्र विरोधी, असामाजिक और आपराधिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने के मकसद से दिया गया है।

दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय वाला विधेयक लाकसभा से पारित

भाषा। नई दिल्ली

लोकसभा ने बुधवार को दो केंद्रशासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।

निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्षेत्र के जनजाति समुदाय के लोगों के आरक्षण को लेकर सदस्यों की आशंकाओं पर स्पष्ट किया कि संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण वैसे ही मिलता रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि दोनों केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाने का उद्देश्य उनकी प्रशासनिक सुगमता को बढ़ाना तथा विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि एक केंद्रशासित प्रदेश बनने से अधिकारी सप्ताह के पांचों कार्यदिवस पर उपलब्ध होंगे जो अभी दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग अलग दिन उपलब्ध रहते हैं।

रेड्डी ने साफ किया कि लोकसभा सीटों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कांग्रेस के जसवीर सिंह गिल के कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019 को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की।

इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए दोनों केद्रशासित क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों ने केंद्र सरकार से यहां विधानसभा का गठन करने की भी मांग की। दादरा और नागर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन देलकर ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपेक्षा है कि दोनों क्षेत्रों की संस्कृति और परपराओं में बदलाव नहीं होना चाहिए। यहां जनजातीय समुदाय का आरक्षण भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि दोनों केंद्रशासित क्षेत्रों में विधानसभा का गठन होना चाहिए।

दमन और दीव के भाजपा सदस्य लालूभाई पटेल ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए क्षेत्र में दिल्ली और पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के गठन की मांग की। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने दोनों केंद्रशासित क्षेत्रों के विलय की जरूरत पर सवाल किया। चर्चा में केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल (राकांपा), तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और वाईएसआर कांग्रेस के एन रेदेप्पा ने भी भाग लिया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की नीति के तहत दोनों संघ राज्यक्षेत्रों की कम जनसंख्या और सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर विचार करते हुए दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों का एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय करने का निश्चय किया गया और इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें कहा गया है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय के लक्ष्य दक्षता बढ़ाकर और कागजी कार्यों में कमी लाकर दोनों संघ राज्यक्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, प्रशासनिक व्यय में कमी लाना, नीतियों और योजनाओं में एकरूपता लाना, योजनाओं की बेहतर निगरानी करना तथा विभिन्न कर्मचारियों के काडर का बेहतर प्रबंधन करना आदि हैं।

मुम्बई के विधान भवन में बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राकांपा नेता सुप्रिया सुले और अजीत पवार

केंद्र सरकार में 6.83 लाख से अधिक पद खाली

नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 6.83 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार में स्वीकृत पदों की संख्या 38,02,779 है और एक मार्च, 2018 तक 31,18,956 पद भरे हुए थे। इस तरह 6,83,823 पद केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा, खाली पदों को भरने के लिए भर्ती की एक सतत प्रक्रिया है। जब तक किसी विभाग में खाली पदों को भरा जाता है, नए रिक्त पद हो जाते हैं। सिंह ने कहा कि जब कोई पद दो या तीन साल से अधिक समय तक खाली रहता है तो इसे समाप्त माना जाता है।

सोनिया के फैसले पर गौर किया जाना चाहिए: देवगौड़ा

कर्नाटक उपचुनाव

भाषा। बेंगलुरु

पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) के संरक्षक एच डी देवगौड़ा ने पांच दिसंबर को होने वाले कर्नाटक उपचुनाव के संदर्भ में बुधवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले पर गौर किया जाना चाहिए कि वह क्या निर्णय लेती हैं।

देवगौड़ा ने कहा, चुनाव के बाद जो होगा उसके हिसाब से सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जो भी फैसला करेंगी वह कांग्रेस में सबको स्वीकार करना होगा। हमारे (जद-एस) के पास कोई भी सर्वोच्च नेता नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। मैसुरु में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन सरकार रहती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। गठबंधन सरकार गिरने के बाद कांग्रेस और जद(एस) के बीच मतभेद के सवाल पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, क्या आप हमसे (कांग्रेस-जद (एस) से) उम्मीद करते हैं कि (सरकार) के गिरने के तुरंत बाद एक हो जाएं?

भाजपा को बहुमत बरकरार रखने के लिए जिन पंद्रह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से कम से कम छह सीटों पर जीतना जरूरी है। राज्य में 224 विधानसभा सीटें हैं। दूसरी ओर से देवगौड़ा के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या जिले में प्रचार करने के दौरान पत्रकारों से कहा कि उपचुनाव के बाद कर्नाटक में एक स्थिर सरकार होगी लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो सरकार भाजपा की हो। एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा, क्या हमने कहा है कि किस (पार्टी की) सरकार स्थिर होगी, किसने कहा है कि भाजपा सरकार स्थिर होगी? हमने कहा है कि एक स्थिर सरकार होगी। आप यह अनुमान क्यों लगा रहे हैं कि यह भाजपा सरकार होगी?

यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य में फिर से गठबंधन सरकार होगी, इस पर कुमारस्वामी ने कहा नौ दिसंबर के बाद देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा। यह पूछे जाने पर कि क्या उपुचनाव के बाद राजनीतिक बदलाव होगा, इस पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक सफाई होगी और उपचुनाव लड़ रहे अयोग्य ठहराए गए विधायकों का जनता विरोध कर रही है और जनता ने उपचुनाव में उन्हें खारिज करना का फैसला किया है। जद (एस) नेताओं ने संकेत दिया है कि वे मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव के बाद भाजपा के बहुमत खोने की स्थिति में उनकी पार्टी की भूमिका पर नौ दिसंबर के बाद फैसला होगा।

उपचुनाव के नतीजे नौ दिसंबर को आएंगे। दिलचस्प है कि कुमारस्वामी और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने हाल में कहा है कि उनकी पार्टियों का मुख्य लक्ष्य दल-बदलुओं को हराना है, जो अब भाजपा के प्रत्याशी हैं। इस बीच, राजस्व मंत्री आर अशोक ने बुधवार को आरोप लगाया कि हाल तक एक-दूसरे से लड़ रही कांग्रेस-जद(एस) ने उपचुनाव में हार के डर से अंदरूनी समझौता किया है।मंत्री ने कहा, उन्होंने (कांग्रेस-जद(एस)) इस सरकार को गिराने का खाका तैयार किया है लेकिन राज्य के लोग भाजपा के साथ हैं और हम सभी 15 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस जद(एस) ने राज्य में 14 महीने तक गठबंधन सरकार चलाई थी और लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा था। जुलाई में सरकार गिरने के बाद दोनों पार्टियों ने अपने रास्ते अलग-अलग कर लिए हैं। कांग्रेस-जद (एस) सरकार 17 विधायकों की बगावत की वजह से गिरी थी।

चुनाव प्रचार के दौरान रो पड़े कुमारस्वामी

बेंगलुरु (भाषा)। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी बुधवार को केआर पेट विधानसभा सीट पर पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए जद(एस) प्रत्याशी बीएल देवराजू का प्रचार करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने मांड्या जिले के किक्केरी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मांड्या के लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैं कभी भी अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को चुनाव में उतारना नहीं चाहता था लेकिन आपके कहने पर मैंने उसे मैदान में उतारा। उल्लेखनीय है कि निखिल कुमारस्वामी मांड्या से चुनाव हार गए थे।

नल-जल पर बीआईएस मानदंड अनिवार्य करने पर विचार कर रही केंद्र सरकार

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार पाइप के जरिए आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल पर बीआईएस मानदंडों को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है, ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त पानी मिल सके। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस सिलसिले में जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा है।

पेयजल का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा की गई जांच के बीच यह प्रस्ताव आया है। जांच में यह पाया गया था कि मुंबई में जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है लेकिन दिल्ली सहित कई राज्यों की राजधानियों में यह खराब है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा, केंद्र के पास बीआईएस मानदंड (पाइप से आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल पर) को अनिवार्य करने की शक्ति है। हमने इसे अनिवार्य करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।

मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी बल्कि देश भर के लोगों को स्वच्छ एवं गुणवत्ता युक्त पानी सुनिश्चित करना है। हालांकि, उन्होंने बीआईएस मानदंडों के मामले में क्रियान्वयन चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा, यदि राज्य मानदंडों का अनुपालन नहीं करेंगे तो हम जलापूर्ति पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। गौरतलब है कि बीआईएस राष्ट्रीय मानक संस्था है जिसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम 2016 के जरिए की गई थी। इसका उद्देश्य वस्तुओं का मानकीकरण, मार्किंग और गुणवत्ता प्रमाणन को सुनिश्चित करना है।

बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि बीआईएस अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि किसी उत्पाद के लिए तैयार किए गए मानदंडों को अनिवार्य किया जा सकता है। बीआईएस ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को एक मसौदा गुणवत्ता नियंत्रण आर्डर भेजा था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि उत्पाद के तौर पर पेयजल पर मानदंड और समूची आपूर्ति श्रृंखला या नियंत्रण बिंदुओं पर मानक को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए बीआईएस ने दो चरणों में जांच की तथा उसकी योजना और दो चरणों में नमूने एकत्र करने तथा उनकी जांच करने की है। प्रथम चरण में दिल्ली के 11 विभिन्न स्थानों से पेयजल के नमूने एकत्र किए गए थे और दूसरे चरण में 20 राज्यों की राजधानियों के 10 स्थानों से 10 नमूने लिए गए थे। पासवान ने 16 नवंबर को दूसरे चरण का बीआईएस अध्ययन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई पेयजल के लिए 11 गुणवत्ता मानदंडों में 10 में खरे नहीं उतर पाए हैं। तीसरे चरण में पूर्वोत्तर के राज्यों और 100 स्मार्ट शहरों से नमूने लिए गए थे।

क्विक न्यूज

एयर इंडिया के कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी : सरकार

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के निजीकरण होने तक इसके कर्मचारियों के हितो की रक्षा करने का आश्वासन देते हुए कहा है कि इनकी नौकरी नही जाने दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा मे प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब मे कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश मे कर्मचारियो के हित को ध्यान मे रखते हुए ही कोई समझौता किया जाएगा। उन्होने एयर इंडिया मे आर्थिक संकट को देखते हुए वेतन नही मिलने के कारण पायलटो द्वारा नौकरी छोड़ने से जुड़े एक पूरक प्रश्न के जवाब मे कहा कि वित्तीय संकट की बात सही है लेकिन वेतन नही मिलने के कारण किसी पायलट द्वारा नौकरी छोड़ने की जानकारी, मंत्रालय के संज्ञान मे नही आई है। पुरी ने कहा कि एयर इंडिया जब वित्तीय संकट के दौर मे थी तब कुछ कर्मचारियो का 25 प्रतिशत वेतन भुगतान विलंबित था।

देश को हर वर्ष औसतन 100 पायलटों की जरूरत होगी

नई दिल्ली (भाषा)। भारत मे उड्ययन क्षेत्र को हर साल औसतन 100 पायलटो की जरूरत होने का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए देश मे विमान उड़ाने की प्रशिक्षण अकादमियो को उन्नत किया जाएगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा मे प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश मे विमान उड़ाने के 32 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इनमे हर साल लगभग 350 पायलट प्रशिक्षित किए जाते है। इनमे से 23 केन्द्र निजी क्षेत्र के है और शेष नौ केन्द्र विभिन्न राज्य सरकारो और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। पुरी ने कहा, हमे विमानन सेवाओ मे 100 विमानो को शामिल किए जाने के मद्देनजर हमे 700 पायलटो की जरूरत होगी। इसकी पूर्ति के लिए विमानन क्षेत्र को हर साल औसतन 100 पायलटो की जरूरत होगी।

अब आसमान से दुश्मनों पर होगी पैनी नजर

● पृथ्वी की बेहद साफ तस्वीर लेने वाले भारत के कार्टोसैट-3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण

भाषा। श्रीहरिकोटा

इसरो ने पृथ्वी पर नजर रखने वाले और मानचित्रण उपग्रह कार्टोसैट-3 और अमेरिका के 13 व्यावसायिक नैनो उपग्रहों को बुधवार को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है और इसरो प्रमुख के. सिवन ने बुधवार को इसकी सफलता को शानदार बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि अत्याधुनिक कार्टोसैट-3 से चित्र लेने की हमारी उच्च क्षमता और बेहतर होगी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं इसरो की पूरी टीम को पीएसएलवी सी 47 के जरिए स्वदेशी कार्टोसैट-3 और अमेरिका के एक दर्जन से अधिक नैनो उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर हृदय से बधाई देता हूं। इसरो ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। इसके प्रक्षेपण के बाद इसरो की बेंगलुरु स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ने उपग्रह का नियंत्रण संभाल लिया। इससे पहले बादलों के बीच 44.4 मीटर लंबे पीएसएलवी-सी47 रॉकेट ने उपग्रहों को लेकर यहां दूसरे लॉन्च पैड से सुबह नौ बजकर 28 मिनट पर उड़ान भरी।

भारत के अब तक के सबसे जटिल और पृथ्वी की बेहद स्पष्ट तस्वीर लेने वाला उन्नत उपग्रह कार्टोसैट-3 उड़ान भरने के 17 मिनट और 46 सेकंड बाद अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित हो गया। चंद्रयान-2 के बाद इसरो का यह पहला मिशन है।

इसरो ने बताया कि अमेरिका के सभी 13 छोटे उपग्रहों को उड़ान भरने के 26 मिनट और 56 सेकंड बाद कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जैसे ही कार्टोसैट-3 को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया तो इसरो अध्यक्ष के. सिवन और अन्य वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। बाद में अभियान नियंत्रण केंद्र से सिवन ने कहा, मुझे यह एलान करते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है कि पीएसएलवी-सी47 ने कार्टोसैट-3 और 13 ग्राहक उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।

उन्होंने कहा, कार्टोसैट-3 भारत का सर्वाधिक रेजोल्यूशन वाला उपग्रह है और अभी तक बना सबसे जटिल तथा पृथ्वी पर नजर रखने वाला उन्नत उपग्रह है। उन्होंने उपग्रहों पर काम करने वाली टीमों को बधाई दी। सिवन ने ताजा प्रक्षेपण का जिक्र करते हुए कहा, मैं एक बार फिर शानदार सफलता के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई देता हूं।

भविष्य के अभियानों के बारे में इसरो प्रमुख ने कहा, हमारे पास बहुत काम हैं। मार्च 2020 तक 13 मिशन पूरे करने हैं। इनमें छह प्रक्षेपण यान मिशन और सात उपग्रह मिशन शामिल हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) के निदेशक एस सोमनाथ ने भी इसरो की टीम की प्रशंसा की।

कार्टोसैट-3 के डिजाइन को कुछ नया बताते हुए उन्होंने कहा, उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पूरी तरह से नया है। कार्टोसैट-3 का समग्र वजन 1625 किलोग्राम और मिशन पांच वर्ष का है। यह व्यापक पैमाने पर शहरी योजना, ग्रामीण संसाधन और आधारभूत ढांचे का विकास, तटीय भूमि उपयोग आदि की बढ़ती मांगों को पूरा करेगा। पीएसएलवी..सी47 पीएसएलवी की एक्सएल कान्फिग्रेशन में 21वीं उड़ान है।

पीएसएलवी..सी47 अमेरिका से 13 वाणिज्यिक नैनो उपग्रहों को भी लेकर जाएगा। ऐसा अंतरिक्ष विभाग के न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत हो रहा है। इसरो ने कहा है कि यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से 74वां प्रक्षेपण यान मिशन है।

कार्टोसैट-3, कार्टोसैट श्रृंखला का नौवां उपग्रह है और बुधवार का प्रक्षेपण 2019 में इसरो का पांचवां प्रक्षेपण है। इस बीच, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी इसरो की सफलता के लिए उसकी तारीफ की। हैदराबाद में एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया है कि यह प्रतिभा और हमारे वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम की एक और जीत है।

अदालत ने वधावन के दो विमान, नौका को बेचने की मंजूरी दी

मुंबई। महानगर की एक अदालत ने पीएमसी बैंक में आरबीआई की ओर से नियुक्त प्रशासक को एचडीआईएल समूह की कंपनियों से जुड़े दो विमान और एक नौका (यॉट) को बेचने की अनुमति दे दी है। एचडीआईएल समूह के प्रवर्तक राकेश वधावन और उसका बेटा सारंग 4,355 करोड़ रुपए के पंजाब एंड महाराष्ट्र को - ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। मुख्य महानगर मेजिस्ट्रेट आर. के राजभोसले ने सोमवार को दो विमान - फैल्कॉन 2000 (वीटी - एचडीएल) और चैलेंजर 300 (वीटी - पीआईएल)- और एक नौका को बेचने की मंजूरी दी। इस मामले में जांच एजेंसियों की ओर से कुर्क चल संपत्तियों की बिक्री करने का निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वकील रमेश दुबे पाटिल ने अदालत में कहा कि प्रतिबंधों की वजह से जमाकर्ता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राशि से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं।

नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखिरियाल निशंक और फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमेनी फिक्की की रिपोर्ट दिखाते हुए

लिबरल आर्ट्स शिक्षा को भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह महत्व देने की जरूरत : राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि लिबरल आर्ट्स शिक्षा को भी विज्ञान की तरह ही महत्व दिया जाना चाहिए ताकि तकनीक का फल अंततः लोगों, समुदायों और संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक हो। राष्ट्रपति कोविंद ने यह बात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की ओर से आयोजित उच्च शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों के मुताबिक भारत में पाठ्यक्रमों को फिर संयोजित करने की जरूरत है। लिबरल आर्ट्स शिक्षा को विज्ञान की तरह महत्व देना चाहिए ताकि उससे उत्पन्न तकनीक का फल अंततः लोगों, समुदायों और संस्कृतियों के लिए प्रासंगिक बने। हमारे विश्वविद्यालयों ने अंतर्विषयक पद्धति से विकास किया है।

राष्ट्रपति ने कहा, मुझे खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालयों में गणित के साथ संगीत और कृत्रिम बुद्धिमता के साथ पशुपालन के संयुक्त पाठ्यक्रम हैं लेकिन इस मामले में और काम करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बदलाव का आह्वान किया। कल की दुनिया ज्ञान, मशीनी बुद्धिमत्ता और डिजिटल उपायों से चलेगी। हमें इस बदलाव और असीमित संभावनाओं का लाभ लेने के लिए खुद को तैयार करना होगा, हमें उच्च शिक्षा को नए पाठ्यक्रम और गंभीर शोध कार्य के जरिए नया स्वरूप प्रदान करना होगा। हमारे पाठ्यक्रम में विचार, नवोन्मेष और अनुकूलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानव संसाधन कोष है। अगर हम अकादमी-उद्योग के संबध को मजबूत करें तो हमारे अंदर दुनिया की शोध एवं विकास राजधानी बनने की क्षमता है। फिक्की के 15 वें उच्च शिक्षा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2019 बुधवार को यहां विज्ञान भवन में शुरू हुई जिसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हिस्सा लिया। अफ्रीका, मध्य एशिया और एशिया सहित 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

तीन दिवसीय सम्मेलन क्रिएटिव इकनॉमी नेशन बिल्डिंग: हायर एजुकेशन एज द कैटलिस्ट विषय पर केंद्रित होगा। राष्ट्रपति ने कहा, खोजने की भावना, आलोचनात्मक सोच और मामलों को क्या, क्यों और कैसे की निगाह से देखने की पूरी संस्कृति एवं दृष्टिकोण को पोषित किया जाना चाहिए। हमारे छात्रों के दिमाग में आने वाली सृजनात्मकता, कल्पना और विचार को मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे फले-फूले। शिक्षा में यह पुनर्जागरण लाने के लिए हमें रुख में बदलाव करना होगा और कई मोर्चों पर आ रहे विचारों के प्रति खुलापन लाना होगा। राष्ट्रपति ने कहा, उच्च शिक्षा की दुनिया महंगी है। इसके लिए हमें विकसित और सशक्त बनना है। सभी साझेदारों- नीतिनिर्माता, शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्यमियों और अन्य के समर्थन की जरूरत है। हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता को देखते हुए राजकीय संस्थाओं को नेतृत्व करना होगा लेकिन इसके साथ ही निजी क्षेत्र को भी इस राष्ट्रीय प्रयास में अपना योगदान जारी रखना होगा।

जापान, स्लोवेनिया के राजदूतों ने राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपे

नई दिल्ली। जापान और स्लोवेनिया के राजदूतों ने बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में इस बारे में बताया है। इसमें कहा गया कि जापान के राजदूत सतोशी सुजूकी और स्लोवेनिया गणराज्य के राजदूत मरजान केनसेन ने राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपे।

माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज की

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें कथित तौर पर माओवादियों के समर्थन में पर्चे बांटने के कारण गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति ए हरिप्रसाद और न्यायमूर्ति एन अनिल कुमार की खंडपीठ ने टी फजल (24) और ए. सुहैब (20) की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है। अदालत ने यह स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा जमा किए गए सबूत इस बात को साबित करते हैं कि गिरफ्तार किए हुए छात्रों का संपर्क माओवादियों से था। पीठ ने कहा कि यूए(पी) अधिनियम के तहत संबंधित अपराधों की जांच जारी रखने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

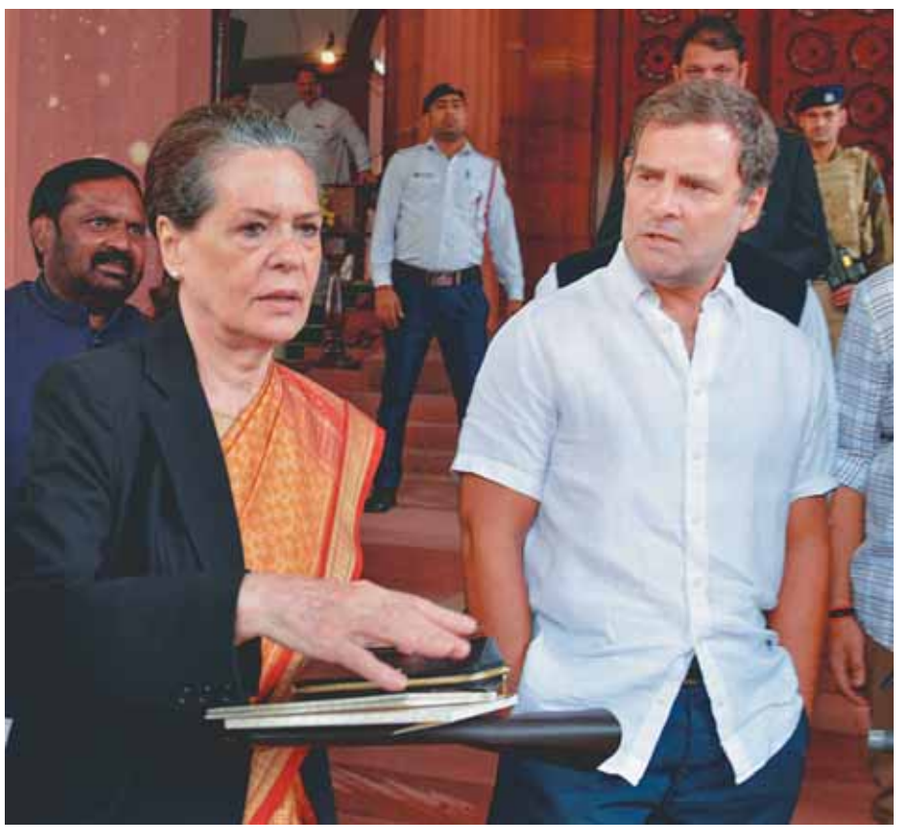

नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया और पार्टी नेता राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र में जाते हुए

370 हटाने के बाद से आतंकी घटनाएं ना के बराबर: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद से आतंकी घटनाएं ना के बराबर हुई हैं और राज्य में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सिंह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना, पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और अन्य बलों के जवान बेहतर समन्वय के साथ कार्वाई कर रहे हैं। कांग्रेस सदस्य के. सुरेश ने शून्यकाल में जम्मू कश्मीर की स्थिति को उठाया और वहां अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी आतंकी हमलों तथा उनमें लोगों के मारे जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।

इस पर जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, जहां तक देश में आतंकी वारदातों की बात है तो सब इस बात को मानेंगे कि पिछले साढ़े पांच साल में जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं घटी। उन्होंने कहा, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो पिछले 30-35 साल से राज्य में आतंकी घटनाएं होती रहीं हैं। सिंह ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आतंकी घटनाएं ना के बराबर हुई हैं। लेकिन यदि कोई आतंकी घटना हुई है तो यह निंदनीय है। सेना, स्थानीय पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और अन्य बलों के जवान पूरी तरह बेहतर समन्वय के साथ मिलकर प्रभावी कार्वाई कर रहे हैं।

जम्मू कश्मीर में पथराव के मामले 40 से 45 प्रतिशत कम हुए : शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों पर पथराव की घटना में 40 से 45 प्रतिशत की कमी आई है। रिपब्लिक टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि प्रावधानों को खत्म करने में 70 साल लग गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे करने का संकल्प लिया। जब तक अनुच्छेद 370 के तहत प्रावधानों को रद्द नहीं किया जाता जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हराना नामुमकिन था। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने क्षेत्र के युवाओं को गुमराह किया, उन्हें हथियार मुहैया कराए और आतंकवाद का प्रचार किया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की कार्वाई से तय होती है और अगर वो शांति चाहते हैं तो उन्हें आतंकवाद खत्म करना होगा। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों की संख्या आज भी उतनी ही है जितनी यह 1990 से रही है।

राजस्थान में इक्कीस और पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता

भाषा। जयपुर

लंबे समय से राजस्थान में रह रहे 21 और पाकिस्तानी विस्थापितों को भारत की औपचारिक नागरिकता प्रदान की गई। इन लोगों को यहां संभागीय आयुक्त के. सी. वर्मा तथा जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने भारत गणराज्य की नागरिकता के प्रमाणपत्र सौंपे। यादव ने बताया कि दो माह में 35 पाकिस्तानी विस्थापितों को भारत की नागरिकता दी गई है। उन्होंने इसे सुखद अनुभव बताया क्योंकि ए लोग पाकिस्तान से विस्थापित होने के बाद वर्षों से यहां अधूरी पहचान के साथ रह रहे थे। उन्हें सरकारी नौकरियों, योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कतें आती थी।

उन्होंने कहा कि अभी नागरिकता संबंधी 28 और आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया में हैं और 63 प्रकरणों की जांच जारी है। इन सभी को भी प्रक्रिया के बाद भारतीय नागरिकता शीघ्र मिल सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।

यादव ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से पाकिस्तानी विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने में जयपुर देशभर में अग्रणी है। राज्य में जयपुर के अलावा जोधपुर व जैसलमेर के जिला कलेक्टर को ही सम्पूर्ण जांच उपरांत पाकिस्तानी विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है।

इस पूरी प्रक्रिया में विस्थापितों को प्रोत्साहित करने वाली संस्था निमित्तकम के जय आहूजा ने बताया कि बुधवार को भारतीय नागरिकता पाने वालों में इंद्रराम, रमेश, मुकेश, सिमित्री, अमिताभ, राजेश कुमार, नंद लाल, कविता, किशोर कुमार, मूली, दिवाना, सुखी, निर्मला बाई, प्रियांषी, विजय, नरेश, भागचंद, सोनिया, सांवल दास, मोना कुमारी व नोमी है।

झारखंड में हर बीपीएल परिवार को रोजगार किसानों के लिए मोबाइल का वादा

भाषा। रांची

केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का जनसंकल्प पत्र (घोषणापत्र) बुधवार को जारी किया। इसमें किसानों को आसान पुनर्भुगतान विकल्प के साथ तीन लाख रुपए तक का ऋण और एक मोबाइल फोन दिए जाने समेत उनके लिए कई कदम उठाए जाने का वादा किया गया है। भगवा पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) प्रत्एक परिवार के एक सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराए जाने का भी वादा किया है। इसमें पिछड़े और गरीब परिवारों से आने वाले स्कूली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया गया है।

मुख्यमंत्री रघुबर दास, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ की उपस्थिति में जारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि नौंवी और दसवीं कक्षा के प्रत्एक छात्र को छात्रवृत्ति के रूप में 2,200 रुपए और 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र को 7,500 रुपए मिलेंगे। भाजपा के संकल्प-पत्र में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम करने, धान के न्यूनतम मूल्य पर दिए जाने वाले डेढ़ सौ रुपए प्रति क्विंटल के बोनस को बढ़ाकर 185 रुपए करने, राज्य को बागवानी का केन्द्र बनाने, 2022 तक ही 70 नए एकलव्य मॉडल स्कूल का काम पूरा करने और जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय संवेदकों को 25 लाख रुपए तक के टेंडर में अर्हता में छूट देकर उनकी भागीदारी बढ़ाने की भी बात की गई है। इसमें राज्य मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत हर वर्ष अधिकतम किसानों को 5 हजार रुपए उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। सभी किसानों को आसान पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ तीन लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।

घोषणा पत्र में कहा गया है कि यदि पार्टी फिर से सत्ता में आई तो कुल 5,000 किसानों को अध्ययन करने और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए विदेशों में भेजा जाएगा। इसमें पूरे राज्य में विदेशी घुसपैठ खत्म करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने की बात कही गई है। घोषणा पत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को 60 वर्ष की आयु के उपरांत पेंशन दी जाएगी। राज्य की हर बेटी को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए हर बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

इसमें कहा गया है कि केन्द्र द्वारा लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास के तहत सभी को पक्के मकान उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पार्टी ने पिछड़े वर्ग को सरकार गठन के तीन माह के भीतर सर्वेक्षण के आधार पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया है। इसमें कहा गया है कि पत्रकारों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। घोषणा पत्र के अनुसार वर्ष 2022 तक साक्षरता दर को 90 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा। पार्टी ने झारखंड आंदोलन के वीरों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रांची में एक स्मारक और संग्रहालय बनाने का भी वादा किया गया है। इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से चुनाव जीतने पर उनकी सरकार जनकल्याण की तमाम योजनाओं के साथ युवाओं के रोजगार के लिए ज्यादा तेजी से काम करेगी।

केरल में 42 वर्षीय महिला की बलात्कार के बाद पीट-पीटकर हत्या

कोच्चि। केरल में असम के प्रवासी मजदूर ने 42 वर्षीय महिला की कथित तौर पर बलात्कार के बाद पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात एक बजे हुई घटना के संबंध में उमर अली (27) को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार एक मजदूर ने आज सुबह शहर में एक होटल के निकट खून में लथपथ नग्न महिला का शव देखा। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने महिला से बलात्कार किया और इसके बाद फावड़े से लगातार उसके चेहरे और सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना पेरुम्बवूर में हुई। महिला कुरुप्पमपाड़ी की निवासी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने नजदीकी इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई थी। हालांकि पुलिस ने दूसरे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान कर ली।

तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ने राज्यपाल पद के औचित्य पर सवाल उठाए

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी ने बुधवार को संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी राज्यपाल पद के रहने के औचित्य पर सवाल उठाया। चटर्जी का बयान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच मंगलवार को विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में नए सिरे से शुरू जुबानी जंग के बाद आया है। पश्चिम बंगाल के संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के पद का पहले महत्व था और अचरज होता है कि संविधान को लागू करने के 70 साल बाद भी क्या इसका औचित्य है। चटर्जी संविधान दिवस पर आयोजित दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन को संबोधित कर रहे थे। लोकतंत्र का अभिप्राय कुछ भी करने का अधिकार नहीं है बल्कि संविधान में मौलिक कर्तव्य भी निहित है।

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे चटर्जी ने कहा कि यह निजी लड़ाई नहीं है बल्कि अधिकारों और संस्थाओं के कर्तव्यों का मामला है। उन्होंने कहा कि राजभवन, राज्यपाल के कार्यालय और आवास पर होने वाला खर्च गत तीन साल में दोगुनी हो गई है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में मंच साझा किया था लेकिन दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन नहीं किया और अपने-अपने भाषणों में एक दूसरे पर हमला किया।

ममता बनर्जी का बेहद सम्मान करता हूं: धनखड़

कोलकाता। तृणमूल सरकार के साथ लगातार जारी वाकयुद्ध के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है और वह शिष्टाचार के संबंध में कोई समझौता नहीं करेंगे। धनखड़ का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले राज्यपाल और बनर्जी ने अभिवादन का आदान-प्रदान नहीं किया था, लेकिन मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान एक दूसरे पर हमला बोला था। भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के 70 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित संविधान दिवस पर आहूत विशेष सत्र के दौरान उनके बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। धनखड़ ने बुधवार को ट्वीट किया, मैंने कभी सम्मान देने में कोई कमी नहीं की, चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री ही क्यों न हों जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से काफी सम्मान करता हूं। आश्चर्य है कि उन्होंने (ममता ने) कोई अपेक्षित कदम नहीं उठाया और मैं चकित रह गया।

फड़नवीस की विदाई

अजित पवार के पालाबदल से बदला माहौल

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का निर्णय करने वाले रांकापा नेता अजित पवार ने सदन में संख्याबल कम होने का अनुमान लगने पर फौरन अपने कदम पीछे खींचे और अपने चाचा तथा कद्दावर नेता शरद पवार के साथ वापस लौट आए। इस प्रकार फडनवीस भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में केवल 72 घंटे पद पर रहे। वे पहले से ही परेशान थे क्योंकि शिवसेना ने उनको मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था तथा गठबंधन से बाहर आ गई थी। कर्नाटक व महाराष्ट्र में चली तोड़फोड़ की राजनीति से यही सबक मिलता है कि अब स्वामिभक्ति बाजार में बिकती है और इसकी कोई सीमित गारंटी भी नहीं है। स्वयं को अलग तरीके की पार्टी बताने वाली भाजपा की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, हालांकि फडनवीस ने दावा किया कि हार्स ट्रेडिंग में विश्वास न होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। अब विपरीत चुनाव नतीजों के बावजूद सत्ता पर कब्जे हेतु प्रयासरत भाजपा को 'आपरेशन कमल' छोड़ देना चाहिए। वह 'वन पार्टी-वन इंडिया' की बात करती है, लेकिन जनता का विश्वास पाना प्रचार से अलग है जिसे चोरी के बजाय लोकतांत्रिक रूप से प्राप्त करना होता है। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि किसी को एक सीमा तक ही हाशिए पर धकेला जा सकता है। शिवसेना के अलग होने तथा विपक्षी कांग्रेस-रांकापा गठबंधन के साथ जाने के बाद भाजपा ने 'मैत्रीपूर्ण'

राष्ट्रपति शासन लागू कर सरकार गठन को अहंकार का मुद्दा बना लिया था। उसने पहले पवार परिवार में मतभेद का लाभ उठाने का प्रयास किया और फिर सारे मानकों को धता बताते हुए तड़के शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल पर दबाव डाला। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 'राजनीति और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है।' राज्यपाल से 30 नवंबर तक विश्वास मत परीक्षण के लिए समय मांगना भी रणनीति का हिस्सा था। यदि भाजपा इतना प्रयास पूर्व सहयोगी को मनाने के लिए करती तो आज उसकी सरकार होती।

भाजपा कह रही है कि तीन परस्पर विरोधी पार्टियों का गठबंधन अस्थिर होगा। लेकिन उसके द्वारा तोड़फोड़ के प्रयासों के कारण आज महाराष्ट्र के सब लोगों की हमदर्दी विपक्ष व खासकर शिवसेना के साथ है। उद्धव ठाकरे को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपना दृष्टिकोण अटल रखा, कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखा जिससे वे किसी के जाल में नहीं फंसे। व्यापक स्वीकार्यता वाली शिवसेना ने कांग्रेस को न केवल वैचारिक सीमा तोड़ने, बल्कि सरकार में शामिल होने के लिए भी तैयार कर लिया। कांग्रेस ने अपने विधि विशेषज्ञों को अदालतों में उतार कर संवैधानिक विकृतियों पर ध्यान केन्द्रित किया। हो सकता है कि इस मामले में उसने अपने हितों का ध्यान भी रखा हो। लेकिन यह राज्य में चौथे स्थान पर पहुंचने वाली पार्टी के लिए जोखिम भरा कदम है। यदि वह सरकार में भागीदारी को अपनी उपस्थिति बढ़ाने तथा विधायकों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहती है तो शायद यह रणनीति कारगर हो। लेकिन पूरे प्रकरण में रांकापा संस्थापक शरद पवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप मे उभर कर सामने आए हैं। सवाल है कि क्या अजित पवार ने उनके इशारे पर ही विद्रोह किया था? इसका उद्देश्य भाजपा को भ्रमित कर चुनाव के पहले रांकापा कार्यकर्ताओं को तोड़ने का बदला लेना हो सकता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या कद्दावर नेता के रूप में पवार सत्ता का केन्द्र अपने पास रखना चाहेंगे? इस प्रकार के सवाल अनेक हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल राज्य में बनने वाली नई सरकार को जनादेश का सम्मान करना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन से निपटने की पहल

दक्षिण एशिया क्षेत्र के अनेक देशों की साझा संस्कृति व समान भौगोलिक आयाम हैं लेकिन वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाने से दूर हैं।

आर के पचौरी
(लेखक जलवायु परिवर्तन अंतरशासकीय समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं)

दुनिया भर में अब मानव-गतिविधियों से पैदा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसमें सरकारों, बिजनेसों, सिविल सोसाइटी तथा आम जनता की सहभागिता शामिल है। 2011 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति-आईपीसी ने एक विशेष रिपोर्ट जारी की थी जिसका संबंध जलवायु परिवर्तन के कारण आत्यन्तिक घटनाओं के जोखिम से निपटना शामिल था। इसने जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया। इसके बाद जनता ने जलवायु परिवर्तन का खतरा समझा जिसके कारण सारी दुनिया में मौसम खराब होने की घटनाओं की गंभीरता व बारंबारता बढ़ी। राष्ट्रीय सरकारों की पेरिस समझौते के अनुसार ज्यादा जिम्मेदारी है, पर क्षेत्रीय पहलें भी जरूरी हो गई हैं।

निसंदेह ग्रीनहाउस गैस-जीएचजी व खासकर कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन रोकने के प्रयास होने चाहिए। लेकिन भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और खतरों के बारे में सारी चीजें अभी ठीक से नहीं समझी गई हैं। पोप फ्रांसिस ने 'जीवधारियों की देखभाल में विश्व प्रार्थना दिवस' पर संदेश देते हुए कहा है कि 'यह मौसम हमें अपनी जीवनशैली तथा भोजन, उपभोग, परिवहन, पानी के प्रयोग, ऊर्जा व अनेक अन्य भौतिक वस्तुओं पर विचार के लिए उपयुक्त है जो अक्सर विचारहीन व हानिकारक हो सकती हैं। हममें से बहुत से लोग जीवधारियों के प्रति अत्याचारियों के रूप में काम करते हैं।'

दुर्भाग्य से पूरी दुनिया में जीवनशैली अत्यधिक उपभोक्तावाद तथा ज्यादा से ज्यादा कचरा पैदा करने की ओर बढ़ रही है। यह बात विकसित व विकासशील देशों, दोनों के लिए सही है। अनेक समाज अपनी ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जड़ों को अनदेखा करते हुए आंख बंद कर ऐसी जीवनशैलियां स्वीकार कर रहे हैं जिनको विकसित देशों, खासकर अमेरिका ने स्थापित किया है। ऐसे में समाजों को अपने भीतर झांक कर देखने तथा अपनी संस्कृति के अनुकूल जीवनशैली अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप समान समस्याओं का सामना करने वाले देशों के साथ सहयोग के नए अवसर खुले हैं।

प्रकृति भौगोलिक बाधायें नहीं स्वीकार करती है। लेकिन अनेक देश जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए समान लक्ष्य देखने तथा एकसाथ काम करने में विफल रहते हैं। दक्षिण एशिया एक ऐसा ही क्षेत्र है जो गरीबी की अनदेखी से पैदा यथार्थ नहीं देख रहा है, जबकि इसके कारण जलवायु परिवर्तन का संकट और गंभीर हो जाता है।

आईपीसी ने अपनी पांचवीं आंकलन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा था कि 'जलवायु परिवर्तन प्रकृति तथा मानव व्यवस्थाओं के लिए वर्तमान खतरों के साथ नए खतरे भी पैदा कर रहा है। इन खतरों का वितरण असमान है तथा आमतौर से यह विकास के सभी स्तरों पर वंचित लोगों व समुदायों के लिए और गंभीर हो जाता है।' इसमें यह भी कहा गया था कि जलवायु परिवर्तन से लोगो के विस्थापन का खतरा बढ़ा है तथा कुछ लोग 'मौसम में आत्यन्तिक परिवर्तनों के कारण नुकसान का सामना करेंगे। विकासशील देशों तथा गरीब लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।' इसके साथ ही गरीबी व आर्थिक झटकों के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण हिंसक टकरावों का खतरा भी बढ़ जाता है।

दक्षिण एशिया में साझा संस्कृति और इतिहास है तथा वह जलवायु परिवर्तन के खतरों की अत्यधिक आशंका वाला क्षेत्र है। यदि हम अफगानिस्तान से भारत के दक्षिणी छोर तक भूमि पर गौर करें तथा श्रीलंका व मालदीव को इससे बाहर रखें तो यह लगभग 1.75 बिलियन लोगों की भूमि है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय प्रभावों में तेजी से वृद्धि हुई है। पता चला है कि तापमान में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर गेंहूं की उत्पादकता पर सात प्रतिशत प्रभाव पड़ सकता है, जबकि 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने पर यह 24 प्रतिशत हो सकती है। दक्षिण एशिया मौसम में आत्यन्तिक परिवर्तनों का शिकार है जिनकी बारंबारता व गंभीरता बढ़ती जा रही है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका व गरीबी पर प्रभाव पड़ सकता है।

आईपीसीसी ने लू चलने, भारी बरसात, बाढ़ व सूखे की घटनाओं में वृद्धि का अनुमान लगाया था। इनमें से कुछ के कारण दस्तरोग, डेंगू व मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में जल की अधिकांश सप्लाई करने वाले मानसून में परिवर्तन के कारण अत्यधिक या बहुत कम बरसात जैसी घटनायें हो सकती हैं। इनके कारण वर्षा-आधारित तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। दक्षिण एशिया में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निचले स्तर के समुद्र तटीय क्षेत्रों व बाढ़ वाले मैदानों में रहता है। समुद्र जल स्तर में वृद्धि से यह संकट का शिकार हो सकती है।

चूंकि श्रीलंका और मालदीव जैसे द्वीप देशों को दक्षिण एशिया की मुख्यभूमि की तुलना में अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वर्तमान समय में हमें उनके लिए अलग प्रयासों व पहलों की आवश्यकता है। लेकिन अभी दक्षिण एशिया में समान सरोकार के मुद्दों पर सहयोग की भावना मोटेतौर से गायब है। इस क्षेत्र में जनसंख्या के अधिक घनत्व को देखते हुए बड़ी संख्या में मनुष्यों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पड़ेंगे जो दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक होंगे।

दक्षिण एशिया आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित है जिसे कुछ देशों ने सरकारी नीति के रूप में बढ़ावा दिया है। यह स्पष्ट है कि आतंकवाद को पैदा करने और उसका समर्थन करने वाले देशों पर भी इसका गंभीर व दीर्घकालीन खतरा मौजूद है। यदि वे अपनी जनता के कल्याण के प्रति गंभीर हों तो उनको आतंकवाद छोड़ना होगा।

दुर्भाग्य से क्षेत्र के कुछ देशों के बीच गंभीर राजनीतिक मतभेद हैं, पर जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौतियों को देखते हुए उनको सबके हित में परस्पर लाभदायक गतिविधियों के माध्यम से शत्रुतापूर्ण व विवादास्पद मुद्दों से ऊपर उठना होगा। इस प्रकार की पहल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल व पाकिस्तान में लागत-प्रभावी उपायों की आवश्यकता होगी।

विकासशील देशों के वार्ताकार कई साल से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन-यूएनएफसीसी में 'साझा पर अलग-अलग जिम्मेदारियों' पर काम कर रहे हैं। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से जीएचजी का उच्च स्तर पर उत्सर्जन करने वाले देशों को विकासशील देशों की तुलना में इनको घटाने के ज्यादा प्रयास करने होंगे।

विकसित देशों को तार्किक रूप से ज्यादा वित्तीय संसाधन विकासशील देशों को देने चाहिए ताकि वे जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्रवाई को मजबूत कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से इन मांगों के पीछे छिपे सिद्धान्तों को विकसित देशों ने भुला दिया है। दक्षिण एशिया के देशों को सामूहिक रूप से उन परियोजनाओं के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए जिनका वित्तपोषण औद्योगिक देशों को करना है।

दक्षिण एशिया में पवन ऊर्जा प्रयोग की संभावनायें असाधारण हैं और वह इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सीमाओं के पार वैज्ञानिक व आर्थिक रूप से सहयोग कर सकता है। क्या दक्षिण एशिया के नेता वर्तमान तनावों और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ कर अपनी वंचित जनसंख्या के हित में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर काम करेंगे जो लगातार गंभीर होते जा रहे हैं? शायद एक शुरुआत के रूप में इस विषय को हाल ही में स्थापित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में शोध एवं एडवोकेसी के तौर पर लिया जा सकता है।

छात्र सक्रियता से भयभीत होने के कारण

नदीम पार्चा
(लेखक एक स्तम्भकार हैं)

अक्टूबर में, बलूचिस्तान विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। यद्यपि विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ छात्रों का कथित रूप से उत्पीड़न किए जाने के विरुद्ध आयोजित किए गए थे, छात्र संघों का नवीनीकरण भी मांगों में शामिल हो गया है। हाल ही में, पंजाब और सिंध में विविध युवा एक्टिविस्टों ने ऐसी ही मांग उठाई हैं, साथ ही 20 नवंबर को एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने की योजना है।

सिंध में सत्ताधारी दल, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने छात्र संघों को बहाल किए जाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और उसे 5 नवंबर को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया। छात्र संघों पर फरवरी 1984 में तत्कालीन तानाशाह जनरल जियाउल हक के अधीन मार्शल ला के आदेशों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2009 में लिखी अपनी पुस्तक, 'रिविजिटिंग स्टूडेंट् पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान', में इकबाल हैदर बट ने कई पूर्व छात्र नेताओं का साक्षात्कार लिया था, जिनमें से अधिकतर सफल राजनेता एवं पत्रकार बन चुके थे। लगभग उनमें से सभी ने दु:ख व्यक्त किया कि 1984 में लगे प्रतिबंध ने राजनीतिक नेतृत्व एवं सहभागिता की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियां की लगभग दो पीढ़ियां इस ज्ञान से अछूती रह गईं कि लोकतंत्र ने कैसे काम किया और वह किसके पक्ष में खड़ा हुआ जब चुनावी प्रचार, चुनावों में सहभागिता एवं छात्र संघों के माध्यम से बेहतर अकादमिक एवं मनोरंजन की सुविधाओं पर विमर्श गैरकानूनी करार दे दिए गए। इस प्रकार, सामान्य रूप से कहें तो, जो लोग इस संदर्भ में छात्र संघों की बहाली की मांग कर रहे हैं, उनके पास संतोषजनक आधार है जिस पर कुछ बाध्यकारी प्रमाण के साथ बहस की जा सकती है। हालांकि, यह समान रूप से समझना महत्वपूर्ण है कि छात्र राजनीति की प्रकृति जो 1984 में प्रतिबंध के रूप में परिणित हुई वह अधिकतर शीत युद्ध काल की प्रघटना है। इसे आज के बदले हुए परिदृष्य में मूल रूप से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग भूल गए हैं कि 1989 में बेनजीर भुट्टो सरकार द्वारा प्रतिबंध हटा लिया गया था। लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि छात्र संघों के चुनाव पंजाब के बहुत से राज्य स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों में सफलतापूर्वक आयोजित हुए थे, मगर यह उद्यम जल्द ही स्वयं विफल हो गया।

छात्र समूहों के बीच हिंसा 1980 के दशक में आम बात हो गई थी। और जब वह 1989 में छात्र संघों के पुनरुत्थान के बाद पुन: भड़क उठी, 1992 में इस बहाली के खिलाफ एक याचिका दायर की गई जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया

और 1993 में विद्यालय परिसरों में सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। लेकिन जबकि 1984 के प्रतिबंध के खिलाफ छात्र समूहों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए गए थे, 1993 में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। इसके पीछे कारणों में से एक था छात्र राजनीतिक के पारम्परिक स्वरूप का क्षरण होना। यह क्षरण अधिकतर इस नए यथार्थ के कारण प्रारम्भ हुआ, जिसमें युवा लोग निजी स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों में जाना पसंद करने लगे जबकि देश की अधिकतर पारम्परिक छात्र राजनीति राज्य स्वामित्व वाली शिक्षण संस्थाओं में केंद्रित थी।

जो लोग छात्र संघों पर प्रतिबंध के खिलाफ थे उनकी दलील थी कि 80 के दशक में जो हिंसा परिसर राजनीति में व्याप्त हो गई थी, वह मुख्यत: जिया की तानाशाही के कारण थी और 1984 के बाद छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के कारण फैली थी। हालांकि, अदालत ने टिप्पणी की कि 1989 में छात्र संघों की बहाली हिंसा रोकने में विफल रही थी और नियंत्रण के लिए परिसरों में सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। निश्चित रूप से, 2000 के दशक के पूर्वार्द्ध से, हिंसा कम हो गई। लेकिन, पुन:, कारण केवल छात्र संघों पर प्रतिबंध अथवा उनकी बहाली के बजाए कहीं ज्यादा जटिल किस्म का था। निजी स्वामित्व वाले गैर राजनीतिक कालेजों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई और राज्य शासित विद्यालय स्वयं की छाया मात्र रह गए। छात्र संघ की स्मृतियों में केवल हिंसा की बात ने संपूर्ण रूप से इस तथ्य को नकार दिया कि 1970 के दशक के उत्तरार्ध तक, यह परिसरों में एक ऊर्जावान लोकतंत्र का आधार रहा था।

परम्परागत छात्र राजनीति के क्षरण का अन्य कारण था मुध्यधारा राजनीतिक दलों की रुचि धीरे-धीरे कम होना, जिसने अधिसंख्य छात्र संगठनों की स्थापना की थी। परम्परागत छात्र राजनीति के पतन के साथ, दलों ने अपने छात्र समूहों का इस्तेमाल परिसरों में उनके चुनावी विस्तार के बजाए सहयोगियों के तौर पर रैलियों में प्रदर्शन के लिए करना प्रारम्भ कर दिया। तथ्य है कि पाकिस्तान में छात्र राजनीति का पतन एक सार्वभौमिक रुझान का हिस्सा था। 1960 के दशक में छात्र राजनीति व सक्रियता दुनिया में सर्वोच्च स्तर पर थी, लेकिन 1970 के दशक मध्य से इसमें गिरावट आने लगी। माइकल बरलैग, ने ब्लड एंड रेज, में लिखा था कि 1960 के दशक में छात्र सक्रियता बढ़ने का कारण बड़ी संख्या में मध्यवर्गीय पुरुषों व महिलाओं का कालेजों व विश्वविद्यालयों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रवेश लेना था।

बरलैग के अनुसार, हालांकि, अधिकांश यूरोपीय देशों, अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका के उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों ने 60 के दशक में किसी न किसी प्रकार की आर्थिक प्रगति की, मगर उनके कालेज व विश्वविद्यालय इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का बोझ संभालने में सक्षम नहीं थे। इसके कारण अनेक प्रशासनिक व प्रचालन तंत्र संबंधी समस्याएं पैदा हुईं जिनसे छात्र निराश व आक्रोशित हुए। बरलैग लिखते हैं कि, बहुत से छात्रों ने यह गुस्सा मुख्यत: वामपंथ की चरमपंथी राजनीतिक विचारधाराओं के माध्यम से निकाला। 70 के दशक में वाम झुकाव वाले विचारों से धीरे-धीरे निराशा पैदा होने के साथ ही दक्षिणपंथी झुकाव भी बढ़ने लगा। इसके साथ ही, शिक्षण संस्थानों की स्थितियां भी सुधरीं तथा तीसरी दुनिया के देशों में निजी कालेजों व विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़र। इस प्रकार, 20वीं सदी की परम्परागत छात्र राजनीति निरर्थक हो गई। लेकिन, इसके बावजूद पाकिस्तान में 2007 से तथा अनेक अन्य देशों में नौजवानों में बेचैनी की नई लहर दिख रही है। इसकी व्याख्या सरकारों व शिक्षण संस्थाओं में समस्याओं को दूर न करना तथा नई पीढ़ी की बदलती सामाजिक-राजनीतिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन, संगठित छात्र राजनीति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने वालों को नए किस्म की रणनीतियां अपनानी होंगी तथा पुराने पड़ चुके माडलों के स्थान पर नए मॉडल तैयार करने होंगे। नवीनता के संदर्भ चाहे जो हों, हमें मुख्यधारा के सत्ता केंद्रों पर ध्यान देना होगा। अनेक निरर्थक शब्दों का ऐसे में कोई अर्थ नहीं है जो वाम से दक्षिण की ओर सोशल मीडिया में चला जा रहे हैं। इन शब्दों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व अनिवार्य मुद्दों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वे केवल चरमपंथ को बौना बनाकर पेश करने की चालें हैं। इसलिए, इस संदर्भ में पहला कदम शोर मचाने के बजाए गंभीर विचार विमर्श होना चाहिए।

आप की बात

विचारणीय प्रश्न

अदालत के समक्ष मुख्य तर्क यह दिया जा रहा है कि सभी कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून समाप्त कर दिए जाएं। यह तर्क पूर्णत: उचित है और हम इससे सहमत हैं। लेकिन आंकड़ों से इस अधिनियम के उचित व कठोर प्राविधानों का व्यापक दुरुपयोग उन लोगों के खिलाफ सिद्ध होता है जो 'जाति' के आधार पर साथी नागरिकों का अपमान या किसी प्रकार व किसी रूप में उनका उत्पीड़न करने की हिम्मत करते हैं। जब देश का सर्वोच्च न्यायालय समुचित विचार-विमर्श के बाद कानून के व्यापक दुरुपयोग वाले कुछ प्राविधानों में परिवर्तन का प्रयास करता है तथा ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समाज के लोगों को घृणा से संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है जिसे कानून में अपराध माना गया है तब सभी राजनीतिक पार्टियों व हित समूहों को अपने भीतर झांकना चाहिए। लेकिन यह बात भी पूरी तरह समझ में आती है कि हम जिस छिद्रान्वेषण वाले समय में रह रहे हैं और जहां चुनावी राजनीति हावी रहती है, ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी समझदारी की बात नहीं सुनेगी क्योंकि वोट से बढ़कर कुछ नहीं होता।

– **अजित सेठ**, कानपुर

कृषि क्षेत्र अब भी महत्वपूर्ण

हालांकि अब भारत 'कृषि अर्थव्यवस्था' नहीं है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान केवल लगभग 17 प्रतिशत है, पर आजीविका के लिए 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं। सरकार किसानों और उपभोक्ताओं के हितों में सामंजस्य स्थापित करने तथा खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए अनाजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी निर्धारित करती है जिसका विस्तार कर अब 23 वस्तुओं को उसके दायरे में लाया गया है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को उचित दाम पर खाद्य पदार्थ दिलाने के लिए वह खाद्य वस्तुओं का आयात करती है या उनके निर्यात को प्रतिबंधित करती है। भारत हर साल 1,50,000 करोड़ के कृषि उत्पाद आयात करता है जिसमें गेंहूं, चावल व चीनी शामिल है जिनका देश में काफी उत्पादन होता है, जबकि देश का कृषि बजट केवल 40,000 करोड़ है। इसका भारी प्रभाव किसानों की आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए बगैर देश में विकास वास्तविक एवं संतुलित रूप में होना संभव नहीं है। अत: किसानों पर विशेष ध्यान दिए बगैर व कृषिक विकास के बगैर कोई भी सरकार देश के विकास का दावा नहीं कर सकती।

– **सुरेंद्र शर्मा**, सीतापुर

बैंकिंग प्रणाली में विश्वास

सरकार द्वारा 'जन धन योजना' जैसी योजनाओं द्वारा बैंक खाते खोलने को प्रोत्साहन के बावजूद अनेक गरीब लोगों का अब भी बैंकिंग व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। इसका कारण विभिन्न घोटालों के बजाय बैंक कर्मचारी हैं जो छोटे खाताधारकों से ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, चाहे वे सरकारी बैंकों में हो या निजी बैंकों में। निश्चित रूप से नीरव मोदी द्वारा जनता का पैसा हड़पने जैसे लगातार हो रहे घोटालों के कारण दुष्प्रचार करना आसान हो गया है जिससे बैंकों को नुकसान होता है। मीडिया से सरकार के बहुत अच्छे संबंध न होने के कारण ऐसा दुष्प्रचार और तेजी से फैलता है। निश्चित रूप से यह अमीरों के लिए चिन्ता का विषय नहीं है, पर गरीबों की स्थिति और खराब होती है तथा नकदी का भंडारण शुरू हो जाता है। सरकार ने काफी देर में कदम उठाते हुए जनता को आश्वस्त किया कि चीजें उतनी खराब नहीं हैं जितना कहा जाता है, लेकिन बार-बार लगता है कि यह सरकार आग लगने पर ही उसे बुझाती है। विश्वास जगाने के लिए प्रशासन को सक्रिय होना होगा।

– **विशाल सिंह**, बाराबंकी

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

फरमाया

अमरावती को राजधानी कैसे कहा जा सकता है, जब वहां केवल पांच प्रतिशत काम हुआ है? नायडू ने इसे कब्रिस्तान बना दिया है।

– **बोट्सा सत्यनारायण**
आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री

यदि आप राजधानी का सम्मान नहीं करते तो कम से कम उन किसानों का सम्मान करें जिन्होंने इसके लिए अपनी जमीनें दी हैं।

– **चंद्रबाबू नायडू**
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री

सबको वैचारिक मतभेदों के बावजूद संवैधानिक नैतिकता तथा संविधान निर्देशित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

– **राम नाथ कोविंद**
राष्ट्रपति

रोडवेज की पहल से दिव्यांगजनों को मिलेगा रोजगार: कटारिया

परिवहन मंत्री ने कैसरबाग बस स्टेशन पर की प्रदेश के पहले 'दिव्यांग स्टॉल' की शुरुआत

● समाज के अंतिम व्यक्ति को कामकाज मिले यही सरकार की मंशा: स्वतंत्र देव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रसूताओं को बस स्टेशन परिसर में 'मदर फीडिंग स्टेशन' की शुरुआत के बाद अब दिव्यांगों के लिए भी विशेष स्टॉल खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेश के अलग-अलग बस स्टेशनों पर इस तरह के 200 स्टॉल खोले जाएंगे। दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश के पहले दिव्यांग अनुकूल स्टॉल की शुरुआत बुधवार को परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कैसरबाग बस स्टेशन परिसर में की। वहीं छह दिसंबर को आलमबाग बस स्टेशन परिसर में भी एक स्टॉल खोल जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इन स्टॉलों को खोले जाने के पीछे यही मंशा है कि दिव्यांगजनों को बस स्टेशनों पर जीविकोपार्जन की ऐसी व्यवस्था मुहैया कराकर उन्हें रोजगारोन्मुख किया जाए। कैसरबाग बस स्टेशन पर ऐसे स्टॉल की चाभी दिव्यांग महिला संचालक पिंकी राजपूत को सौंपते हुए परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया ने कहा कि निश्चित तौर पर यह दिव्यांगों के लिये शुरू की गई बेहतर व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि रोडवेज द्वारा की गई इस पहल से दिव्यांगजन आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार की यही मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को कामकाज मिले ताकि वो हर तरह से सशक्त बन सके। वहीं दिव्यांग खानपान स्टॉल शुरू किये जाने की योजना के बारे में रोडवेज के प्रबंध निदेशक डा. राजशेखर ने बताया कि आगामी दिनों में विभिन्न बस स्टेशनों पर जो 200 स्टाल शुरू किए जाएंगे उसमें से 25 फीसदी स्टॉल उन निगम कर्मियों के लिए आरक्षित रहेगा जो बस संचालन के दौरान दुर्घटनावश घायल या निशक्त हो गए हैं। इस बाद बचे हुए स्टॉलों में से 50 फीसदी स्टॉल दिव्यांग पुरूष व दिव्यांग महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। यह स्टॉल जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी व सम्बंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा बहुत ही न्यूनतम दरों को दिव्यांगो को आवंटित किया जाएगा। इन स्टॉलों की शुरूआत कराने में 'दिव्यांग एक उम्मीद' संस्था का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संस्थान से जुड़े और आईआईटी रूड़की के छात्र रहे विकास गुप्ता ने यूपी रोडवेज के प्रबंध निदेशक डा. राजशेखर के साथ इस मामले को लेकर चर्चा की। जिसके बाद एमडी की पहल पर इन दिव्यांग स्टॉलों को खोले जाने की शुरूआत कराई गई है। इन स्टॉलों से खानपान के साथ ही दिव्यांग अनुकूल अन्य वस्तुओं की बिक्री भी की जाएगी।

डीएनए उपकरण की खरीद में न बरती जाए कोई लापरवाही:अवनीश

● अपर मुख्य सचिव गृह ने की बैठक, डीएनए आगरा के लिए किए गए टेंडर को निरस्त करने के दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए उपकरणों की खरीद फरोख्त के संबंध में बैठक की। उन्होंने डीएनए उपकरणों की सप्लाई के लिए एक्सपर्टों की बैठक बुलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

3 दिसम्बर 2019 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक्सपर्टों के साथ यह बैठक की जायेगी। उन्होंने कहा कि डीएनए उपकरणों को अधिक से अधिक जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाए। जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जा सकने वाले उपकरणों की सूची विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों से मांगी गयी है। अवस्थी ने कहा कि इस सम्बन्ध में सीईओ जेम पोर्टल से पत्राचार कर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव को बताया गया कि डीएनए वाराणसी के लिए किये गए टेण्डर को अनियमितता की शिकायत पर यूपी इलेक्ट्रानिक्स द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि टेण्डर निरस्त होने के बाद चयनित फर्म मेसर्स पीएस ग्लोबल के द्वारा प्रयोगशाला मे रखे उपकरणों को 10 दिसम्बर 2019 तक हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगरा डीएनए के लिए किये गए टेण्डर फर्म मेसर्स पीएस ग्लोबल में भी अनियमितता परिलक्षित होने पर टेंडर निरस्त करने के सख्त निर्देश दिए। अवस्थी ने कहा कि डीएनए उपकरणों के क्रय किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए। बैठक में सचिव गृह भगवान स्वरूप सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

30 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों की होगी स्वास्थ्य की जांच

● गैर संचारी रोगों के बढ़ते प्रभाव को कम करने की कवायद

● पुरुषों में ही सकता है स्तन कैंसर: सीएमओ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारत सरकार आने वाले दिनों में गैर संचारी रोगों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए 30 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच करायेगी। प्रदेश सरकार के सहयोग से होने वाली इस जांच में आशाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जांच के दौरान कैंसर, मधुमेह और ब्लड प्रेशर पर विशेषज्ञों का ध्यान केन्द्रित होगा। इसके लिए एएनएम एक हजार की आबादी पर सूची तैयार करेगी। बुधवार को यह जानकारी सीएमओ डॉ. नरेन्द्र अग्रवाल ने दी है।

एएनएम प्रशिक्षण केंद्र, अलीगंज में लखनऊ की 36 एएनएम के गैर संचारी रोगों पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण समापन को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉ. नरेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि इन सभी लोगों के सी बैक कम्युनिटी बेस्ड एसेसमेंट चेकलिस्ट फार्म आशाओं द्वारा भरे जायेंगे। इसके आधार पर जिन्हें अधिक नम्बर मिलेंगे, उनकी जांच पहले की जाएगी लेकिन जांच सभी की होगी। बता दें कि गैर संचारी रोग जिन्हें लंबे समय तक चलने वाले रोग भी कहा जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगते। बीमारी होने में लंबा समय लगता है और शुरू में उसके लक्षण दिखाई नहीं देते। इनका इलाज वर्षों तक और कुछ मामलों में पूरे जीवन काल तक चलता रहता है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि हमारे देश में गैर संचारी रोग समय पूर्व मृत्यु का एक प्रमुख कारण हैं। भारत में इस समय जितनी मृत्यु होती हैं उसका 60 फीसदी से अधिक मौत गैर संचारी रोगों के कारण हो रही हैं। उन्होंने बताया कि स्तन कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है, यद्यपि यह बहुत दुर्लभ है। पुरुषों में स्तन कैंसर 60 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। स्तन कैंसर के एक प्रतिशत केस पुरुषों में देखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह आशाएं अपने-अपने गांव में 30 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करेंगी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय राजा ने बताया कि आशाएं अपनी एक हजार की आबादी में 30 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का सी बैक फॉर्म भरेंगी। 1000 की आबादी में सामान्यत: 370 व्यक्ति 30 वर्ष से ऊपर के होते हैं। इन सभी का कम्युनिटी बेस्ड एसेसमेंट चेक लिस्ट आधारित मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा जिसके आधार पर उनमें रोग होने की संभावना का पता चलेगा। जो व्यक्ति ज्यादा संदेह के घेरे में होंगे उनकी पहले जांच की जाएगी। सभी लोगों की वर्ष में एक बार मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापे तथा कैंसर के लिए गांव में ही जांच की जाएगी। प्रशिक्षण डॉ एसके सक्सेना, अजीत कुमार यादव स्वास्थ शिक्षा अधिकारी गीता मिश्रा तथा सुष्मिता द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे सभी परीक्षा केन्द: कमलरानी वरूण

● पालीटेक्निक परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण को लेकर प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने की बैठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमलरानी वरूण ने सभी परीक्षा केन्द्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किये जाने के निर्देश दिये हैं। जिससे प्राविधिक शिक्षा परिषद की तरफ से परीक्षाओं की ऑनलाइन मानीटरिंग हो सके। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण तथा परीक्षाओं की शुचिता व गुणवत्ता को बरकरार रखा जाय।

बुधवार को अपने कार्यालय में पालीटेक्निक परीक्षा केन्द्र निर्धारण को लेकर आयोजित बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि गत वर्ष काली सूची में डाले गये परीक्षा केन्द्रों को पुन: परीक्षा केन्द्र न बताया जाय। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के लिए निर्धारित मानक में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये तथा मानक पूरा होने पर ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। बैठक में उन्होंने कहा कि एक संस्था में दो से अधिक संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र न बनाया जाये तथा विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही परीक्षा केन्द्र निर्धारित करना सुनिश्चित करें। प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन परीक्षा केन्द्रों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनकी जांच कराकर शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के भी निर्देश दिये गये हैं। बैठक में प्राविधिक शिक्षा परिषद के चेयरमैन विद्यासागर गुप्ता, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एस.राधा चौहान, संयुक्त सचिव प्राविधिक शिक्षा अलका वर्मा, निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग कानपुर आरसी राजपुत समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।

अपराधों पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही प्रदेश सरकार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के तमाम वादों और कथित आदेशों के बावजूद प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में तनिक भी सुधार नज़र नहीं आ रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं नहीं घटती हो। राजधानी लखनऊ में भी अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। लोग आशंकाओं में जी रहे हैं। प्रदेश में बुजुर्ग नागरिकों और बेटियों तक की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। अखिलेश ने कहा कि आजमगढ़ में ट्रिपिल मर्डर, मुजफ्फरनगर में नाबालिग से चलती गाड़ी में रेप, काकोरी में महिला का जंगल में शव, बहराइच में छह वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या, तीन दिन से लापता बच्ची का क्षत विक्षत शव मिला, लखीमपुर खीरी में छेड़छाड़ की रिपोर्ट न लिखी जाने पर युवती ने कीटनाशक पीकर जान दी और बापू भवन के अंदर क्षुब्ध किसान ने खुद को आग लगा ली। बलिया में युवती दरिंदगी की शिकार, बहराइच जेल में कैदी पूर्व प्रधान की मौत, हत्या होने का आरोप, देवरिया में मुनीम की हत्या। ये तो बानगी है कि भाजपा राज में किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का वादा कर उत्तर प्रदेश वासियों को अपराध व्यवस्था देने वाली भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने जंगलराज के लिए जानी जाएगी। अपराधिक घटनाओं की कई दिनों तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। पीड़ित का उत्पीड़न आम बात है। पुलिस अपराधियों को भाजपा नेताओं के कहने पर संरक्षण देती नज़र आती है। प्रशासनिक मशीनरी राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पंगु हो चली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेखौफ अपराधी लगातार कहर बरपा रहे हैं। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश वासियों के सुख चैन और शान्ति की दुश्मन बन गई है।

यूपी में भ्रष्टाचार जारी है: प्रियंका गांधी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना कार्रवाई का दावा करते हैं लेकिन उनकी सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार जारी है। उन्होंने कहा कि मानव संसधान विकास मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है कि मिड-डे-मील में भ्रष्टाचार के मामले में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। बुधवार को ट्वीट कर प्रियंका ने भाजपा सरकार पर निधाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है जबकि राज्य में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक खबर का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है कि मिड-डे-मील कार्यक्रम से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है।

बड़े बिजली बकायदारों पर आज से शुरू होगी कार्रवाई

● बारह दिसंबर तक चलेगा अभियान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विद्युत विभाग बड़े बकायदारों पर गुरुवार 28 नवम्बर से अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहा है। यह अभियान 12 दिसम्बर तक चलेगा। यह जानकारी प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने दी। उन्होंने बताया इस सन्दर्भ में वितरण निगमों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे गये हैं। इस अभियान में बड़े बकायेदारों पर वसूली की कार्रवाई की जानी है।

अभियान में खण्ड एवं उपखण्ड स्तर के समस्त अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं फील्ड कर्मचारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया प्रत्येक खण्ड हेतु न्यूनतम् 250 बकायेदारों से प्रतिदिन वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिन समस्त पुलिस परिवर्तन दल भी विद्युत विच्छेदन कार्य में सहयोग करने के लिये उपलब्ध रहेंगे। स्मार्ट मीटर बकायेदार उपभोक्ताओं का भी उपरोक्तानुसार सघन विद्युत विच्छेदन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राजस्व वसूली बढ़ाने एवं उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की सहूलियत के लिये आसान किश्त योजना भी लागू है। जिसके अन्तर्गत 71 लाख उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है।

किसान व युवा विरोधी है सरकार: लल्लू

● कांग्रेस के जिलाध्यक्षों व शहर अध्यक्षों की बैठक में हुई संगठन को मजबूत करने पर चर्चा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला-शहर अध्यक्षों के साथ कई मुद्दों पर बैठक की। जिसमें खासतौर से आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित भारत बचाओ महारैली को सफल बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ।

बैठक में पूरे प्रदेश में चल रहे अभियान और संगठन निर्माण पर चर्चा और समीक्षा हुई। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों ने अपने-अपने जिले में रैली के लिए चल रहे अभियानों की रिपोर्ट प्रस्तुत किए। बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के चलते आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। अर्थव्यवस्था का आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दैनिक जीवन-यापन के खर्च में भयानक गिरावट दर्ज हुई है। यह सब नोटबन्दी, जीएसटी के गलत क्रियान्वयन, बीजेपी के कुप्रबन्धन और विनाशक आर्थिक नीतियों का नतीजा है। उन्होंने किसानों की समस्या पर बोलते हुए कहा कि भारत को किसानों का देश कहा जाता है लेकिन भाजपा की जनविरोधी नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है न समय पर उसे खाद मिल रही है न पानी। जिन किसानों ने कर्ज लिया है उनको सरकार लगातार प्रताड़ित कर रही है।

उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि कर किसानों को लूटा जा रहा है। लेकिन देश की सरकार अपने पूंजीपति मित्रों की जेब भरने के लिए तरह-तरह की नीतियां बनाकर उनकी मदद कर रही है। बैठक को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं होगा। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश से चलकर हम 14 दिसम्बर को मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हुंकार भरेंगे। उन्होंने प्रदेश व जिला कमेटी से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं।

यूपीएचएसएसपी परियोजना से निकाले गये कर्मचारियों ने दिया धरना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपीएचएसएसपी परियोजना के जरिए प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में तैनात 5000 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाये जाने से आक्रोशित कर्मचारियों ने बुधवार को ईको पार्क में धरना देकर विरोध दर्ज कराया है। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना था कि ठेका प्रथा के जरिए पहले कर्मचारियों को काम और बाद में उन्हें बेरोजगार कर देना सरकार की रणनीति है। कर्मचारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सुरक्षित भविष्य की मांग की है।

संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारी संघ का कहना है कि गत 15 अक्टूबर को एनएचएम की तरफ से जिला स्वास्थ्य समिति से टेंडर करवाकर मानव आपूर्ति का निर्देश जारी हुआ। जिसमें पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन का कोई आदेश न होने से सभी कर्मचारियों की सेवाएं 30 नवंबर को समाप्त हो जायेंगी। धरने को संबोधित करते हुए महामंत्री सच्चितानन्द मिश्रा ने कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा आउटसोसिंग नियमावली बनाने के लिये कमेटी का गठन किया गया था। कार्मिक विभाग द्वारा नियमावली तैयार करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा नियमावली कैबिनेट में पेश नहीं की गयी। जिस कारण से आउटसोर्सिंग व्यवस्था में आज भी लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब संविदा कर्मचारी संघ युवाओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। जल्द ही आउटसोर्सिंग व्यवस्था में सुरक्षित नौकरी और उचित वेतन नहीं दिया गया तो प्रदेश के लाखों युवा कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगी। प्रदेश मंत्री मनीष मिश्र ने कहा कि सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कालेज के कर्मचारियों का वेतन कम कर दिया गया है। शासन लगातार एजेन्सियों के ऊपर हाथ रखे हुये है, नयी नियुक्ति तथा टेण्डर का खेल शासन द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के प्रोन्नतीय महामंत्री रामेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग व्यवस्था द्वारा युवाओं का शोषण किया जा रहा है। सरकार को तत्काल यह व्यवस्था बन्द करते हुये समस्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करना चाहिए और आउटसोर्सिंग व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलाने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाये। संविदा कर्मचारी संघ की सभी मांगे जायज हैं, सरकार तत्काल इनके समस्याओं का निराकरण करे। प्रदेश सहायक मंत्री विकास तिवारी ने कहा कि सरकार कर्मचारी के निष्कासन की प्रक्रिया बन्द करें तथा सभी कर्मचारियों को पदानुसार समान कार्य का समान वेतन दे, राम मनोहर लोहिया, पीजीआई तथा केजीएमयू प्रदेश के उच्च स्तरीय संस्थान हैं यहां के कर्मचारियों को प्रदेश का उच्चतम वेतनमान दिया जाये।

आउट सोर्सिंग कर्मियों के धरने में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इको गार्डेन पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों में आउट सोर्सिंग के तहत भर्ती कर्मियों के धरने में शामिल हुए। लल्लू ने उनकी मांगों पर अपना समर्थन देते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि आउट सोर्सिंग के तहत भर्ती कर्मियों को तत्काल उनका वेतन दिया जाए एवं उन्हें नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरी छीनने का गुजरात माडल लागू हो गया है। इसके कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल बयान देना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। पैरामेडिकल एवं नान पैरामेडिकल के युवा जो डिग्री प्राप्त कर बैठे हैं, जहां इन्हें अस्पतालों में पांच लाख पद खाली हैं उसमें भरा नहीं जा रहा है। इन्हें आउट सोर्सिंग पर पहले रखते हैं फिर ठेकेदार इन्हें नौकरी से निकाल फेंकते हैं। कांग्रेस पार्टी इनकी मांगों का समर्थन करती है।

ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में बदलाव के खिलाफ फार्मासिस्टों का धरना कल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के शेड्यूल की धारा 23 में भारत सरकार द्वारा किये गये संशोधन के विरोध में इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के फार्मासिस्ट 29 नवंबर को जंतर मंतर पर धरना देकर विरोध दर्ज करायेंगे। संसोधन को लेकर फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि संशोधन से आनेवाले दिनों में आशा एवं आंगनबाड़ी को भी चिकित्सालयों में औषधि वितरण का अधिकार मिलने लगेगा। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुनील यादव ने बताया कि जनता के हितों को ध्यान में रखकर आइपीए ने आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 के अनुसार केवल रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट ही औषधि का भंडारण वितरण कर सकता है और इस संशोधन में दर्ज एएनएम, आशा,आंगनबाड़ी, नर्स आदि कोई भी कर्मी फार्मेसिस्ट की योग्यता नहीं रखता है। अगर ये संशोधन हुआ तो अप्रशिक्षित एवं अयोग्य लोगों द्वारा जनता को औषधि उपलब्ध कराई जाएगी जो जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रस्ताव अत्यंत कमजोर है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है और लोगों के जीवन के लिए खतरनाक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केके सचान ने बताया कि भारत सरकार ने संशोधन का ड्राफ्ट 6 नवम्बर को जारी कर सुझाव मांगे हैं। प्रथम चरण में देश भर से इस प्रस्तावित संशोधन के विरोध में भारत सरकार को पत्र भेजे जा रहे हैं लेकिन व्यापक जनहित के कारण आंदोलन का भी फैसला लेना पड़ा है। फीपो सचिव सुभाष श्रीवास्तव ने कहा कि देश के सभी राज्यों के फार्मेसिस्ट, केंद्रीय योजनाओं के फार्मेसिस्ट आंदोलन में शामिल होंगे।

जम्मू-कश्मीर की समूची आबादी को बंद नहीं किया जा सकता : आजाद

भाषा। नई दिल्ली

कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह स्वीकार करते हैं कि देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के तहत जम्मू कश्मीर की 70 लाख की आबादी को ही बंधक बना दिया जाए।

आजाद ने कहा कि सरकार का दावा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगाई गई निषेधाज्ञा जम्मू कश्मीर के सभी थाना क्षेत्रों से वापस ले ली गई है लेकिन इसे वापस लेने संबंधी कोई भी आदेश जनता की जानकारी में नहीं है। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद वहां लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन और कई अन्य की याचिकाओं पर सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इस दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि नागरिकों के अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आजाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को वह समझते हैं लेकिन इस वजह से घाटी की समूची 70 लाख की आबादी को ताले में बंद नहीं किया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि हालात समान्य होने संबंधी दावों के समर्थन में प्रशासन द्वारा पेश आंकड़े हकीकत से बहुत परे हैं और शीर्ष अदालत को कानूनी सिद्धांतों के आधार पर इन पाबंदियों की वैधता के बारे में फैसला करना होगा। अनुराधा भसीन की ओर से अधिवक्ता वृन्दा ग्रोवर ने इन पाबंदियों को असंवैधानिक बताया और कहा कि इन प्रतिबंधों आनुपातिक परीक्षण से गुजरना होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के बाद पूर्व राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई पाबंदियों को मंगलवार को न्यायोचित ठहराया था। मेहता ने कहा था कि उनकी लड़ाई भीतर सक्रिय दुश्मनों से ही नहीं बल्कि सीमापार से सक्रिय शत्रुओं से भी है। उन्होंने अनुच्छेद 35ए हटाए जाने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेन्स पार्टी के नेताओं के भाषणों और सोशल मीडिया पर अपलोड पोस्ट का हवाला दिया। अनुच्छेद 35ए राज्य के स्थाई निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था और अनुच्छेद 370 में राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रावधान थे।

महाराष्ट्र विधानसभा में विजय चिन्ह दिखाते शिव सेना के विधायक। बुधवार को यहां नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की

मां के डांटने पर बेटी ने फांसी लगाकर जान दी

बरेली। खेत में काम करते समय बेटी ने खाना खाने की जिद की तब मां ने काम समाप्त होने के बाद खाना खाने को कहा जिससे नाराज होकर बेटी घर वापस लौट आई और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम समाप्त होने के बाद घर वापस लौटी मां ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जो मौके पर पहुंची और मृतका की लाश को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

नवाबगंज थाने के गांव ईद जागीर निवासी मुन्ना लाल की 16 वर्षीय बेटी शिवानी ने कल शाम अपने ही घर में खपरैल की बल्ली से लगे पंखे से साड़ी बांध कर फांसी लगा ली पोस्टमार्टम हाउस पर मृतका के पिता ने बताया कि उसने लगभग 5 साल पहले बेटी शिवानी का विवाह क्योलड़िया थाने के गांव मथुरापुर उमरिया निवासी तुलाराम से किया था। लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही शिवानी का गौना होना था। वह कल दिन में अपनी मां चंद्रो देवी के साथ गांव में एक खेत पर गन्ने की छिलाई करने गई थी जहां काम समाप्त होने से पहले ही उसने मां से कहा कि वह खाना खाने के लिए घर पर चले लेकिन मां ने उसे कहा कि काम समाप्त होने के बाद ही वह घर जाएगी। जिद करने पर मां ने बेटी की डांट लगा दी तब वह गुस्से में आकर काम छोड़कर घर आ गई और यहीं पर उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम समाप्त होने के बाद जब उसकी मां घर वापस लौटी तब उसने बेटी की लाश को फांसी पर लटके देखा और उसके पिता को सूचना दी जो घर वापस लौटा और पुलिस को सूचना दे दी इस मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी मृतका सात बहनों में सबसे छोटी थी उसके दो भाई है।

दुर्घटना के तीन आधार, नशा, नींद और तेज रफ्तार

ललितपुर। यातायात माह नवंबर 2019 के तहत जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के अंतर्गत दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए नेहरू नगर के विद्यालय में यातायात नियमों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सबसे पहले मां सरस्वती जी की फोटो के समक्ष यातायात प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इसके बाद विधालय के प्रबंधक ध्यान सिंह यादव, प्रधानाचार्य सीताराम, रवि बाबू, कवि यादव ने अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया। फिर विधालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को, समस्त विद्यालय स्टाफ को एवं मुहल्ले के नागरिकों को यातायात प्रभारी आशुतोष मिश्रा व सहायक यातायात प्रभारी नरेन्द्र सिंह ने बड़े ही विस्तार से सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। यातायात प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने कहा कि हमेशा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करे जिससे अपना जीवन सुरक्षित बना रहे। कहा कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल व हेड फोन का प्रयोग न करें, वाहन चलाते समय हैल्मेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय शीट बेल्ट का प्रयोग करे, वाहन चालक तेज गति से वाहन न चलायें, दो पहिया वाहन चालक तीन सवारी बैठाकर वाहन न चलाएं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन ना चलाएं, वाहन चालक सड़क पर वाहन चलाते समय किसी भी वाहन को ओवरटेक न करे और वाहन चालक हमेशा वाहन के कागजाद साथ लेकर वाहन चलाएँ वाहन चालक सड़क पर वाहन चलाते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, जिससे अपना जीवन सुरक्षित बना रहे। विद्यालय के प्रबंधक ध्यान सिंह यादव, सीताराम, रामकुमार रजक, रामबाबू यादव ने भी सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी देकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया देवेन्द्र राय ने भी सड़क सुरक्षा नियमो के बारे में बताया कि वाहन चालकों द्वारा सड़क पर वाहन चलाते समय की गई जरा सी लापरवाही कितनो का सुहाग छीन लेती है और कितनो को अनाथ बना देती है। हमेशा हम सबको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात नियमो के बारे में जानकारी होना ही इसका बचाव नही है। यातायात नियमो को पालन करना ही इसका बचाव है। यातायात प्रभारी ने संयुक्त रूप से यातायात नियमो की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में छात्र-छात्रायें सड़क सुरक्षा नियमो के बारे में नारे लगाते चल रहे थे। छात्र छात्राओं के हाथों में संदेश लिखी तख्तियां भी थी जो सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के बारे में जागरूकता सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना के तीन आधार नशा नींद ओर तेज रफ्तार, ट्राफिक पुलिस का यही संदेश जीवन नहीं तो क्या है शेष, सोच समझकर चलना है दुर्घटना से बचना है, ड्राइवर ने यदि नशा कर डाला तो समझो फोटो पर लगी माला सन्देश दे रहीं थी। रैली विद्यालय से शुरू होकर नेहरू नगर की विभिन्न गलियों में घूमती हुई वापिस विद्यालय आकर सम्पन्न हुयी। समस्त टीचर स्टाफ, यातायात पुलिस स्टाफ मे दीपक कुमार द्विवेदी, भूपेन्द्र सिंह व मुहल्ले के नागरिक मौजूद रहे।

यातायात जागरूकता रैली निकालते विद्यालय के बच्चे

फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर बृहस्पतिवार तक ईडी की हिरासत में

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में कई दस्तावेजों के संबंध में तथा गवाहों के साथ पूछताछ के लिए फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह और एक अन्य सह आरोपी को बृहस्पतिवार तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय को हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी।

अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में मालविंदर के अलावा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी को भी 28 नवंबर तक निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें सिंह और गोधवानी को सात दिसंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि बढ़ाने से इंकार दिया था और उन्हें सात दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच एजेंसी ने इन दोनों को 14 नवंबर को तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया था। कथित घोटाला के संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर मामले में उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। मालविंदर और गोधवानी धन शोधन मामले में आरोपी हैं जो धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धाराओं 3 एवं 4 के तहत दंडनीय अपराध है।उच्च न्यायालय ने जेल अधीक्षक को दोनों आरोपियों को ईडी की हिरासत में सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने ईडी को 28 नवंबर को उनकी पुलिस हिरासत खत्म होने पर दोनों आरोपियों को संबंधित निचली अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मालविंदर और गोधवानी को ईडी की हिरासत के दौरान बुधवार शाम तथा कल सुबह आधा-आधा घंटा के लिए अपने परिजन एवं वकील से मिलने की इजाजत भी दी। अदालत ने उन्हें घर का बना भोजन खाने की भी अनुमति दे दी।

पेज एक का शेष

शिव तीर्थ में ...

प्रफुल्ल ने बताया कि तीनों पार्टियों से गुरुवार को दो-दो मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है जिनके नाम आज रात तक तय कर लिए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में मुख्यमंत्री समेत शिवसेना के 15 मंत्री होंगे। राकांपा से एक उपमुख्यमंत्री और 14 मंत्री जबकि कांग्रेस से स्पीकर व तेरह मंत्री होंगे। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत (कुल सदस्य संख्या का) से अधिक नहीं हो सकती यानी कि उद्धव कैबिनेट में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा विधानसभा में शिवसेना के 56, राकांपा के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा का विशेष सत्रआज यहां शुरू हुआ जिसमें नव निर्वाचित 285 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। समर्थकों के जमावड़े और भव्यता के पैमाने पर अभूतपूर्व साबित होने जा रहे कल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत, कमलनाथ, भूपेश बघेल और अन्य, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी न्योता गया है। कांग्रेस नेता विजय वेतद्दीवार ने बुधवार को यह जानकारी दी। सोनिया को आमंत्रित करने के लिए उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे रात को दिल्ली पहुंच गए। इससे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बताया था कि सोनिया गांधी को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। हालांकि, दिल्ली में विपक्षी पार्टी ने स्पष्ट किया कि सोनिया और राहुल कल के समारोह का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। पटेल और खडगे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहले से तय कार्यक्रम में व्यस्तता के चलते उद्धव के शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं ले सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से देर शाम यह जानकारी दी गई। चाकचौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) विनय चौबे समेत आला पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को समारोह स्थल पर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। शिवाजी पार्क पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है जिसे देखते हुए 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को लगाया जाएग। कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यातायात प्रबंधन के साथ चर्चा कर आगंतुकों और वीवीआईपी मेहमानों के वाहनों की पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इससे पहले, बंबई उच्च न्यायालय ने शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता जताई और कहा कि सार्वजनिक मैदानों पर इस किस्म के कार्यक्रमों को आयोजित करने का यह नियमित सिलसिला नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति आरआई छागला की खंडपीठ ने कहा कि अन्यथा हर कोई इस तरह के कार्यक्रम के लिए मैदान को इस्तेमाल करना चाहेगा। एनजीओ वीकम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करती पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कल होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। उच्च न्यायालय ने एक एनजीओ की याचिका पर वर्ष 2010 में इस क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया था।

वित्त मंत्री ...

दिया है। यूपीए सरकार में लोगों को एमएसपी समर्थन का फायदा हुआ था, लेकिन मोदी सरकार में उनकी हालत बदतर हो गई है।' देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा की उच्च सदन में शुरुआत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अर्थतंत्र चरमरा रहा है और आर्थिक प्रगति ठहर गई है। उन्होंने कहा कि आज बाजार ठंडे पड़े और और मांग टूट गई है। लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं बची है तथा किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि हम इस स्थिति को सरकार की तरह आर्थिक सुस्ती (स्लोडाउन) या चक्रीय गिरावट (साइकिलिक रिसेशन) नहीं कह सकते। उन्होंने दावा किया, हम गहरे आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने चर्चा में भाग लेते हुए सवाल किया कि आज देश के लोगों और उद्योगों में अनिश्चितता क्यों है? उन्होंने कहा कि इसका एक ही जवाब है कि विश्वास टूट गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के रविप्रकाश वर्मा ने कहा कि देश में आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति है जहां बाजार में मांग ही नहीं रह गई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है। टीआरएस के के केशव राव ने कहा कि राजग सरकार के शासनकाल के दौरान निवेश का स्तर घटा है और कृषि विकास दर कम हुई है। माकपा के इलावरम करीम ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आर्थिक विकास दर में कमी आई है और बेरोजगारी पांच दशक के निचले स्तर पर है। आटोमोबाइल क्षेत्र पांच दशक के निचले स्तर पर है जहां लगभग 10 लाख लोगों का रोजगार गया है।

कांग्रेस को ...

प्रकार की बातें देश की जनता के सामने लाई जा रही हैं कि एसपीजी कानून को गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने के लिए बदला जा रहा है। यह वास्तविकता नहीं है। शाह ने कहा कि 2015 के बाद राहुल गांधी ने एसपीजी को बताए बिना भारत के अंदर 1892 बार और विदेशों में बिना एसपीजी को बताए करीब 247 बार यात्राएं की हैं। सोनिया गांधी ने भी अनेकों बार इस तरह बिना बताए यात्राएं कीं। प्रियंका गांधी ने 339 बार बिना बताए, यात्राएं कीं। उन्होंने कहा कि हमारा उनसे आग्रह है कि उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था का अनुपालन करें। इससे पहले कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने की पृष्ठभूमि में एसपीजी अधिनियम में संशोधन का तीखा विरोध किया और केंद्र सरकार से मांग की कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिजनों को विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की सुरक्षा आजीवन प्रदान की जानी चाहिए। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने चर्चा में भाग लेते हुए आगाह किया कि इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा है।

मस्जिद की ...

पर पुनर्विचार की याचिका नहीं दाखिल करेगा। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने गत नौ नवम्बर को अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राममंदिर बनवाने और मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने का सरकार को आदेश दिया था। न्यायालय ने इससे ठीक पहले विवादित स्थल पर शिया वक्फ बोर्ड की दावेदारी सम्बन्धी अपील को खारिज कर दिया था। रिजवी का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में मस्जिद बनाने के लिए जमीन लेने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो सका। बोर्ड के सदस्यों ने इस मामले के शरई पहलुओं पर गौर करने के लिए और वक्त मांगा है। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष की रहनुमाई कर रहा आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड मस्जिद निर्माण के लिए जमीन लेने से पहले ही इनकार कर चुका है। रिजवी ने बताया कि शिया वक्फ बोर्ड का यह मानना है कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो भी फैसला किया है वह अन्तिम है और राम जन्म भूमिबाबरी मस्जिद प्रकरण के विवाद का अन्त है। फैसले पर किसी भी तरह की कोई पुनर्विचार याचिका दायर करने से देश के हालात खराब हो सकते हैं।

अयोध्या मामले ...

के खिलाफ दिसंबर के पहले सप्ताह में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि एक सदी से भी पुराने बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि मामले का उच्चतम न्यायालय ने नौ नवंबर को निपटारा कर दिया। इससे पहले, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने से मना कर दिया था।

ट्राई के फिलहाल टैरिफ प्लान, न्यूनतम शुल्क मामले में हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं

नई दिल्ली(भाषा)। दूरसंचार नियामक ट्राई की फिलहाल टैरिफ प्लान या न्यूनतम शुल्क तय करने के मामले में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं है। हालांकि दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से इसकी मांग कर रही हैं और हाल ही में उन्होंने आने वाले दिनों में अपनी शुल्क दरें बढ़ाने की घोषणा की है।

इस मामले में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क तय करने के किसी नए प्रस्ताव को इस मौके पर लाना ठीक नहीं होगा क्योंकि दूरसंचार कंपनियां पहले ही आने वाले दिनों में शुल्क बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। सूत्रों ने कहा कि इस समय ट्राई का कोई भी कदम दूरसंचार कंपनियों द्वारा शुरू की जा चुकी प्रक्रिया को पटरी से उतार देगा। ट्राई का मानना है कि उसका हस्तक्षेप करना अंतिम विकल्प होगा।

दूरसंचार कंपनियां पहले ही अपने शुल्क दरों में बढ़ोत्तरी की घोषणा कर चुकी हैं। अब ट्राई इस पूरी स्थिति के साफ होने का इंतजार करेगा। वहीं दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी तरह का न्यूनतम शुल्क तय करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस संबंध में कोई भी निर्णय आने वाले दिनों में लिया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि बुधवार को दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों की ट्राई के साथ हुई बैठक में दूरंसचार सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क तय करना प्रमुख मुद्दा रहा। उद्योग का एक धड़ा चाहता है कि ट्राई इस मामले में हस्तक्षेप करे। इसी बीच एक अन्य खबर के मुताबिक उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा टैरिफ प्लान के प्रकाशन में पारदर्शिता के मुद्दे पर बुधवार को नई बहस शुरू करने का निर्णय किया है। ट्राई ने एक बयान में कहा कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के मामले में पारदर्शिता होना अपरिहार्य है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसकी एक समग्र समीक्षा की जरूरत महसूस की गई है।

नियामक को बहुत से ग्राहकों से टैरिफ से जुड़ी जानकारी में पारदर्शिता के अभाव की शिकायतें प्राप्त हूईं थीं। इसके बाद ट्राई ने यह पहल की है।

सांसदों ने श्री श्री रविशंकर से सीखे क्रोध और तनाव पर नियंत्रण के गुर

नई दिल्ली (भाषा)। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने बुधवार को लगभग 30 संसद सदस्यों एवं सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को आधुनिक जीवनशैली और कामकाज के तनावपूर्ण तरीकों के कारण बढ़ रही अवसाद की समस्या से निपटने के तरीकों से अवगत कराया।

उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्य्रकम में केन्द्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री श्री रविशंकर से मुलाकात कर सार्वजनिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के बारे में चर्चा की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के अलावा विभिन्न दलों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नायडू ने जीवन को शांतिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आध्यात्मिक समझ को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारतीय दर्शन इस समझ को विकसित करने में मददगार है। नायडू ने कहा कि महान भारतीय परंपरा में जीवन की सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए बुजुर्गों, ऋषि मुनियों और गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यवस्थित परिपाटी है। इस दौरान श्री श्री रविशंकर ने योग और ध्यान का महत्व बताते हुए मानसिक शुद्धि के लिए इन दोनों क्रियाओं का नियमित अभ्यास करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरी नींद लेने और सांस क्रिया पर ध्यान केन्द्रित करने पर भी जोर दिया।

प्याज की माला पहनकर बिहार विस पहुंचे राजद विधायक

भाषा। पटना

बिहार विधानसभा क्षेत्र राजापकाड से राजद विधायक शिवचंद्र राम बुधवार को प्याज की ैमालौ पहनकर सदन पहुंचे। राजद विधायक प्याज की बढ़ती कीमत के मद्देनजर सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इसकी माला गले में पहनकर बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। शिवचंद्र ने कहा बढ़ती कीमतें लोगों को उनके सामान्य भोजन से वंचित कर देगी। प्याज, जिसकी पहले कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम से कम थी, अब 80 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं है। वास्तव में, मुझे इसे (गले में पहनी माला में लगे प्याज) 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदना पड़ा।

उन्होंने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर सब्जी उपलब्ध कराने वाली स्टाल स्थापित करने के वादे को खोखला बताते हुए कहा कि मैंने अभी तक इस तरह का कोई स्टाल नहीं देखा है। शिवचंद्र ने कहा मैं इस माला (प्याज से बनी) को पहनकर सदन के भीतर जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की नजर इस पड़े और यह उन्हें कुछ गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर करे।

उन्होंने मांग की कि सरकार गरीबों को 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्याज उपलब्ध कराए।

यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्याज की माला पहने विधायक शिवचंद्र को खुद को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिल पाया या नहीं क्योंकि नीतीश कुमार सदन की भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही के दौरान नहीं पहुंचे थे। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद सहित अन्य विपक्षी दलों कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों के राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करने के कारण अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी।

भाजपा अघोरी कोशिशों के बावजूद अपना सीएम नहीं बना पाई: राउत

भाषा। मुंबई

शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में सत्ता फिर से हासिल करने के लिए अघोरी (निकृष्ट) कोशिशें कीं लेकिन राज्य की जनता ने इसे नाकाम कर दिया और इसके साथ ही देश की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो गई है। राउत ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह हैरानी नहीं होगी अगर शिवसेना महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) बनाने के बाद केंद्र में सरकार बना ले।

भाजपा से टकराव के बाद पिछले एक महीने से नियमित रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि वह बृहस्पतिवार से नियमित संवाददाता सम्मेलन संबोधित नहीं करेंगे और शिवसेना के मुखपत्र सामना से जुड़े अपने काम पर लौटेंगे। राज्यसभा सदस्य शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं। भाजपा ने राकांपा के अजित पवार के समर्थन के साथ महाराष्ट्र में शनिवार को सरकार बनाई थी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली यह सरकार मंगलवार को गिर गई जब अजित पवार ने निजी कारणों का हवाला देते हुए उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राउत ने यहां पत्रकारों से कहा, भाजपा महाराष्ट्र में अपनी अघोरी कोशिशों के बावजूद अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में रोष है। राज्यसभा सदस्य ने कहा, महाराष्ट्र में बदलाव की शुरुआत हो रही है, महाराष्ट्र ने देश को नई सुबह दिखाई है। राउत ने कहा कि लोग पहले उन पर भरोसा नहीं करते थे जब वह कहते थे कि शिवसेना का सूर्ययान मंत्रालय (सचिवालय) के छठे माले पर सुरक्षित उतरेगा। इसका मतलब है कि पार्टी राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। मुख्यमंत्री का कार्यालय यहां राज्य सचिवालय की छठी मंजिल पर स्थित है। शिवसेना नेता ने कहा, लेकिन हमारा सूर्ययान सुरक्षित उतरा और आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर सूर्ययान दिल्ली में उतरे। शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार के प्रमुख शिल्पकारों में से एक माने जा रहे राउत ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह पूछे जाने पर कि बृहस्पतिवार को ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए किसे-किसे आमंत्रित किया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा, मेरी जिम्मेदारी अब कम होगी। मैं कल से आपको (मीडिया) संबोधित नहीं करूंगा। मैं सामना में अपना मूल काम शुरू करूंगा, ये सभी फैसले नए मुख्यमंत्री लेंगे। एक अन्य सवाल पर राउत ने कहा कि वह लड़ाका और शिवसेना कार्यकर्ता हैं न कि चाणक्य। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने मंगलवार को ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया। ठाकरे बृहस्पतिवार शाम को यहां दादर इलाके के शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

अजित पवार के लौटने का भरोसा था परिवार एकजुट है: रोहित पवार

मुंबई। राकांपा विधायक रोहित पवार ने बुधवार को कहा कि उन्हें भरोसा था कि उनके चाचा अजित पवार पार्टी में लौट आएंगे और उन्हें खुशी है कि अजित पवार ने पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। उन्होंने यह भी कहा कि पवार परिवार एकजुट है और हमेशा रहेगा। अजित पवार ने मंगलवार देर रात अपने चाचा और राकांपा के दिग्गज नेता शरद पवार से मुलाकात की थी। अजित के महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने और फिर इस्तीफा देने के बाद यह शरद पवार से पहली मुलाकात थी।

शरद पवार के बड़े भाई अप्पासाहेब पवार के पोते रोहित पवार ने एक समाचार चैनल से कहा, मैं भरोसा नहीं कर पाया कि यह कैसे हुआ। एक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। परिवार के सदस्य के तौर पर कुछ कशमकश थी, मैं समझ नहीं सका कि क्या हो रहा है। उनसे पूछा गया था कि भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद अजित पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उन्हें कैसा लगा था। रोहित पवार ने कहा, लेकिन हमें उनकी वापसी का पूरा यकीन था। हम दादा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अजित पवार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह बहुत सक्षम प्रशासक हैं और शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए महत्वपूर्ण है जो राज्य में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे लगा कि परिवार के सदस्य और राकांपा कार्यकर्ता के तौर पर जब दादा कल साहेब (शरद पवार) से मिले तो मुझे खुशी हुई। रोहित पवार ने भाजपा पर अन्य दलों से नेताओं की खरीद-फरोख्त का हथकंडा अपनाने का भी आरोप लगाया। रोहित ने कहा, उन्होंने इस मामले में भी कुछ हद तक इस शैली (हथकंडे) का इस्तेमाल किया। दादा को यह पसंद नहीं आया होगा और फिर उन्होंने साहेब से मुलाकात की। मुझे उम्मीद है कि हम उनके (अजित पवार) मार्गदर्शन में जल्द ही लोगों की सेवा करेंगे।

बेंगलुरु में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक कर्मियों जैसा एक पुतला लगाया गया

महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं का झारखंड चुनाव पर नहीं होगा प्रभाव: रविशंकर

भाषा। रांची

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को दावा किया कि महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाओं और हरियाणा के चुनाव परिणामों का झारखंड के विधानसभा चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहां भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा और स्थिर सरकार बनेगी।

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह दावा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए यहां भाजपा का जनसंकल्प पत्र जारी करते हुए किया। प्रसाद ने एक सवाल पर कहा, सेवा करने पर जनता आशीर्वाद देती है। इसका परिणाम मिलता है। हाल में लोकसभा चुनाव के परिणाम और हरियाणा तथा महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम देखकर इसका आप स्वयं अनुमान भी लगा सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या हरियाणा के चुनाव परिणाम और महाराष्ट्र में राजनीतिक घटना का झारखंड के चुनावों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, रविशंकर प्रसाद ने कहा, झारखंड में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। पूर्ण बहुमत की और स्थाई, प्रामाणिक हमारी विजय होगी।उन्होंने कहा, हरियाणा में हम सरकार में हैं। दुष्यंतजी ने स्पष्ट कहा है कि वह कांग्रेसवाद और उसकी नीतियों में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, झारखंड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और यहां भाजपा को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम स्थिर सरकार का गठन करेंगे। उन्होंने कहा, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में हमारी युति (गठबंधन) को पूर्ण बहुमत था। जो यह सरकार बनी है, मैंडेट (जनादेश) को चुराया गया है। उन्होंने कहा, वास्तव में शिवसेना ने भाजपा की पीठ पर सवार होकर चुनाव जीता है। प्रसाद ने भाजपा के मंत्री रहे और अब बागी होकर मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सरयू राय के बारे में किसी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया।

असम के नजरबंदी शिविरों में 2016 से अब तक 28 बंदियों की मौत हुई: सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की नजरबंदी के लिए संचालित छह शिविरों में 2016 से अब तक 28 लोगों की विभिन्न बीमारियों के कारण मौत हुई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि 2016 से इस साल 13 अक्टूबर तक असम के छह नजरबंदी शिविरों में रखे गए 28 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में 988 विदेशी नागरिकों को रखा गया है। मृतकों को हर्जाना देने संबंधी पूरक प्रश्न के जवाब में राय ने कहा कि गैरकानूनी ढंग से देश में आने वाले और रहने वालों के पकड़े जाने पर नजरबंदी के दौरान बीमारी के कारण मौत होने पर मुआवजा या हर्जाना देने का कोई प्रावधान नहीं है। इन शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव की आशंका को गलत बताते हुए राय ने कहा कि असम सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नजरबंदी केन्द्र सभी मूलभूत सुविधाओं और चिकित्सा देखभाल की मूलभूत सुविधाओं से लैस हैं। राय ने कहा कि प्रत्एक नजरबंदी केन्द्र में मेडिकल स्टाफ के साथ अंदर ही अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इनमें डाक्टरों द्वारा बंदियों की नियमित जांच की जाती है।

रास में उठी चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मांग

भाषा। नई दिल्ली

दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को, उच्च न्यायालयों के फैसलों को आवश्यकता पड़ने परउच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के समय होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाते हुए राज्यसभा में बुधवार को कई सदस्यों ने चेन्नई में सर्वोच्च अदालत की पीठ स्थापित किए जाने की मांग की। शून्यकाल में एमडीएमके सदस्य वाइको ने चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा होने पर खुद उच्चतम न्यायालय का ही बोझ कम होगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 54,013 मामले लंबित हैं।

वाइको ने कहा कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है और दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को उच्च न्यायालयों के फैसलों को आवश्यकता के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। यहां आने, ठहरने पर होने वाला खर्च और भाषा की दिक्कत तथा अन्य समस्याएं होती हैं।उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से राहत मिल सकती है अगर चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित कर दी जाए। द्रमुक के पी विल्सन ने कहा कि पूर्व में स्थाई संसदीय समितियां उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रीय पीठ स्थापित किए जाने की सिफारिश कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली आने, ठहरने पर होने वाला खर्च और भाषा की दिक्कत तथा अन्य समस्याओं के कारण वही लोग उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं जो इनका सामना कर सकते हैं। विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे से स्वयं को संबद्ध किया। इनमें से ज्यादातर सदस्य दक्षिण भारतीय राज्यों के थे। शून्यकाल में भाजपा के डी पी वत्स ने मांग की सांसद क्षेत्रीय विकास निधि (एमपीलैड) के तहत पांच करोड़ रुपए की किस्त सालाना जारी की जानी चाहिए और इसके लिए कोष की उपयोगिता संबंधी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।

वत्स ने कहा कि कोष जारी करने में दो से तीन साल का समय लग जाता है क्योंकि पहले अनुमान तैयार किया जाता है, फिर उसे मंजूरी दी जाती है और उसके बाद काम पूरा होता है। इसके पश्चात राशि जारी की जाती है।इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जानना चाहा कि अगर धन राशि जारी कर दी जाए और उसका उपयोग न हो पाए, वह राशि बैंक में पड़ी रहे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा।

अदाणी अहमदाबाद मैराथन बहादुर जवानों को समर्पित

अहमदाबाद। भारत में सबसे बड़े कॉरपोरेट समूहों में से एक, अदाणी ग्रुप ने अदाणी अहमदाबाद मैराथन के तीसरे संस्करण को गर्व से झंडी दिखाकर रवाना किया। हर साल की तरह, इस साल भी भारतीय सैनिकों की बहादुरी को उजागर करने के लिए, अदाणी ग्रुप ने मैराथन को समर्पित किया। थीम #runyoursoldiers भारत के वीर सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने की एक पहल है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। इस साल इस मैराथन कुल 14,000 पंजीकरण हुए और कुल 12,000 प्रतिभागियों ने भागीदारी की जो पिछले दो संस्करणों से अधिक है। 42 किमी की दौड़ के प्रमुख वर्ग के समारोह में शामिल होने वाले में प्रमुख रूप से प्रणव अदाणी और नॉरसन विलियम्सन थे, जिन्होंने दौड़ को हरी झंड़ी भी दिखायी।

10 किमी को एयर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरन वीएम, ब्रिगेडियर विनोद बाजिया, करण अदाणी, श्रीमती परिधि अदाणी, सागर अदाणी, श्रणव अदाणी और श्रीमती नम्रता अदाणी ने हरी झंडी दिखाई। 5 किमी को मुख्यमंत्री विजयभाई रूपानी, राजेश अदाणी और ब्रिगेडियर विनोद बाजिया द्वारा हरी झंडी दिखाई गयी।

बेंगलुरू में महालक्ष्मी सीट से उप चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर श्वेत पत्र लाए सरकार: येचुरी

भाषा। नई दिल्ली

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को मांग की कि सरकार को अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। उन्होंने इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के आंकड़ों की ध्यान दिलाते हुए यह मांग की जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया गया है।

एचुरी ने ट्वीट किया, यह तीसरी तिमाही है जब देश में विकास दर गिरी है। यदि यह मंदी नहीं है तो यह क्या है? सरकार को भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। फिच समूह की भारतीय फर्म इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार छठवीं तिमाही जुलाई-सितंबर के दौरान विकास दर गिरकर 4.7 प्रतिशत पर आ सकती है। फर्म ने वर्तमान वित्त वर्ष में चौथी बार विकास दर को लेकर अपने पूर्वानुमान को घटाया है। एचुरी ने कहा, धनवानों का तुष्टिकरण और कंपनियों को कर रियायत देना बंद कीजिए। इसके बदले इस धन का इस्तेमाल रोजगार बढ़ाने और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि के लिए सार्वजनिक निवेश में कीजिए और बेहद जरूरी हमारे आधारभूत ढांचे का निर्माण कीजिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अप्रैल-जून के दौरान पांच प्रतिशत रही जो 2013 के बाद सबसे धीमा विकास है। वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए 4.7 प्रतिशत का विकास दर अनुमान लगातार छठवी तिमाही में कम विकास दर का प्रतीक है। ऐसा 2012 के बाद पहली बार हो रहा है। विकास दर में कमी ऐसे हालात में हो रही है जबकि निगमित कर दरों में कटौती सहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

मोदी सरकार बनने के बाद सरकारी कामकाज में बढ़ा हिंदी का उपयोग: मंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का उपयोग बढ़ा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गिरिधारी यादव और रमा देवी के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले पांच वर्षों में हिंदी और सभी स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद से प्रधानमंत्री के निर्देश पर सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ा है। मंत्री ने कहा कि 45 वर्ष पहले कानून के जरिए हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रसार का निर्णय हुआ था, लेकिन अब तक यह नहीं हो पाया तो उनको जवाब देना चाहिए जो इस दौरान सरकार में थे। लोकसभा अध्यक्ष सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के जन्मदिन की जानकारी दी तो सदस्यों ने मेजे थपथपाकर उनको बधाई दी।

ईडी ने एक रत्न निर्यात कंपनी, प्रवर्तकों की पांच करोड़ की परिसंपत्तियां कुर्क की

भाषा। नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान की एक रत्न निर्यात करने वाली कंपनी और उसके प्रवर्तकों की करीब पांच करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने बुधवार को बताया कि कंपनी, प्रवर्तकों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी और धनशोधन की जांच के दौरान ये संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई परिसंपत्तियों में जयपुर में चार अचल संपत्तियां, तीन आवासीय सह कार्यालय परिसर और मुंबई के संभ्रांत इलाके में एक फ्लैट शामिल हैं। इनका मूल्य करीब 3.80 करोड़ रुपए है। वही इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक की जयपुर शाखा में 1.31 करोड़ रुपए की जमा को भी कुर्क किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत एजेंसी ने विपुल जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के शांति कुमार चोरडिया, उमराव मल चोरडिया और नयनतारा चोरडिया के खिलाफ जब्ती का अस्थाई आदेश जारी कर कुल 5.11 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई बैंक ऑफ बड़ौदा की जयपुर की नेहरू प्लेस शाखा में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ की गई है। बयान के अनुसार, इन इकाइयों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की और गड़बड़ी कर आपराधिक इरादे से बैंक को कर्ज राशि वसूलने से रोका। इसके कारण बैंक को करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह राशि इन कर्जदाताओं को दी गई थी। बयान के मुताबिक जांच में रत्न निर्यात में लगी तीन कंपनियां विपुल जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, विपुल जेम्स एंड के. वी. एक्सपोर्ट्स का नाम सामने आया था। इसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई : सरकार

भाषा। नई दिल्ली

केन्द्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के व्यय में कोई इजाफा नहीं हुआ है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो पृथक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था।

उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए कोई पृथक वित्तीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। इस कारण जम्मू कश्मीर के व्यय में कोई इजाफा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख, संघ शासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आए हैं।

कैबिनेट ने मानव तस्करी रोकने के लिए भारत और म्यामां के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी रोकने के लिए भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और म्यामां के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध को और मजबूत करना एवं मानव तस्करी को रोकना, पीड़ितों को छुड़ाना और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना तथा मानव तस्करी के सभी रूपों को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाना और तस्करी के शिकार लोगों को सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इसके माध्यम से दोनों देशों में मानव तस्करों और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ त्वरित जांच और अभियोजन सुनिश्चित करना तथा आप्रवासन एवं सीमा नियंत्रण सहयोग को मजबूत करना और मानव तस्करी रोकने के लिए संबंधित मंत्रालयों और संगठनों के साथ रणनीति का क्रियान्वयन करना है। इसके तहत दोनों देश मानव तस्करी रोकने की कोशिशों के तहत कार्य समूहाकार्यबल का गठन करेंगे। साथ ही मानव तस्करों एवं तस्करी के शिकार लोगों के आंकड़े जुटाए जाएंगे और भारत एवं म्यामां के तय केंद्र बिंदुओं के जरिए सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देशों से जुड़ी एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाने के साथ तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, उन्हें छुड़ाना और स्वदेश वापस भेजने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करना और उसका पालन करेंगे। भारत और म्यामां के बीच सीमा नियंत्रण एजेंसियों और संचार के विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग मानव तस्करी रोकने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का एक प्रभावी साधन हो सकता है।

युवक-युवती ने जहर खाया, युवक की मौत

जयपुर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली थानाक्षेत्र में बुधवार सुबह एक होटल में ठहरे युवकयुवती ने सल्फास की गोलियां खाकर कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस जांच अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि दो दिन पूर्व हरियाणा से आकर एक होटल में ठहरे युवकयुवती ने कल रात सल्फास की गोलियां खाकर कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने अमित शर्मा (25) को मृत घोषित कर दिया जबकि युवती का अस्पताल में उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि दोनों के बीच पिछले डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजनों ने युवती का विवाह अन्य लड़के के साथ इस वर्ष फरवरी में करा दिया था। मृतक युवक के परिजनों के यहां पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अमृतसर में बुधवार को अन्य पदाधिकारियों के साथ स्वर्ण मंदिर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के फिर से निर्वाचित अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल (मध्य में) प्रार्थना करते हुए

क्विक न्यूज

अशोक लेलेंड को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम से 1,750 बसों के लिए मिला आर्डर

नई दिल्ली। हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लेलेंड ने बुधवार को बताया कि उसे तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम से 1,750 बसो के लिए आर्डर मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी नियामकीय सूचना मे इसकी जानकारी दी है। इसमे कहा गया है कि राज्य सरकार का यह आर्डर हाल मे कंपनी को कई अन्य राज्य परिवहन निगमो से मिले आर्डर के बाद उसे मिला है। अशोक लेलेंड के मुख्य परिचालन अधिकारी अनुज कथूरिया ने कहा, हमे इस आर्डर की पुष्टि मिलने पर प्रसन्नता हुई है। हमारी उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के साथ बेहतर मूल्य की हमारी क्षमता से हमे भारत मे बसो के क्षेत्र मे अग्रणी स्थिति को बनाए रखने मे मदद मिली है। कंपनी ने हालांकि, इस सौदे की वित्तीय जानकारी नही दी है। इस आर्डर के साथ ही कंपनी के पास उपलब्ध राज्य परिवहन निगमो के बसो के आर्डर की संख्या मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अशोक लेलेंड वर्तमान मे दुनिया की चौथी बड़ी बस विनिर्माता कंपनी और भारत की सबसे बड़ी बस विनिर्माता है।

भारत का इस्पात उत्पादन अक्टूबर में 3.4 प्रतिशत गिरकर करीब 91 लाख टन रहा

नई दिल्ली। भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन अक्टूबर माह मे एक साल पहले इसी माह के मुकाबले 3.4 प्रतिशत घटकर 90.89 लाख टन रहा। विश्व इस्पात संघ (वर्ल्डस्टील) की रिपोर्ट मे यह जानकारी दी गई है। वर्ल्डस्टील ने अपनी ताजा रिपोर्ट मे कहा है कि एक साल पहले इसी माह के दौरान भारत मे कच्चे इस्पात का उत्पादन 94.08 लाख टन रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान वैश्विक इस्पात उत्पादन मे भी हल्की गिरावट आई है। अक्टूबर 2019 मे विश्व इस्पात उत्पादन 15 करोड 15 लाख टन रहा जो कि एक साल पहले इसी माह के उत्पादन 15.58 करोड़ टन के मुकाबले 2.8 प्रतिशत कम रहा। रिपोर्ट मे गया है, चीन का कच्चा इस्पात उत्पादन जहां अक्टूबर 2019 मे एक साल पहले के मुकाबले 0.6 प्रतिशत घटकर 8.15 करोड़ टन रहा वही भारत का इस्पात उत्पादन 3.4 प्रतिशत घटकर 90.98 लाख टन रहा। चीन मे अक्टूबर 2018 मे 8.20 करोड़ टन और भारत मे 94.08 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ था। इस दौरान जापान का इस्पात उत्पादन 4.9 प्रतिशत घटकर 81.57 लाख टन रहा। अमेरिका मे इस दौरान 74.07 लाख टन उत्पादन हुआ जो कि एक साल पहले इसी माह मे हुए इस्पात उत्पादन के मुकाबले दो प्रतिशत नीचे रहा। रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ मे जर्मनी ने अक्टूबर माह मे 33 लाख टन, इटली ने 22 लाख टन, फ्रांस मे 12 लाख टन और स्पेन मे 12 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ। वर्ल्डस्टील मे शामिल सदस्य दुनिया के कुल इस्पात उत्पादन का 85 प्रतिशत उत्पादन करते है। इसमे 160 से अधिक इस्पात उत्पादक शामिल है।

सियाम का कोरिया की कामा के साथ वाहन उद्योग में सहयोग के लिए समझौता

नई दिल्ली। वाहन उद्योग के संगठन सियाम ने वाहन उद्योग की बेहतरी मे सहयोग के लिए कोरिया के वाहन उद्योग संगठन कोरिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (कामा) के साथ समझौता किया है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की यहां बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह समझौता एक सतत, सुरक्षित, स्वच्छ, वहनीय और सक्षम वाहन उद्योग के क्षेत्र मे सहयोग के लिए किया गया है। विज्ञप्ति मे कहा गया है कि दोनो संगठन आपस मे सहयोगात्मक बातचीत और साझा हितो से जुड़े मुद्दो पर चर्चा के लिए नियमित रूप से सूचनाओ के आदान- प्रदान की प्रणाली स्थापित करेगे। सियाम के अध्यक्ष राजन बढ़ेरा ने इस भागीदारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सबंधो की शुरुआत 1996 मे ही हो गई थी जब हुंडई मोटर्स ने भारतीय बाजार मे प्रवेश किया था। उन्होने कहा कि भारतीय वाहन विनिर्माताओ टाटा समूह, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा ने भी कोरिया के आटोमोबाइल उद्योग मे उल्लेखनीय निवेश किया है। वढेरा ने कहा वर्ष 2000 के बाद से इन कंपनियो ने भारत मे विभिन्न क्षेत्रो मे 3.8 अरब डालर का निवेश किया है। यह निवेश इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोबाइल, धात्विक और अन्य क्षेत्रो मे किया गया। हाल ही मे दक्षिण कोरिया की किया मोटर्स ने भारत मे शुरुआत की है। कामा के अध्यक्ष एवं सीईओ जियांग मार्न-की ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से दोनो के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। यह समझौता दोनो पक्षो के आपसी फायदे, निवेश बढ़ाने और व्यापार बढ़ाने मे मददगार साबित होगा।

शेयर बाजार नई ऊंचाई पर

सेंसेक्स 199 अंक चढ़ा, निफ्टी 12,100 अंक की ऊंचाई पर

भाषा। मुंबई

बैंक, आईटी और वाहन कंपनियों के शेयरों में विदेशी निवेशकों की लिवाली से शेयर बाजार बुधवार को नई रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हुए। वैश्विक बाजारों की सकारात्मक प्रवृत्ति से बाजार को मजबूती मिली।

तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 199.31 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 41,020.61 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। तीस शेयरों में से 24 लाभ में रहे।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 63 अंक यानी 0.52 प्रतिशत सुधरकर 12,100.70 के नए रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में एस बैंक सर्वाधिक लाभ में रहा। इसमें 7.65 प्रतिशत की तेजी रही। उसके बाद क्रमशः एसबीआई (2.43 प्रतिशत) का स्थान रहा। इसके अलावा मारुति 2.38 प्रतिशत, सन फार्मा 1.87 प्रतिशत और एचयूएल 1.78 प्रतिशत मजबूत हुए।वहीं दूसरी तरफ एल एंड टी को सर्वाधिक नुकसान हुआ। कंपनी का शेयर 2.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, टाटा स्टील, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक भी नुकसान में रहे।विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक रुख के बीच सतत विदेशी पूंजी प्रवाह से बाजार धारणा को बल मिला।अस्थाई आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 4,677.75 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे। कारोबारियों के अनुसार नवंबर महीने के वायदा एवं विकल्प खंड में सौदों के समाप्त होने से पहले की लिवाली से भी तेजी को बल मिला।एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग (चीन), तोक्यो (जापान) और सियोल (दक्षिण कोरिया) लाभ में रहे जबकि शंघाई (चीन) में गिरावट रही। वहीं यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में सकारात्मक रुख रहा।

● सेंसेक्स के शेयरों में एस बैंक सर्वाधिक लाभ में रहा, इसमें 7.65 प्रतिशत की तेजी रही। उसके बाद क्रमशः एसबीआई (2.43 प्रतिशत) का स्थान रहा

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन उपायों पर काम कर रही सरकार: गोयल

नई दिल्ली। सरकार जम्मू - कश्मीर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहनों और उपायों पर काम कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीरोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2019 में यहां कहा ,औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों और उपायों पर काम कर रही है। यह इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा। गोयल ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएआई) और दुबई की कंपनियां जम्मू - कश्मीर में कारोबारी अवसर तलाशने की इच्छुक हैं। उन्होंने कहा , " मुझे यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां उद्योग लगाना और निवेश करना चाहेंगे। " यहां जलविद्युत , औषधि , पर्यटन और खाद्य क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने और खुबानी तथा सी बकथॉर्न पौधे जैसे कुछ स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जम्मू - कश्मीर में आधुनिक संस्थान और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। रेल क्षेत्र को लेकर , गोयल ने कहा कि उधमपुर - श्रीनगर - बारामूला को जोड़ने वाली 272 किलोग्राम लंबी रेल लिंक परियोजना पर काम चल रहा है। चेनाब रेल ब्रिज पर भी अब काम शुरू हो गया है , जो कि आंतकी गतिविधियों के कारण रुक गया था। उन्होंने कहा , यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा और हमें उम्मीद है कि इसे बहुत अहम परियोजना के रूप में घोषित किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर दस हजार करोड़ रुपए की गई

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की प्राधिकृत पूंजी को मौजूदा 3,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के इस निकाय में अतिरिक्त पूंजी डालने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले से एफसीआई को खाद्यान्नों की खरीद और वितरण में सुविधा होगी। इसके साथ ही एफसीआई अपने कर्ज और ब्याज लागत को भी कम कर सकेगा। एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया, एफसीआई की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाए जाने के बाद इस उपक्रम में केन्द्रीय बजट के जरिए अतिरिक्त पूंजी डाली जा सकेगी। इससे एफसीआई को खाद्यान्न भंडार को बनाए रखने में आने वाली लागत का वहन करने में मदद मिलेगी।विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार के इस कदम से एफसीआई का कर्ज कम होगा, ब्याज लागत की बचत होगी और खाद्य सब्सिडी में भी कमी आएगी। वक्तव्य में कहा गया है कि एफसीआई को अपना काम करते हुए लंबे समय तक अनाज के भंडार का रख रखाव करना होता है। उसके इस काम में सरकार को वित्तपोषण उपलब्ध कराना होता है। यह काम इक्विटी पूंजी के जरिए या फिर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। एफसीआई की 31 मार्च 2019 को चुकता पूंजी 3,447.58 करोड़ रुपए है। एफसीआई का गठन खाद्य निगम कानून 1964 के तहत किया गया था। सरकार की सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की नीति को अमल में लाने के लिए एफसीआई का गठन किया गया।

कार्वी शेयर ब्रोकिंग ऐसे कार्यों में लिप्त थी जिसकी कभी अनुमति नहीं थी: सेबी प्रमुख

भाषा। मुंबई

कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग प्रकरण के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि यह ब्रोकरेज कंपनी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाई गई जिनकी कभी अनुमति नहीं दी गई थी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नियामक ने कुछ ही दिन पहले स्टॉक ब्रोकिंग फर्म कार्वी के कामकाज करने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई है। कार्वी ब्रोकिंग फर्म उसके पास रखे ग्राहकों के शेयरों में अपनी सहयोगी इकाइयों के जरिए खरीद-फरोख्त करने के काम में लिप्त पाई गई। त्यागी ने कहा कि जून में सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर अपनी स्थिति इस मामले में स्पष्ट कर दी थी कि किसी भी इकाई को इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त नहीं होना चाहिए। इससे पहले की भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेबी अध्यक्ष ने यहां कंपनी संचालन पर आयोजित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की एशियाई बैठक के मौके पर अलग से संवाददाताओं से कहा, बुनियादी तौर पर जिसकी कभी अनुमति नहीं थी, वह काम किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि इसके लिए जून में ही मना किया गया है। उन्होंने कहा, चाहे इस मामले में स्पष्ट तौर पर पहले कुछ भी नहीं कहा गया था फिर भी आप अपने स्तर पर ग्राहकों के शेयरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। त्यागी ने दोहराया यह बुनियादी मुद्दा है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। पिछले शुक्रवार को स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कार्वी को शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों के लिए नए ग्राहकों का पंजीकरण करने से रोक दिया गया। कंपनी पर ग्राहकों की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करने का आरोप है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने इस संबंध में सेबी को प्राथमिक रिपोर्ट भेजी थी, उसके बाद ही सेबी की तरफ से कदम उठाया गया। सेबी ने कहा कि एक्सचेंज की शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के खिलाफ 19 अगस्त को सीमित जांच की गई। इसमें एक जनवरी के बाद के सौदों की जांच की गई। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत बरुआ की 12 पृष्ठ के अंतरिम आर्डर में कहा गया है कि मामले में ग्राहकों की प्रतिभूतियों का आगे दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत नियामकीय हस्तक्षेप की जरूरत है।

बीएसई, एनएसई ने वाणिज्यिक पत्र को सूचीबद्ध करने के लिए व्यवस्था जारी की

नई दिल्ली । बंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वाणिज्यिक पत्र को सूचीबद्ध करने के लिए व्यवस्था की रूपरेखा जारी की है। इस कदम का उद्देश्य इस तरह की प्रतिभूतियों में निवेशकों का योगदान बढ़ाना है। शेयर बाजारों ने अलग - अलग नोटिस में कहा कि जारीकर्ता अब 27 नवंबर या उसके बाद जारी किए गए वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेबी ने अक्टूबर में शेयर बाजारों को वाणिज्यिक पत्र को सूचीबद्ध करने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं की जरूरी व्यवस्था पेश करने के लिए कहा था। उसके बाद ही यह कदम उठाया गया है। दिशा - निर्देशों के अनुसार , जारीकर्ता कुछ विशेष जानकारियों के साथ अपने वाणिज्यिक पत्र सूचीबद्ध कराने के लिए शेयर बाजारों के पास आवेदन भेज सकते हैं। कम से कम 100 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति वाली और इसी तरह की अन्य प्रतिभूति वाली कंपनियां , गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और अन्य इकाइयां वाणिज्यिक पत्रों को सूचीबद्ध कराने के लिए पात्र है।

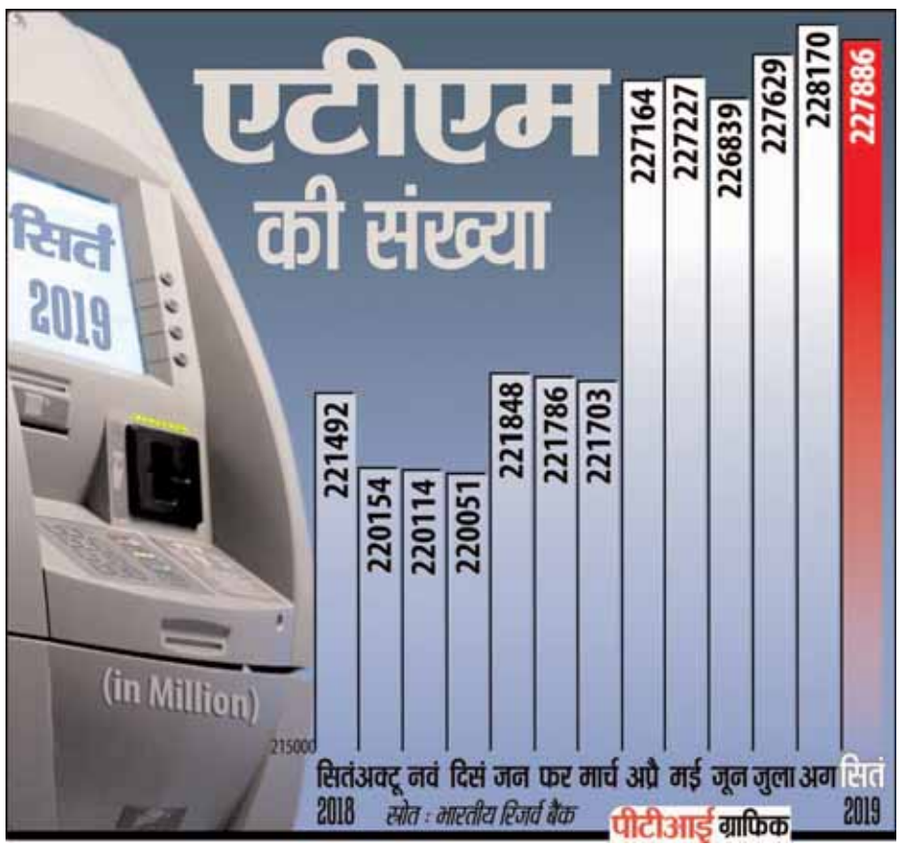

15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ा

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक साल बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। वित्त आयोग कर राजस्व और दूसरे संसाधनों का केन्द्र और राज्यों के बीच बंटवारे के बारे में अपने सुझाव के साथ केन्द्र को रिपोर्ट सौंपता है।

एक अधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग को अपनी पहली रिपोर्ट पहले वित्त वर्ष 2020- 21 के लिए सौंपने की मंजूरी दी है। उसके बाद आयोग के कार्यकाल को बढ़ाते हुए उसे 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट 2021- 22 से लेकर 2025- 26 तक के लिए देने को कहा है। आयोग का कार्यकाल मूलरूप से अक्टूबर 2019 तक था लेकिन बाद में इसे एक महीना बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 तक कर दिया गया। वक्तव्य में कहा गया है कि वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ने से उसे 2020- 2026 की अवधि के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सहूलियत होगी। इस दौरान आयोग नए आर्थिक सुधारों और वास्तविकताओं के मद्देनजर वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलनात्मक अनुमानों का परीक्षण कर सकेगा।

वक्तव्य में कहा गया है, चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगे होने के कारण आयोग विभिन्न राज्यों की दौरा हाल ही में पूरा कर पाया। इससे आयोग द्वारा राज्यों की जरूरतों का विस्तृत आकलन करने पर असर पड़ा है। इसमें कहा गया है कि आयोग को जो काम दिया गया है वह व्यापक क्षेत्र में फैला है। इसमें कहा है, इनके प्रभाव की व्यापक जांच परख करने और उन्हें राज्यों और केन्द्र सरकार की जरूरतों के साथ जोड़कर देखने में अतिरिक्त समय की जरूरत होगी।

गडकरी का वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के विनिर्माण में सरकारी मदद का आश्वासन

भाषा। नई दिल्ली

कच्चे तेल के आयात को देश के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती बताते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वाहन कंपनियां वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के विनिर्माण पर ध्यान लगाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इसमें उनकी मदद सुनिश्चित करेगी।

गडकरी ने जैव-ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उपज के विविधीकरण की जरूरत पर भी बल दिया। वह यहां न्यूजेन मोबिलिटी समिट-2019 को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा, मैं आपको सरकार की ओर से भरोसा दिलाता हूं कि हम सब वाहन क्षेत्र के समर्थक हैं। आप सब भविष्य की नीतियों को लेकर बहुत आशंकित हैं लेकिन सरकार नए विकास (वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहन) के प्रोत्साहन और सहयोग में बहुत रुचि रखती है। आप पुराने विनिर्माण के साथ आगे बढ़ें लेकिन इसके साथ ही वैकल्पिक ईंधन को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि सरकार कच्चे तेल के आयात, प्रदूषण और लागत प्रभावी विकल्प अपनाने की नीति को लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडलीय सचिव और प्रधान सलाहकार को विशेष निर्देश दिया है कि वह कोयला गैसीकरण और उससे मेथनॉल बनाने की दिशा में काम करे। गडकरी ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था की दिक्कत यह है कि हमारा आयात हमारी पूंजी लागत का 20 प्रतिशत है। यह देश के सामने एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। यह वह समय है जब हमें किसी समाधान को खोजना होगा।

आपूर्ति से एक घंटा पहले बिजली खरीदने की व्यवस्था एक अप्रैल से हो सकती है शुरू: सीईआरसी चेयरमैन

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पी के पुजारी ने बुधवार को कहा कि खरीद के साथ ही कम से कम समय में बिजली आपूर्ति शुरू करने की व्यवस्था अगले साल एक अप्रैल से शुरू हो सकती है। इसमें बिजली वितरण कंपनियां या निजी उपयोग के लिए बिजली संयंत्र चलानी वाली इकाइयों के ग्राहक आपूर्ति से महज एक घंटा पहले बिजली खरीद कर सकेंगे।

फिलहाल बिजली बाजारों में अगले दिन की आपूर्ति के लिए एक दिन पहले (डीएएम) बिजली खरीद करनी होती है। इन बाजारों में दो घंटे सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कारोबार होता है।

इंडिया एनर्जी फोरम के 22वें इंडिया पावर फोरम के दौरान संवाददाताओं से अलग से बातचीत में पुजारी ने संवाददाताओं से कहा, हम

उम्मीद कर रहे हैं कि वास्तविक समय पर आधारित बिजली बाजार एक अप्रैल 2020 से काम करने लगेगा। वास्तविक समय आधारित बिजली बाजार पर संबद्ध पक्षों के साथ नियमन रूपरेखा पर चर्चा पूरी हो चुकी है। हालांकि, उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि सीईआरसी द्वारा नियमन की मंजूरी के बाद वास्तविक समय पर आधारित बिजली बाजार तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमें प्रणाली बनानी है। साफ्टवेयर (कारोबार समाधान) तैयार करना होगा और लोगों को उसके बारे में शिक्षित करने की जरूरत होगी। इसके अमल में आने के साथ बिजली वितरण कंपनियां समेत उपभोक्ता बेहतर तरीके से ऊर्जा आपूर्ति की योजना बना सकते हैं। वहीं बिजली उत्पादक कंपनियां अपना उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ा या घटा सकती हैं।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित मसौदा नियमन के तहत एक दिन में आधे-आधे घंटे के 48 सत्र होंगे। इसका मतलब है कि बिजली का कारोबार 24 घंटे हो सकेगा। इसमें अगर उपभोक्ता दोपहर 1.30 से 2 बजे के सत्र में बिजली खरीदता है, तब बिजली आपूर्ति उसी दिन दोपहर तीन बजे से की जा सकती है।इससे पहले, उन्होंने सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि नियामक ने बिजली क्षेत्र में कई नियमनों का प्रस्ताव किया है जो अगले साल एक अप्रैल से प्रभाव में आ सकता है। इसमें वास्तविक समय पर आधारित बिजली नियमन प्रमुख है।उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 20 साल में बिजली क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में काफी कुछ किया गया है लेकिन अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।सम्मेलन में टेरी के महानिदेशक अजय माथुर, इंडिया एनर्जी फोरम के अध्यक्ष अनिल राजदान समेत अन्य लोगों ने भी अपनी बातें रखी।

● फिलहाल बिजली बाजारों में अगले दिन की आपूर्ति के लिए एक दिन पहले (डीएएम) बिजली खरीद करनी होती है, इन बाजारों में दो घंटे सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कारोबार होता है

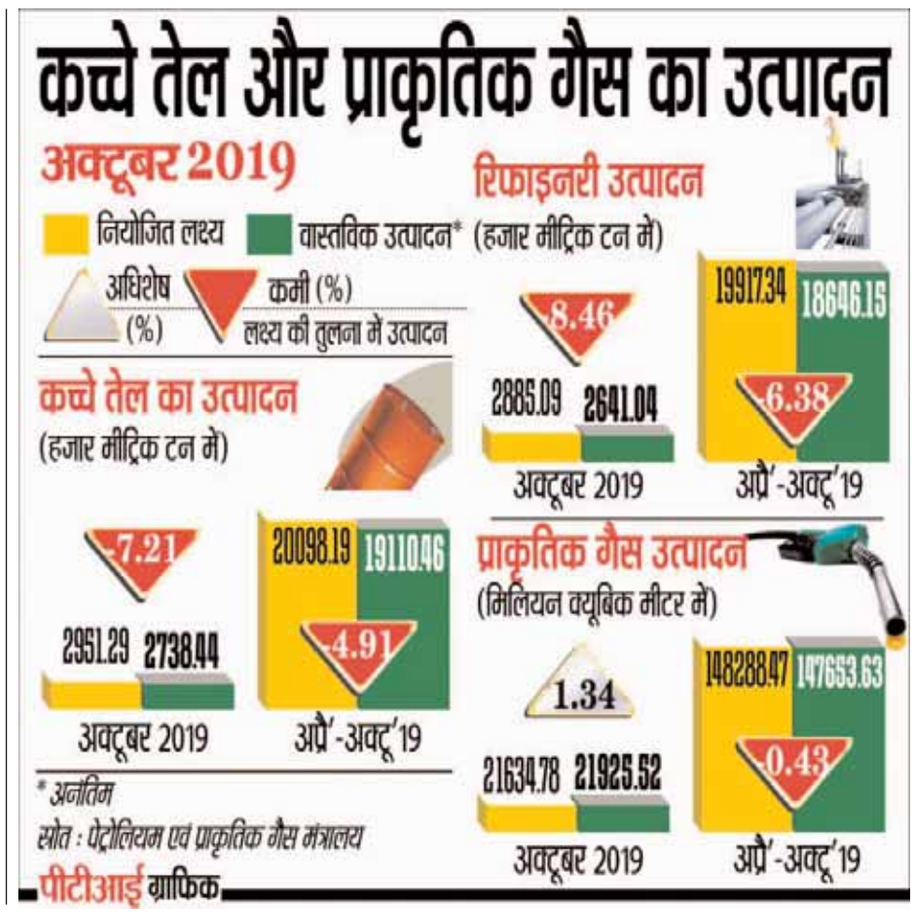

बांग्लादेश में 2016 कैफे हमला मामला:

सात संदिग्धों को फांसी की सजा

● देश के इतिहास में सबसे भीषण आतंकवादी हमले में एक भारतीय लडकी समेत 20 लोग मारे गए थे

भाषा। ढाका

बांग्लादेश में बुधवार को ढाका कैफे पर हमले में 20 से अधिक लोगों की हत्या करने वाले को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस एक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह के एक सदस्य को ले जाते हुए

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में 2016 में हुए इस्लामिक स्टेट के हमले में संलिप्तता के आरोप में विशेष बांग्लादेशी न्यायाधिकरण ने आठ संदिग्धों में से सात को मौत की सजा सुनाई है। देश के इतिहास में सबसे भीषण आतंकवादी हमले में एक भारतीय लड़की समेत 20 लोग मारे गए थे। ढाका के आतंकवाद-रोधी विशेष न्यायाधिकरण के न्यायाधीश मुजिबुर रहमान ने पुराने ढाका में अदालत परिसर में सजा सुनाते हुए कहा, उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। दोषियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया था।

मामले की जांच में यह पता चला कि दोषियों ने आतंकवादियों को धन मुहैया कराया था, हथियार की आपूर्ति की थी या फिर हमले में सीधे तौर पर शामिल लोगों की सहायता की थी। घटना एक जुलाई, 2016 को ढाका के गुलशन इलाके में हुई थी। न्यायाधीश ने आठवें आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष प्रतिबंधित नियो-जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (नियो-जेएमबी) द्वारा किए गए हमले में उसके संबंध को साबित नहीं कर सका। हमले में मारे गए 17 विदेशी नागरिकों में नौ इतालवी, सात जापानी, एक भारतीय लड़की शामिल थे। बंधक बनाए जाने के दौरान दो बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे।

हमले में मारे गए लोगों में शामिल भारतीय लड़की तारिशी जैन बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा थी और वह छुट्टी मनाने के लिए ढाका आई थी। अपने फैसले में न्यायाधीश ने बांग्लोदशी मूल के कनाडाई नागरिक तमीम चौधरी को हमले का मास्टरमाइंड बताया, जो बाद में राष्ट्रव्यापी आतंकवाद रोधी सुरक्षा अभियान के दौरान मारा गया था।

पाक सुरक्षा एजेंसी ने आतंकवादी योजना को विफल किया, तीन आतंकवादी गिरफ्तार

लाहौर (भाषा)। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एजेंसी ने बुधवार को बताया कि उसने पंजाब प्रांत के दक्षिण में स्थित एक खुफिया एजेंसी के दफ्तर और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना को विफल कर दिया है और इस बाबत अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआईएस) के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी)ने एक बयान में बताया कि डेरा गाज़ी खान की उसकी इकाई को मंगलवार को सूचना मिली थी कि सरकारी डिग्री कॉलेज चोबारा के पास तीन आतंकवादी मौजूद हैं। बयान में बताया गया है कि सीटीडी ने तीन आतंकवादियों के ठिकाने पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे संवेदनशील प्रतिष्ठानों और जिले में एक खुफिया एजेंसी के दफ्तर को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। बयान के मुताबिक, एक्यूआईएस के आतंकवादियों की पहचान एम सलीम, एम कासिम, जमील-उर-रहमान के तौर पर हुई है। उनके पास से विस्फोटक, हथगोले, पिस्तौल और नकदी बरामद की गई है। अल-कायदा के सरगना एमन अल-जवाहिरी ने सितंबर 2014 में एक ऑडियो संदेश में एक्यूआईएस बनाने का ऐलान किया था जो भारत, म्यांमा और बांग्लादेश में लड़ेगा।

काबुल में आतंकी हमले में भारतीय मूल के अमेरिकी विशेषज्ञ की मौत : पोम्पिओ

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बताया कि अफगानिस्तान में यूएनडीपी के लिए काम कर रहे भारतीय मूल के अमेरिकी विशेषज्ञ की काबुल में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई है। पोम्पिओ ने बताया कि काबुल में संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी पर हुए आतंकवादी हमले में अनिल राज की मौत हो गई। उन्होंने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता में बताया, मैं दुख के साथ पुष्टि करना चाहता हूं कि 24 नवंबर को काबुल में संयुक्त राष्ट्र की एक गाड़ी पर हुए आतंकवादी हमले में अमेरिका के कैलिफोर्निया निवासी अनिल राज की मौत हो गई। इस हमले में स्टाफ समेत पांच अन्य नागरिक भी जख्मी हुए हैं।

राज अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के लिए काम कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का लक्ष्य गरीबी को खत्म करना है। पोम्पिओ ने कहा, हम पीड़ित के परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा, अफगान लोगों की मदद करने के लिए काम रहे संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को निशाना बनाकर हमले करना अविवेकपूर्ण है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

विदेश विभाग ने राज के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी है। अमेरिकी मीडिया की खबरों में बताया गया है कि वह कैलिफोर्निया के सारातोगा में रहते थे। अफगानिस्तान में 24 नवंबर को हुए हमले की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। राज ने 2002 में सारातोगा हाई स्कूल से पास हुए थे और रीवरसाइड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली थी और इसके बाद डेनवर विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों में परास्नातक की डिग्री ली थी। यूएनडीपी के प्रशासक अचिम स्टेनर ने हमले की कड़ी निंदा की और मांग की कि अपराधियों को इंसाफ के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा, यूएनडीपी की ओर से, मैं मारे गए हमारे सह कर्मी के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और इस हमले में जख्मी हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहता हूं। उन्होंने एक बयान में कहा कि हमारा समर्पित स्टाफ अफगानिस्तान की सरकार और लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे।

ईरानियों ने बेहद खतरनाक साजिश नाकाम की : खमैनी

एएफपी। तेहरान

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अल खमैनी ने बुधवार को कहा कि देश ने पिछले महीने पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद एक बेहद खतरनाक साजिश को नाकाम किया है।

पेट्रोल के दामों में 200 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की आधीरात को की गई घोषणा के कुछ घंटों बाद 15 नवंबर को यह प्रदर्शन शुरू हुए थे। इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप धारण कर लिया था और इस दौरान कई पेट्रोल पंप जला दिए गए, पुलिस थानों पर हमला किया गया और दुकानों में भी लूटपाट हुई। बाद में हालांकि इन विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया गया। अधिकारियों ने अभी तक इस दौरान हताहत हुए लोगों या गिरफ्तार किए गए लोगों के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान देश के अधिकतर इलाके प्रभावित हुए थे।

सरकारी टेलीविजन के मुताबिक खमैनी ने कहा, लोगों ने एक गहरी, व्यापक और बेहद खतरनाक साजिश को नाकाम किया जिसमें बर्बादी, क्रूरता और लोगों की हत्या के लिए काफी रकम खर्च की गई थी। ईरानी नेता ने बासीज - इस्लामिक गणराज्य सरकार के वफादार लड़ाकों - के एक समूह को संबोधित करते हुए यह बात कही। खमैनी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में ईरानी नागरिकों का सोमवार को तेहरान में सरकार समर्थक विशाल रैली निकालने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, लोगों ने एक बार फिर साबित किया कि वे शक्तिशाली और महान हैं तथा मौके पर अपनी उपस्थिति से उन्होंने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया।

अमेरिका के टेक्सास स्थित रसायन संयंत्र में धमाका

वाशिंगटन (एएफपी)। अमेरिका के टेक्सास स्थित एक रसायन संयंत्र में बुधवार धमाका हुआ जिसके बाद आसमान में आग की ऊंची लपटे दिखाई। मीडिया ने बताया कि धमाके बाद लोगों को इलाके से निकाला जा रहा है। नेडरलैंड स्वयंसेवी दमकल विभाग के स्थानीय अधिकारी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, कृपया ध्यान दें कि पोर्ट नेचेस स्थित टीपीसी संयंत्र के आधे मील के दायरे में सभी को बाध्यकारी तरीके से दूर जाने का निर्देश दिया जाता है। सोशल मीडिया पर धमाके का वीडियो और तस्वीर साझा की गई है जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति बता रहा है कि धमाके बाद चारों तरह कांच के टुकड़े फैल गए। संयंत्र से मात्र दो मिनट की दूरी पर रह रहे रेयान मैथ्यूसन ने एएफपी से कहा, जब धमाके के बाद कांच के टुकड़े गिरे और छत-दरवाजे में कंपन महसूस हुई तब हमारी आंखे खुली। 25 वर्षीय रेयान ने कहा कि धमाके के बाद वह स्तब्ध और डरे हुए हैं। काउंटी जज जेफ ब्रानिक ने स्थानीय समाचार वेबसाइट को बताया कि अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

क्विक न्यूज

पाकिस्तान के सेवानिवृत्त सैन्य जनरल सीपीईसी प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त

इस्लामाबाद (भाषा)। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही मे गठित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) असिम सलीम बाजवा को नियुक्त किया है। सीपीईसी प्राधिकरण का गठन इस मकसद के साथ किया गया कि अरबों डॉलर की परियोजनाओं का काम समय से पूरा हो सके। सीपीईसी सड़कों, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं का नियोजित नेटवर्क है जो चीन के संसाधन संपन्न शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र को अरब सागर पर पाकिस्तान के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। सीपीईसी का शुभारंभ 2015 मे किया गया था जब चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे और अब इसमें पाकिस्तान मे विकास की विभिन्न परियोजनाओं मे 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया

कोलंबो (भाषा)। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव तक अपनी नवनिर्वाचित सरकार को चलाने के लिए बुधवार को 35 राज्य मंत्रियों और तीन उप मंत्रियों की नियुक्ति के साथ अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। राष्ट्रपति ने अपने सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे को नए रक्षा राज्य मंत्री नियुक्त किया, जो उनके 16 सदस्ईय मंत्रिपरिषद का पहले से ही हिस्सा है। हालांकि, राष्ट्रपति के भतीजे एवं प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे को कोई पद नही दिया गया है। इन 38 नए मंत्रियों मे न तो किसी महिला को शामिल किया गया है और न ही तमिल एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक को शामिल किया गया है। हालांकि, 16 सदस्ईय अंतरिम मंत्रिपरिषद मे दो तमिल एवं एक महिला शामिल किए गए थे। गोटबाया राजपक्षे ने कहा, इन पदों को विशेषाधिकार के तौर पर नही मानना चाहिए, ए सभी पद हमारे घोषणापत्र मे किए गए वादों को पूरा करने और जनता की भलाई के लिए अपने कार्य को लागू करने के लिए है।

भारत को तीन ऐतिहासिक कलाकृतियां वापस लौटाएगा ऑस्ट्रेलिया

मेलबर्न (भाषा)। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को कहा कि वह जनवरी मे अपनी भारत यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क स्थित भारतीय मूल के कलाकृति विक्रेता से खरीदी गईं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तीन कलाकृतियां वापस लौटाएंगे। नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने सुभाष कपूर नामक व्यक्ति से ए कलाकृतियां खरीदी थी, जिनके खिलाफ भारत और अमेरिका मे आपराधिक कार्वाई चल रही है। गैलरी ने शोध के बाद स्वेच्छा से भारत को कलाकृतियां वापस करने का निर्णय लिया गया है। कलाकृतियां तमिलनाडु के 15वीं सदी के द्वारपालों का जोड़ा और छठी से 8वीं शताब्दी के बीच राजस्थान या मध्य प्रदेश के नागराज की है। मॉरिसन ने एक बयान मे कहा, भारत की तरह हम भी अपनी प्राचीन संस्कृति और कलाकृतियों की कीमत जानते है।

पाक सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार से जुड़े नियमों पर बुधवार को सवाल उठाए। दरअसल, शीर्ष न्यायालय एक अहम मामले की सुनवाई कर रहा है जिसके नतीजे मौजूदा सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को और तीन साल इस पद पर रहने से रोक सकता है।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिए जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था। इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल का हवाला दिया था। बाजवा का मूल कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है। पाक सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने मंगलवार को एक अप्रत्याशित कदम के तहत कानूनी खामियों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश को निलंबित कर दिया था। बाजवा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका रियाज राही नाम के एक व्यक्ति ने दायर की है।

शीर्ष न्यायालय के मंगलवार के आदेश के बाद कैबिनेट ने सेना नियम एवं नियमन की धारा 255 में संशोधन किया और नियम में कानूनी खामी को दूर करने के लिए कार्यकाल में विस्तार शब्द शामिल किया। जियो न्यूज ने बताया कि खबरों के मुताबिक कैबिनेट ने दो बैठकों में कार्यकाल विस्तार का एक नया प्रारूप तैयार किया और इसे राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के पास मंजूरी के लिए भेजा। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने नई अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। पाक सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की।

पीठ में प्रधान न्यायाधीश खोसा, न्यायमूर्ति मियां अजहर आलम खान मियांखेल और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह शामिल हैं। बाजवा की पैरवी फारूग नसीम कर रहे हैं जिन्होंने इसके लिए कल कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। खबर में प्रधान न्यायाधीश के हवाले से कहा गया है, सेना प्रमुख के कार्यकाल का विषय बहुत अहम है। उन्होंने कहा, अतीत में, पांच या छह जनरलों ने खुद ही अपने कार्यकाल में विस्तार कर लिया। हम मामले पर करीब रूप से गौर करेंगे ताकि भविष्य में यह नहीं हो। यह अत्यधिक अहम विषय है और संविधान इस बारे में खामोश है। गौरतलब है कि पाकिस्तान सेना ने देश के 70 साल से अधिक के इतिहास में इसकी आधी से भी अधिक अवधि तक शासन की बागडोर संभाली है।

चीन सरकार हिरासत शिविरों में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रही है : अमेरिका

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि हाल में लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि चीन सरकार ने अशांत शिनजियांग प्रांत में मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों को क्रूरता से हिरासत शिविरों में बंद कर रखा है और वह उनका सुनियोजित तरीके से दमन कर रही है।

पोम्पिओ ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हिरासत शिविरों में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रही है। विदेश मंत्रालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पोम्पिओ ने कहा कि दुनियाभर के देश अब यह जान रहे हैं कि चीन में क्या हो रहा है। ए देश शिनजियांग में लोगों के लिए मानवाधिकारों के हालात में सुधार करने के वास्ते अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

पोम्पिओ ने चीन सरकार से उन सभी लोगों को फौरन रिहा करने का आह्वान किया जिन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया और साथ ही उससे अपनी कठोर नीतियों को भी खत्म करने को कहा है जिससे शिनजियांग में उसके अपने ही नागरिक भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार ने ईसाइयों, तिब्बतियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों का भी दमन किया।

पोम्पिओ ने कहा, हमने हाल फिलहाल में जारी हुए शिनजियांग पेपर्स देखे हैं। इनमें चीन सरकार की शिनजियांग में उइगरों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को क्रूर ढंग से हिरासत में लेने और उनके सुनियोजित दमन के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ए रिपोर्टें इस बात का सबूत है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रही है।

अमेरिका ने हांगकांग के लोगों को दी जिला परिषद चुनाव शंतिपूर्ण संपन्न होने पर बधाई

● इस अर्ध-स्वायत्त शहर में कई विरोध प्रदर्शनो के बाद हुए मतदान के परिणामों ने सभी को चौंका दिया है

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस सप्ताहांत हांगकांग में जिला परिषद चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के लिए वहां के लोगों को बधाई दी। पोम्पियो ने संवाददाताओं से कहा, हम हांगकांग के लोगों को 24 नवंबर को संपन्न हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण जिला परिषद चुनाव के लिए बधाई देते हैं। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों ने शहर की 452 सदस्ईय 18 जिला परिषदों में भारी जीत दर्ज कर शानदार बहुमत हासिल किया। इन सीटों पर चीन समर्थकों का दबदबा था।

इस अर्ध-स्वायत्त शहर में कई विरोध प्रदर्शनों के बाद हुए मतदान के परिणामों ने सभी को चौंका दिया है। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका हांगकांग में मौलिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्य और एक देश, दो प्रणाली व्यवस्था का समर्थन करता है।

हांगकांग में सुरंग फिर खुली, विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस की घेराबंदी खत्म होने की ओर

हांगकांग (एपी)। हांगकांग की एक प्रमुख सुरंग बुधवार को खुल गई। नजदीक के विश्वविद्यालय में हफ्तेभर से जारी पुलिस की घेराबंदी लगभग खत्म होने वाली है जिसके साथ ही चीन के क्षेत्र में लंबे समय से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों का हिंसक अध्याय समाप्त हो रहा है। हांगकांग को बाकी के शहरों से जोड़ने वाली क्रॉस हार्बर सुरंग दो हफ्ते से बंद थी। प्रदर्शनकारियों ने इसके प्रवेश मार्ग को मलबे से भर दिया था और इसे बंद कर दिया था। यही नहीं बल्कि उन्होंने पुलिस के साथ झड़प के दौरान टोल बूथों को आग लगा दी थी। विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष मिरांडा लोउ ने कहा कि तलाशी दलों ने हांगकांग पॉलीटेक्निक परिसर में लगातार दूसरे दिन खोजबीन की लेकिन उन्हें वहां किसी भी प्रदर्शनकारी के मौजूद होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। मंगलवार को एक युवती बहुत ही कमजोर हालत में वहां मिली थी। लोउ ने संवाददताओं को बताया कि विश्वविद्यालय के अधिकारी पुलिस को यह फैसला करने देंगे कि वह जांच करने के लिए परिसर में दाखिल होना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह घेराबंदी खत्म हो जाएगी। हालांकि पुलिस की ओर से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई है। परिसर कचरे से पटा हुआ है। पुलिस का कहना है कि कचरे में विस्फोटकों समेत खतरनाक सामग्री भी है। रविवार को लोकतंत्र समर्थक नेताओं की स्थानीय चुनाव में जीत के साथ पुलिस के परिसर से लौट जाने की मांग उठने लगी है।

राजनयिक मिशनों के मामले में पहले स्थान पर पहुंचा चीन: अध्ययन

भाषा। बीजिंग

चीन ने दुनियाभर में राजनयिक मिशनों के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और वह पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस तरह, अब चीन का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राजनयिक नेटवर्क हो गया है। वहीं, एशियाई देशों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है।

अध्ययन के मुताबिक भारत 123 दूतावासोंउच्चायोगों, 54 वाणिज्य दूतावासों और पांच स्थाई तथा चार अन्य मिशनों के साथ 12वें स्थान पर है। हालांकि, एशियाई देशों की बात करें तो भारत, चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर है। अध्ययन में कहा गया है कि बीजिंग ने विश्वभर में संपर्क स्थापित करने की अपनी कोशिशों के तहत यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सिडनी स्थित लोवी संस्थान के अनुसार 2019 में चीन के दुनियाभर में कुल 276 राजनयिक केन्द्र हैं, जो अमेरिका से तीन केन्द्र ज्यादा है।

चीन के दुनियाभर में 169 दूतावास, 96 वाणिज्य दूतावास, आठ स्थाई मिशन और तीन अन्य मिशन हैं। वहीं, अमेरिका के दुनियाभर में 168 दूतावास, 88 वाणिज्य दूतावास, नौ स्थाई और आठ अन्य मिशन हैं। चीन इस मामले में 2016 में अमेरिका और फ्रांस के बाद तीसरे स्थान पर था। 2017 में वह दूसरे स्थान पर आ गया। 2018 में इससे संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं आई।

दुनियाभर में चौथे स्थान पर मौजूद जापान के 151 दूतावास, 61 वाणिज्य दूतावास, दस स्थाई और 21 अन्य मिशन हैं। वहीं 85 दूतावासों और उच्चायोगों, 30 वाणिज्य दूतावासों और दो स्थाई मिशनों के साथ पाकिस्तान 28वें स्थान पर है। एशिया में उसका छठा स्थान है।

इज़राइल ने गाजा में हमास के ठिकानों को बनाया निशाना

एपी। यरूशलम

इजराइल ने बुधवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए। सेना ने गाजा पट्टी से इजराइली क्षेत्र में रॉकेट दागे जाने के जवाब में यह हमले किए।

इजराइली सेना ने कहा कि दक्षिणी गाजा पट्टी में इन हवाई हमलों में हथियार बनाने वाली एक इकाई समेत हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया।इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हर हमले का सख्ती से जवाब देने की चेतावनी दी थी जिसके बाद यह हवाई हमले किए गए। इजराइली बलों और फलीस्तीनी आतंकवादियों के बीच लगातार दो दिनों तक चले संघर्ष का जिक्र करते नेतन्याहू ने एक बयान में कहा था, अगर गाजा में किसी को लगता है कि वह ऑपरेशन ब्लैक बेल्ट के खिलाफ अपना सिर उठा सकते हैं तो यह उनकी गलतफहमी है। सेना ने मंगलवार को कहा, गाजा पट्टी से इजराइली क्षेत्र में दो रॉकेट दागे गए थे। इस सप्ताह में रॉकेट दाग कर संघर्षविराम तोड़ने की यह दूसरी घटना थी। इजराइल ने मंगलवार को एक अभियान में इस्लामी जिहाद के एक सर्वोच्च कमांडर की हत्या कर दी थी। इस हमले के तुरंत बाद इस्लामी जिहाद द्वारा इजराइल में सैंकड़ों की संख्या में जवाबी रॉकेट हमले किए गए। इसके बाद इजराइली सेना ने हमले किए जिसमे 16 आम नागरिकों समेत कुल 34 लोग मारे गए थे।

थाइलैंड के प्रधान मंत्री प्रथुथ चान-ओहाचा दक्षिण कोरिया के बुसान में बुधवार को फर्स्ट मेकोंग-रिपब्लिक ऑफ कोरिया समिट में एक संयुक्त प्रेस बयान के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ हाथ मिलाते हुए

किशोरों के बीच तनाव का संबंध सोशल मीडिया के इस्तेमाल से

भाषा। टोरंटो

एक हालिया अध्ययन के मुताबिक किशोरों में तनाव के लक्षण का संबंध सोशल मीडिया के इस्तेमाल, टेलीविजन देखने और कंप्यूटर के इस्तेमाल से हैं। कनाडाई जर्नल ऑफ साइक्रेट्री में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक गत चार साल में औसत से अधिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले, टीवी देखने वाले और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले किशारों में तनाव के गंभीर लक्षण देखे गए। कनाडा स्थित मांट्रियाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में पाया कि जब किशोरों ने सोशल मीडिया, टेलीविजन और कंप्यूटर के इस्तेमाल में कमी लाई तब उनमें तनाव के लक्षण भी कम हो गए। हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल और टेलीविजन देखने का संबंध अवसाद के लक्षणों से है। हालांकि, शोध में कंप्यूटर के इस्तेमाल से अवसाद के लक्षणों से संबंध स्थापित नहीं हो पाया। शोधकर्ताओं ने कहा कि लगता है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल का संबंध तनाव बढ़ने से है और संभवत: गृह कार्य की गतिविधियां कंप्यूटर से। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण असर हो सकता है, जैसे कैसे युवा और परिवार टीवी देखने या सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करें ताकि तनाव के लक्षणों को कम किया जा सके।

कड़ी प्रतिस्पर्धा में मौका मिलना आसान नहीं है : उमेश यादव

नई दिल्ली। उमेश यादव को पता है कि भारतीय तेज आक्रमण में चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा में मौका मिलना आसान नहीं है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि टीम से बाहर होने पर नकारात्मक विचारों और बोरियत से पार पाना मुश्किल होता है। उमेश को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से पहले भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था लेकिन जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के कारण उन्हें टीम में जगह मिल गई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट में 11 और बांग्लादेश के खिलाफ 12 विकेट लेकर मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि टीम से बाहर होने पर सकारात्मक बने रहना बहुत मुश्किल है। उमेश ने कहा कि जब आप बाहर होते तो वह समय काफी बोरियत भरा होता है तथा कुछ ऐसे विचार आपके दिमाग में घर करने लगते हैं जिनसे आप दूर रहना चाहते हो। मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं? क्या हो रहा है? खुद को सकारात्मक बनाए रखना, कड़ी मेहनत करना और खुद को तैयार रखना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि अगर मैं फिट रहा तो मुझे मौका मिलेगा क्योंकि हमने कई मैच खेलने हैं। आपको इंतजार करना होगा क्योंकि तेज गेंदबाजी आक्रमण वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तेज गेंदबाजी आक्रमण में बुमराह, इशांत शर्मा ओर मोहम्मद शमी भी शामिल हैं और यादव ने कहा कि वह इसमें फिट बैठते हैं तथा कार्यभार संबंधी प्रबंधन से सुनिश्चित है कि हर किसी को पर्याप्त मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी चार अब उस स्तर पर हैं जहां आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो कि एक समय में कौन तीन खेलेंगे। ऐसा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण है। मैं इसे बहुत अच्छी बात मानता हूं कि हम खिलाड़ियों को रोटेट कर रहे हैं क्योंकि इससे हम लंबे समय तक खेल में बने रहेंगे और अधिक मैच विजेता प्रदर्शन करेंगे। उमेश ने कहा कि जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा वह टीम का हिस्सा होगा। सबसे महत्वपूर्ण मौकों का पूरा फायदा उठाना है। जब मैं बुमराह, इशांत और शमी को देखता हूं तो उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। सीखना कभी रुकता नहीं है। यादव घरेलू परिस्थितियों में प्रभावशाली रहे हैं लेकिन विदेशों में वह गलतियां कर जाते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या उनके बारे में ऐसी राय सही है तो उन्होंने कहा कि इसमें वह कुछ नहीं कर सकते। इस तेज गेंदबाज ने कहा कि अमूमन जिन परिस्थितियों में आप अधिक खेलते हो आपको उनके बारे में अधिक पता होता है और आप अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल करते हो। हां मैं इस धारणा से सहमत हूं कि कोई खास गेंदबाज भारतीय या एशियाई परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर आप इंग्लैंड की परिस्थितियों में अधिक मैच खेलोगे तो वहां भी अच्छा प्रदर्शन करोगे। उपमहाद्वीप से बाहर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में मैंने बहुत कम मैच खेले हैं। मैंने केवल आस्ट्रेलिया में कुछ टेस्ट मैच खेले हैं। इसलिए शायद ऐसी धारणा बनी क्योंकि कम मैच का मतलब है कि आपके नाम पर विकेट भी कम होंगे।

चोटिल धवन बाहर, सैमसन को मौका

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित

भाषा। नई दिल्ली

सलामी बल्लेबाज शिखर धवन घुटने की चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 श्रृंखला से बाहर हो गए जिनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है। धवन को सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच के दौरान बाएं घुटने में चोट लगी थी।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने मंगलवार को उसकी चोट की समीक्षा की। उसे कुछ और समय आराम देने की सलाह दी गई है ताकि वह पूरी तरह से चोट से उबर जाए। इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने उसकी जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टी-20 मैच हैदराबाद में छह दिसंबर को खेला जाएगा। बाकी दो मैच तिरूवनंतपुरम (आठ दिसंबर) और मुंबई (11 दिसंबर) को होंगे। केरल के सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए टीम में रखा गया था लेकिन एक भी मैच खेले बिना बाहर कर दिया गया था। इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी और पूर्व खिलाड़ियों ने इस पर सवाल उठाए थे। 33 बरस के धवन वनडे श्रृंखला से पहले फिट हो सकते हैं।

हालिया खराब फार्म के कारण वह काफी दबाव में भी हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे श्रृंखला 15 दिसंबर से शुरू होगी। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों में धवन सिर्फ 91 रन ही बना सके। सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में भी वह कुछ खास नहीं कर सके। इस बीच बीसीसीआई ने कहा कि टेस्ट विकेटकीपर रिधिमान साहा के दाहिने हाथ की ऊंगली का आपरेशन हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ दिन रात के टेस्ट के दौरान साहा की ऊंगली में फ्रेक्चर हुआ था। बोर्ड ने कहा कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने हाथ और कलाई के विशेषज्ञ से सलाह ली।

उन्हें आपरेशन की सलाह दी गई थी। मुंबई में मंगलवार को उनका सफल आपरेशन हुआ। वह अब बेंगलुरू में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन कराएंगे। टी-20 टीम: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, संजू सैमसन।

साहा की ऊंगली का आपरेशन न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट तक फिट होने की उम्मीद

नई दिल्ली। भारत के टेस्ट विकेटकीपर रिधिमान साहा के दाहिने हाथ की ऊंगली में बांग्लादेश के खिलाफ दिन रात के टेस्ट के दौरान फ्रेक्चर हुआ था जिसका आपरेशन कराया गया है हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी में होने वाली दो मैचों की श्रृंखला में उनके फिट होने की उम्मीद है। 35 बरस के साहा का मंगलवार को मुंबई में आपरेशन हुआ। बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा , बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने हाथ और कलाई के विशेषज्ञ से सलाह ली। उन्हें आपरेशन के लिए कहा गया। मुंबई में मंगलवार को उनका सफल आपरेशन हुआ। अब वह जल्दी ही बेंगलुरू में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन कराएंगे। टीम प्रबंधन के करीबी सूत्र ने बताया कि साहा न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला तक फिट हो जाएंगे। वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में टेस्ट से पहले भारत को हैमिल्टन में तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलना है। इसके बाद पांच टी-20 और तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे। साहा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर में टेस्ट श्रृंखला के दौरान ऐसी ही चोट लगी थी लेकिन वह बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला से पहले ठीक हो गए थे। आईपीएल 2018 के दौरान उन्हें कंधे में चोट लगी थी जिसका उन्हें इंग्लैंड में आपरेशन कराना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत टीम में आ गए लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला में साहा को तरजीह मिली। साहा ने दिन रात के टेस्ट के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 100 शिकार पूरे किए।

अपने ऊपर गैरजरूरी दबाव बढ़ा रहे हैं ऋषभ पंत: प्रसाद

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद का मानना है कि ऋषभ पंत खुद को एमएस धोनी का उत्तराधिकारी मानकर अपने। प्रसाद ने कहा कि खराब फार्म से जूझ रहे इस खिलाड़ी को वापसी के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा का सहारा लेना चाहिए। अभी कुछ समय पहले तक पंत तीनों प्रारूपों में विकेटकीपिंग के लिए पहली पसंद थे लेकिन पिछले काफी समय से वह फार्म हासिल करने में विफल रहे हैं।

अनुभवी ऋद्धिमान साहा की चोट से वापसी के बाद वह टेस्ट टीम की अंतिम एकादश में जगह नहीं बना सके। सीमित ओवरों के प्रारूप में भी उनका बल्ला नहीं चल रहा और उन्होंने विकेट के पीछे भी लचर प्रदर्शन किया। टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने उनके आलोचकों से आग्रह किया कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें और उन्हें खुल कर खेलने दें, जबकि महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का कहना है कि जब भी वह भारत के लिए खेलेंगे तो दबाव होना तय है।

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि पुरुष हाकी विश्प कप 2023 के मुकाबले भुवनेश्वर और राउलकेला में आयोजित किए जाएंगे। इस महीने आठ तारीख को अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ ने भारत को 2023 हाकी विश्व कप की मेजबानी दी।

COURT NOTICE

MS. Bhavna Kalia,Metropolitan Mg, Room No.14, Patiala House Court, Order Date- 30/8/2019, Date of Issue- 1/10/2019, Next Date of Hearing- 30/11/2019 PROCLAMATION REQUIRING THE APPERANCE OF A PERSON ACCUSED (See Section 82), THOUG S.H.O, CC NO.- 6644/2017, TITLE- VIBHAKAR MISHRA VS. PANKAJ RAI, U/S- 138, P.S.- TILAK MARG Where as complaint has been made before me **pankaj rai, s/o Ravindra rai, near b.s.n.l. exchange N.H.-29, BHAMASHAH SCHOOL CIVIL LINE, BHUJAUTI, MAU DISTRICT MAU, U.P., PIN CODE 275101** has committed (or is suspected to have committed) the offence..... punishable under section.....**138 IN . ACT**.....of the Indian Penal Code, and it has been returned to a Warrant of arrest thereupon issued that the said **SH. PANKAJ RAI**....cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said **PANKAJ RAI**..... has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant).Proclamation is hereby made that the said **SH. PANKAJ RAI,**,.... of..... is required to appear **in this Court to answer the said complaint on the day of 30-11- 2019**

Publice Date-28/11/2019

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्
(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)
61–65, संस्थागत क्षेत्र, डी–ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

वॉक–इन–इंटरव्यू

केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। परिषद् निम्नलिखित अनुबंधित पदों की नियुक्ति हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू आयोजित कर रही है। योग्य उम्मीदवारों को वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए प्रत्येक पद के समक्ष दर्शित दिनांक एवं समय पर के.यू.चि.अ.प. मुख्यालय, 61–65, संस्थागत क्षेत्र, डी–ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, दिल्ली –110058 में आमंत्रित किया जाता है।

क्र. सं.	पदों के नाम	वॉक–इन–इंटरव्यू की तारीख	उपस्थिति का समय
1.	एसआरएफ/जेआरएफ (यूनानी)	06.12.2019	प्रातः 10:00 बजे
2.	प्रोफेसर (मोआलिजात)	06.12.2019	प्रातः 10:00 बजे
3.	रीडर (मोआलिजात)	06.12.2019	प्रातः 10:00 बजे
4.	रीडर (इल्मुल अदविया)	06.12.2019	प्रातः 10:00 बजे
5.	वरिष्ठ सलाहकार (तकनीकी)	06.12.2019	प्रातः 10:00 बजे

1. प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या, योग्यता की स्थिति, आयु सीमा, पारिश्रमिक, नियुक्ति का स्थान आदि का पूरा विवरण परिषद की वेबसाइट ***ccrum.res.in*** पर उपलब्ध है, ।
2. उम्मीदवारों की योग्यता विज्ञापन की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
3. आवश्यकता केवल छोटी अवधि के लिए है और नियुक्ति शुरू में छह महीने की अवधि के लिए होगी।
4. योग्य आवेदक निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा के साथ आयें, जिसे परिषद की वेबसाइट ***ccrum.res.in*** से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्हें मूल शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (पत्रों), के साथ एक सेट छायाप्रति और दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो भी लाएँ।
5. पहले से ही सेवारत उम्मीदवार अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' लाएँ।
6. किसी भी पद के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले योग्य उम्मीदवारों की संख्या 50 से अधिक होती है, तो उसी तिथि पर उम्मीदवारों की लघु–सूची के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, सीसीआरयूएम की ओर से

जनवरी तक कोई क्रिकेट नहीं: धोनी

मुंबई। महेंद्र सिंह धोनी से जब पिछले कुछ समय से बाहर रहने को लेकर सवाल किए गए तो इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सपाट शब्दों में कहा कि जनवरी तक मत पूछो। धोनी जुलाई में विश्व कप के बाद से नहीं खेल रहे हैं जिससे उनके संन्यास को लेकर भी अटकलबाजियां भी लगाई जाने लगी। यहां एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे धोनी से पूछा गया कि वह कब तक क्रिकेट से बाहर रहेंगे, उन्होंने कहा, जनवरी तक मत पूछो। इस पूर्व कप्तान के एक करीबी सूत्र ने मंगलवार को कहा था कि वह अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद अपने भविष्य को लेकर फैसला करेंगे।

कार्यालय ग्राम पंचायत पिपलैड़ा विकास खण्ड–धौलाना, हापुड़

पत्रांक मी0मो0/निविदा प्रकाशन/ग्रा0पअ0/2019–2020 दिनांकः– 26.11.2019

–: अल्पकालीन निविदा सूचना :–

ग्राम पंचायत द्वारा राज्य वित्त/चौहदवा वित्त योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो के लिये पंजीकृत ठेकेदारो से बन्द निविदायें दिनांक 07.12.2019 की सॉय 2.30 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 06.12.2019 तक कार्यालय समय में सम्बन्धित ग्राम पचांयत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्ति किये जा सकते है। निविदा अधिकृत अधिकारीयो द्वारा इच्छुक ठेकेदारो की उपस्थिति मे दिनांक 07.12.2019 को सॉय 3.00 बजे खोली जायेगी।

क्र0 स0	कार्य का नाम	कार्य का स्थल	अनु.लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण होने की अवधि
1.	इण्टरलाकिंग	यासीन डा0 मूदअली की गली	117500	2350	100	2 माह
2	"	उमरी से फजल तक	176400	3528	200	"
3	"	मुन्शी इरफान से मदीना मस्जिद	392300	7846	400	"
4	नाली निर्माण	मुन्शी इरफान से मदीना मस्जिद	134800	2696	100	"
5	नाली व मिटटी	छिद्या से हाफिज कदीर तक	329400	6588	300	"
6	नाला सफाई"	विभिन्न स्थानों पर	200,000	4000	200	"
7	पुलिया निर्माण	विभिन्न स्थानों पर	199,500	3990	200	"
8	इण्टरलाकिंग	इस्तेकार से जमालुद्दीन तक	201500	4030	200	"
9	नाली व मिटटी कार्य	डा0 जाहिद से डा0 फरमान तक	187800	3756	200	"
10	L. E. D. लोहर	विभिन्न स्थानों पर	500000	10,000	500	"
11	नाली व इण्टरलाकिंग	गुलफाम से सहीस तक	281,100	5622	300	"
12	इण्टरलाकिंग	साबर से हाजी बुन्दुतक	191135	9823	500	"
13	"	कलूवा से खिलाफत तक	331200	6624	300	"
14	"	खिलाफत से भूड़ गढी तक	33,200	6624	300	"

नियम व शर्तें:–

1. अरनेस्ट मनी निविदा डालने के समय एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/पास बुक के रूप मे दी जा सकती है सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नाम से बन्धन हो अथवा नकद जमा की जा सकती हैं।
2. कार्य पी0डब्लू0डी0 की विशिष्टियो के अनुरूप होगा
3. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को होगा।
4. निविदा केवल सरकारी विभाग मे पंजीकृत ठेकेदारो को ही देय होगी।
5. ठेकेदार का पंजीयन उप श्रमायुक्त हापुड़ के यहा होना चाहिए तथा ठेकेदार को प्रत्येक कार्य का पंजीकरण उप श्रमायुक्त कार्यालय हापुड़ में कराना अनिवार्य होगा।
6. निविदा प्रपत्र के साथ 100/– का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रसीदी टिकिट के साथ लाने।
7. नियमानुसार सभी शासकीय कटौतिया की जायेगी।
8. अन्य नियम व शर्तें लागू रहेंगी।

प्रधान
ग्राम पंचायत पिपलैंड़ा
वि0ख0 धौलाना जनपद हापुड़

सचिव
ग्राम पंचायत पिपलैंड़ा
वि0ख0 धौलाना जनपद हापुड़

डे-नाइट टेस्ट : पाकिस्तान के खिलाफ आस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहेगा

एएफपी। एडीलेड

पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में आस्ट्रेलिया का पलड़ा भार होगा लेकिन मेजबान का कहना है कि दिन-रात के टेस्ट में आत्ममुग्धता से बचना होगा। आस्ट्रेलिया ने पिछले सप्ताह ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट चार दिन के भीतर एक पारी और पांच रन से जीता था। एडीलेड पर हालांकि शुक्रवार से शुरू होने वाला मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। आस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने कहा कि मैच में ऐसा समय आएगा जब दिन रात का होने के कारण इसमें फर्क महसूस होगा। उन्होंने कहा कि हर कोई इसे लेकर बेकरार है लेकिन हमें पता है कि इसमे हालात अलग होंगे।

आस्ट्रेलिया ने गुलाबी गेंद से सभी पांच टेस्ट जीते हैं। इनमें से तीन एडीलेड में खेले गए जिनमें मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस की तेज तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। आस्ट्रेलियाई अंतिम एकादश में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है हालांकि एक घरेलू मैच में गाली गलौच के कारण निलंबन झेलने वाले तेज गेंदबाज जेम्स पेटिंसन चयन के लिए उपलब्ध हैं। पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट में सकारात्मक बात बाबर आजम का शतक और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के 95 रन रहे। पहली पारी में पाकिस्तानी टीम कोई कमाल नहीं कर सकी और उसके युवा तेज गेंदबाज आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने पहले मैच में 16 बरस के तेज गेंदबाज नसीम शाह को उतारा जिसने डेविड वार्नर का विकेट लिया। पाकिस्तानी टीम अगर उसे आराम देती है तो 19 बरस के मूसा खान को शामिल किया जा सकता है।

आस्ट्रेलियाई क्रिकटरों ने ह्यूज को याद किया

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया ने क्रिकेट के मैदान पर एक बाउंसर लगने के कारण पांच साल पहले अपनी जान गंवा चुके दिवंगत क्रिकेटर फिलीप ह्यूज को श्रृद्धांजलि दी जबकि पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन खेल अप्रासंगिक हो गया था। ह्यूज को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान सिडनी में सीन एबोट का बाउंसर लगा। अपने 26वें जन्मदिन से तीन दिन पहले उनका निधन हो गया। स्मिथ ने कहा कि वह केयरफ्री सप्ताह था, अगर क्रिकेट की बात करें। उस समय लगा कि क्रिकेट अप्रासंगिक हो गया। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातें अक्सर याद आती रहती हैं। इससे उसकी याद आती है। ऐसा बार बार होता है। पूर्व कप्तान और ह्यूज के करीबी दोस्त माइकल क्लार्क ने कहा कि मैं रोज तुम्हें याद करता हूं लेकिन आज बहुत याद आ रहा हूं।काश तुम यहां होते दोस्त। क्लार्क ने ह्यूज की अर्थी को कंधा भी दिया था। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन राबटर्स ने कहा कि ह्यूज आस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने परिवार को समर्पित व्यक्ति, वफादार दोस्त, लोकप्रिय साथी और बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर।

न्यूजीलैंड दौरे के बीच से लौटेंगे इंग्लैंड के कोच

वेलिंगटन। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड परिवार में शोक होने के कारण न्यूजीलैंड दौरा बीच में से छोड़कर लौटेंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि सिल्वरवुड शनिवार को रवाना होंगे जबकि दूसरा टेस्ट हैमिल्टन में शुक्रवार से खेला जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि सहायक कोच ग्राहम थोर्प और पाल कोलिंगवुड टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंग्लैंड को पहले मैच में न्यूजीलैंड ने एक पारी और 65 रन से हराया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने बताया कि माउंट मोउंगानुइ में खेले गए मैच में एक दर्शक ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की थी।

इंग्लैंड के स्टार हरफनमौला बेन स्टोक्स ने कोच के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि परिवार सबसे पहले आता है। आप दुनिया में कहीं भी हों या टीम किसी भी हालत में हो। उन्होंने मुझसे राय मांगी और मैने कहा कि आपको घर जाना चाहिए। अभी यह पता नहीं चला है कि सिल्वरवुर के परिवार में किसका निधन हुआ है।

नार्दर्न प्रोविन्स के गवर्नर नियुक्त होंगे दिग्गज स्पिनर मुरलीधरन

कोलंबो। श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन जल्द ही देश के तमिल बहुल क्षेत्र नार्दन प्रोविन्स के गवर्नर के रूप में एक अलग तरह की पारी शुरू कर सकते हैं। मीडिया की बुधवार की रिपोर्टों के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने उन्हें इस पद को स्वीकार करने के लिए निजी तौर पर निमंत्रण भेजा है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 800 विकेट लेने वाले 47 वर्षीय मुरलीधरन उन तीन नए गवर्नर में शामिल हैं जिनको राजपक्षे ने इस पद के लिए चुना है। डेली मिरर समाचार पत्र ने राष्ट्रपति सचिवालय के सूत्रों के हवाले से कहा, राष्ट्रपति गोटवाया राजपक्षे ने मुरलीधरन को नार्दर्न प्रोविन्स का गवर्नर पद संभालने के लिए निजी तौर पर आमंत्रित किया है। मुरलीधरन ने मार्च 2005 में चेन्नई की रहने वाली मधिमलार राममूर्ति से शादी की थी। उन्होंने 2010 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

पीसीबी ने दक्षिण अफ्रीका को तीन टी-20 मैचों का न्यौता दिया

कराची। पाकिस्तान ने अगले साल तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका को देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को अगले साल भारत के खिलाफ वनडे श्रृंखला के बाद पाकिस्तान का दौरा करने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें पाकिस्तान का दौरा करने और तीन टी-20 मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया है और उनका रवैया अच्छा है। अगर दक्षिण अफ्रीका दौरा करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका आयोजन पाकिस्तान सुपर लीग के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में हो सकता है।

स्कीट क्वालीफायर्स के पहले दिन तीन परफेक्ट राउंड बना

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के ओलंपियन मैराज अहमद खान, ओएनजीसी के समित सिंह और पंजाब के गुरजोत सिंह ने राष्ट्रीय शाटगन चैंपियनशिप में स्कीट निशानेबाजी क्वालीफायर्स के पहले दिन बुधवार को यहां तीन राउंड में परफेक्ट स्कोर बनाया। मैराज, समित और गुरजोत ने पुरुष स्कीट में पहले दौर राउंड में 25 में से 25 का स्कोर बनाया और वे 110 निशानेबाजों में शीर्ष पर हैं। पंजाब के गुरनिहाल सिंह गार्चा पुरुषों के जूनियर वर्ग में बढ़त पर हैं। उनका दो दौर का स्कोर 49 है। पंजाब की गनिमत शेखों सीनियर महिला और जूनियर महिला दोनों वर्गों में 48 के स्कोर के साथ बढ़त पर हैं। उन्होंने पहले दौर में 25 सही निशाने लगाए लेकिन दूसरे दौर में दो निशाने चूक गई। गुरुवार और शुक्रवार को भी क्वालीफाईंग के दो-दो दौर होंगे जिसके बाद फाइनल्स होगा जिसमें चोटी के छह निशानेबाज जगह बनाएंगे।

ग्रेग चैपल की जगह जार्ज बेली आस्ट्रेलिया क्रिकेट के चयनकर्ता बने

सिडनी। आस्ट्रेलिया के पूर्व टी-20 कप्तान जार्ज बेली को ग्रेग चैपल की जगह तीन सदस्यीय राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति में चुना गया। समिति में ट्रेवर होंस और कोच जस्टिन लैंगर भी हैं। बेली ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं कि इतने साल बतौर खिलाड़ी योगदान दे सका। अब मेरे पास चयनकर्ता के रूप में योगदान देने का मौका है। उन्होंने आस्ट्रेलिया के लिए पांच टेस्ट, 90 वनडे और 30 टी-20 मैच खेले हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वह तस्मानिया, होबर्ट हरिकेंस और मेलबर्न स्टार्स के लिए खेले।

कॉर्नवाल ने अफगानिस्तान को सस्ते में समेटा

187 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने दो विकेट के नुकसान पर 68 रन बनाए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कॉर्नवाल ने शानदार गेंदबाजी करके 75 रन खर्चकर सात विकेट चटकाए

आफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल की बलखाती गेंदों के आगे अफगानिस्तान की पहली पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में मात्र 187 रनों पर सिमट गयी। जवाब में वेस्टइंडीज ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय दो विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए है। जान कैम्पबेल 30 रन और शमार्ह ब्रुक्स 19 रन बनाकर नाबाद लौटे। अटल बिहारी स्टेडियम में टास हारकर पहले बल्लेबाजी उतरी अफगानिस्तान के बल्लेबाज कॉर्नवाल की फिरकी के आगे बेबस नजर आए। इस भारी भरकम गेंदबाज ने अफगानिस्तानी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर डाला और पूरी टीम महज 187 रन पर आउट हो गई। कॉर्नवाल ने शानदार गेंदबाजी करके 75 रन पर सात विकेट चटकाए। जवाब में कैरेबियाई टीम की शुरुआत भी खराब रही और उसके दोनों सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट (11) और शाई होप (07) 34 रन के टीम स्कोर पर अमीर हमजा और राशिद खान का शिकार हुए।

इससे पहले अफगानिस्तान की सलामी जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत करते हुए 12.2 ओवर में 28 रन जोड़े। इसी स्कोर पर इब्राहीम जादरान (17) आफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल की गेंद पर कैच आउट हुए। उसके बाद जावेद अहमदी और इहसानउल्ला ने पारी को आगे बढ़ाया और दूसरे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अहमदी (39) का ध्यान भटका और वह जोमेल वारिकन (35 रन पर एक विकेट) का शिकार बन गए। महज 111 रन पर सात विकेट खो चुके अफगानिस्तान की हालत और खराब होती अगर विकेटकीपर बल्लेबाज अफसर जजई (32) और अमीर हमजा (34) ने सातवें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी नहीं की होती। कॉर्नवाल ने जादरान के अलावा रहमत शाह (04), असगर अफगान (04), इहसानउल्ला (24), अफसर जाजाई (32), नासिर जमाल (02) और यामीन अहमदजई (18) को पवेलियन भेजा। कप्तान जेसन होल्डर ने भी दो बल्लेबाजों को चलता किया।

स्कोर बोर्ड

अफगानिस्तान (पहली पारी) : इब्राहीम जादरान का होल्डर बो. कार्नवाल 17, जावेद अहमदी का. ब्रुक्स बो. वारिकन 39, इहसानउल्ला का. होप बो. कार्नवाल 24, रहमत शाह का. होल्डर बो. कार्नवाल 04, असगर अफगान का. डोरिच बो. कार्नवाल 04, नासिर जमाल का. होप बो. कार्नवाल 02, अफसर जजई पगबाधा बो. कार्नवाल 32, राशिद खान का. कार्नवाल बो. होल्डर 01, अमीर हमजा का. डोरिच बो. होल्डर 34, यामीन अहमदजई का. वारिकन बो. कार्नवाल 18, जहीर खान नाबाद 00

अतिरिक्त :12

कुल : 68.3 ओवर में : 187 पर सभी आउट

विकेट पतन: 1-28, 2-84, 3-90, 4-91, 5-95, 6-98, 7-111, 8-165, 9-187, 10-187

गेंदबाजी: केमार रोच 8-1-33-0, जेसन होल्डर 17-10-22-2, रहकीम कार्नवाल 25.3 5-75-7, जोमेल वारिकन 13-1-35-1, रोस्टन चेज 5-0-10-0

वेस्टइंडीज : पहली पारी- क्रेग ब्रेथवेट पगबाधा बो. हमजा 11, जान कैम्पबेल नाबाद 30, शाई होप का. इहसानउल्ला बो. राशिद 07, शमार्ह ब्रुक्स नाबाद 19

अतिरिक्त: 1

कुल: 22 ओवर में दो विकेट पर : 68 रन

विकेट पतन: 1-27, 2-34

गेंदबाजी: यामीन अहमदजई 4-1-9-0, अमीर हमजा 8-1-25-1, राशिद खान 8-2-24-1, जहीर खान 2-0-10-0

नाबाद लौटते वेस्टइंडीज के जान कैम्पबेल और शमार्ह ब्रुक्स

सही लाइन से गेंदबाजी की रणनीति रही कारगर : कॉर्नवाल

लखनऊ। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में सात विकेट झटकने वाले वेस्टइंडीज के आफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल ने कहा कि उन्हें सही लाइन से गेंदबाजी करने के कारण सफलता मिली। कॉर्नवाल ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि सही लाइन से गेंदबाजी करने से ही उन्हें सात विकेट लेने में कामयाबी मिली। अपने दूसरे ही टेस्ट में 75 रन देकर सात विकेट झटकने वाले इस आफ स्पिनर ने कहा कि कप्तान जेसन होल्डर ने उनसे कहा था कि लंच से पहले उन्हें अफगानिस्तान के कुछ विकेट लेने हैं। इस कामयाबी में चुस्त क्षेत्ररक्षण से भी खासी मदद मिली। इस साल भारत के खिलाफ अपने पहला टेस्ट खेलने वाले कॉर्नवाल ने कहा कि पदार्पण टेस्ट से अब तक मेरी गेंदबाजी में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। उधर, अफगान पारी में सर्वाधिक 34 रन बनाने वाले अमीर हमजा ने कहा कि जब वह आठवें नम्बर पर बल्लेबाजी करने आए थे, तब तक विकेट काफी धीमा हो चुका था। इसलिए उन्होंने सीधे बल्ले से खेलने की रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि अफगान बल्लेबाजों ने कुछ गलतियां कीं। लंच के बाद गेंद काफी उछाल और टर्न ले रही थी। कोच ने हमसे कहा कि हम छोटीछोटी साझीदारी करके पारी को आगे बढ़ाएं। हमने वही ही कोशिश की। हमजा ने कहा कि कॉर्नवाल की आर्म बॉल काफी मारक थी। उनकी लम्बाई की वजह से उनकी गेंद को काफी उछाल भी मिल रहा था। उन्होंने कहा कि हम मैच के दूसरे दिन स्थितियों को अपने माफिक करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम टॉस जीतते तो भी बल्लेबाजी ही चुनते।

गत चैंपियन समीर उलटफेर के शिकार

मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन

श्रीकांत, प्रणीत और मारिन दूसरे दौर मे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गत चैंपियन समीर वर्मा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हारकर बाहर हो गए हैं वहीं तीसरी वरीयता प्राप्त भारत के के. श्रीकांत, चौथी वरीय बी.साई प्रणीत और कैरोलिना मारिन ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है।

पहले दिन टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब पिछली बार के पुरुष सिंगल्स चैंपियन समीर वर्मा अनुभवी अजय जयराम का शिकार हो गए। अजय जयराम ने एक घंटा दो मिनट चले मैराथन मैच को 15-21, 21-18, 21-13 से जीता। अजय जयराम ने पूरे मैच में शानदार कोर्ट कवरेज के सहारे समीर वर्मा को खूब परेशान किया। पहला गेम समीर 15-21 से जीता। दूसरे गेम में अजय जयराम ने अपने अनुभव के सहारे अंक जुटाते कड़ी टक्कर के बाद 21-18 से जीत दर्ज की। तीसरे व निर्णायक गेम भी अजय जयराम ने 21-13 से अपने नाम करने के साथ मैच में जीत दर्ज की। वहीं समीर के भाई सौरभ वर्मा ने कनाडा के झियाडांग शेंग को 21-11, 21-16 से मात देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। टूर्नामेंट में तीसरी वरीय भारत के के. श्रीकांत ने रूस के ब्लादीमिर माल्कोव को 36 मिनट तक चले मैच में सीधे गेम में 21-12, 21-11 से हराया। श्रीकांत की अब दूसरे दौर में मुकाबला हमवतन पी. कश्यप से टक्कर होगी। कश्यप को पहले दौर में फ्रांस के लुकास कॉर्वी से वॉकओवर मिला।

18 साल के लक्ष्य सेन भी एकल के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। लक्ष्य को फ्रांस के थामस रासेल ने वाकओवर दिया। महिला वर्ग में चौथी वरीय ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलीना मारीन ने बुल्गारिया की लिंडा को 32 मिनट चले मुकाबले में आसानी से 21-16, 21-11 से हराया।

वहीं टूर्नामेंट का पहला मैच ही उलटफेर का गवाह बना जिसमें पुरुष एकल में टाप सीड चीन के शी यू की को हार का सामना करना पड़ा। इस चीनी खिलाड़ी को गैर वरीय मलेशिया के शो तेक झी ने 25-23, 21-17 से हराया। पुरुष एकल में चीन के ली शी फेंग ने भारत के एचएस प्रणय को 21-13, 16-21, 21-19 से हराया।

पुरुष एकल में चौथी वरीय बी. साई प्रणीत ने मलेशिया के इस्कंदर जुल्करनैन को 47 मिनट चले मुकाबले में 21-16, 22-20 से मात दी। महिला युगल के पहले दौर में में आठवीं वरीय अश्विनी और एन सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने हांगकांग की एनजी यायू और युएन सिन यिंग को 56 मिनट तक चले मैच में 21-13, 16-21, 21-19 से हराया।

क्रिकेटर द्रविड़ ने उठाया बैडमिंटन का लुत्फ

लखनऊ। यूपी बैडमिंटन अकादमी में चल रही सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप को देखने दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ पहुंच। उस समय के. श्रीकांत की टक्कर रूस के ब्लादीमिर माल्कोव से हो रही थी। कुछ लोग समझे कि थे ये बैडमिंटन के कोच है, लेकिन तभी किसी ने आवाज लगायी ये तो टीम इंडिया की दीवार राहुल द्रविड़ है। उसके बाद एकाएक यहां का नजारा ही बदल गया और वहां पर मौजूद बैडमिंटन के शौकीन भी इससे अछूते नहीं रहे. इसके बाद छोटे-छोटे बच्चे उनके पास पहुंच फोटो खिंचवाने की ललक दिखाने लगे। वहां मौजूद खेल प्रेमियों ने उनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करनी शुरू कर दी।

अभिषेक वर्मा व ज्योति सुरेखा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता

एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप

भाषा। बैंकाक

अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेख वेन्नाम की मिश्रित युगल भारतीय जोड़ी ने 21वें एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप में बुधवार को यहां कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया जिससे देश कुल पदकों की सात पदकों के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। वर्मा और ज्योति को जोड़ी ने चीनी ताइपै की यि-ह्सुआन चेन और चीह-लुह चेन की जोड़ी को 158-151 से हरा का भारत के लिए पहला सोने का तमगा जीता। टूर्नामेंट में भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत के साथ चार कांस्य पदक हासिल किए। इससे पहले वर्मा टीम स्पर्धा में सटिक निशाना लगाने से चूक गए जिससे भारतीय टीम को कोरिया के खिलाफ एक अंक से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कोरिया ने यह मुकाबला 233-232 के अंतर से जीता। वर्मा ने कहा कि तेज हवा के कारण परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल थी लेकिन हमारे पास स्वर्ण जीतने का यह आखिरी मौका था। हम इसमें सफल हुए। यह पूरी टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। ज्योति ने कहा कि मैं इस स्कोर से खुश हूं। इससे पहले के मैचों में भी हम ने निरंतर प्रदर्शन किया है। पुरुष टीम स्पर्धा में शीर्ष वरीय वर्मा, रजत चौहान और मोहन भाद्वाज की भारतीय तिकड़ी ने पहले दौर में 58 अंक बनाए। कोरिया के जेइवॉन यांग, यांगही चोइ और ईयून-क्यू चोई ने भी इतने ही अंक बनाए। दूसरे दौर में कोरियाई टीम ने भारतीय टीम से एक अंक की बढ़त हासिल की। भारतीय खिलाड़ियों को तीसरे दौर के आखिरी तीन निशाने नौ-नौ अंक का लगाए जो टीम को भारी पड़ा और कोरियाई टीम ने तीन अंक की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। अंतिम दौर में कोरिया के 57 अंक के मुकाबले भारत ने 59 अंक बनाए लेकिन यह जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। ज्योति, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर की भारतीय महिला टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर सकी और कोरिया के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में 231-215 से हार गई। भारतीय तीरंदाजी महासंघ के निलंबन के कारण टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी विश्व तीरंदाजी संघ के ध्वज तले खेल रहे है। उन्हें यह मौका इस लिए दिया गया ताकि वे गुरुवार को होने वाले ओलंपिकक्वालीफिकेशन प्रतियोगिता में भाग ले सके। पुरुष टीम ने पहले ही विश्व चैम्पियनशिप से ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है जबकि महिला टीम इस यहां कोटा हासिल करने की कोशिक करेगी। यहां से तोक्यों के लिए छह ओलंपिक कोटे हासिल किए जा सकते है।

मुंबई-नार्थईस्ट का मैच ड्रा पर छूटा

गुवाहाटी। मुंबई सिटी एफसी ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के छठे सत्र में मेजबान नार्थईस्ट युनाइटेड एफसी को बुधवार को यहां उसके घरेलू मैदान पर 2-2 गोल की बराबरी पर रोक दिया। इस ड्रा मैच से हालांकि दोनों टीमों को तालिका में अपने स्थान में सुधार करने का मौका मिला। नार्थईस्ट युनाइटेड चौथे जबकि मुंबई की टीम सातवें स्थान पर पहुंच गई। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच के चारों गोल पहले हाफ में हुए जबकि दूसरे हाफ में किसी भी टीम को सफलता नहीं मिली। दूसरे हाफ में हालांकि मुंबई मेजबान टीम पर भारी रही लेकिन नार्थईस्ट उसे गोल करने से रोकने में सफल रहा। मैच की पहली सफलता मेजबान टीम को मिली। नौवें मिनट में ही पानागियोतिस त्रियादिस ने मुंबई की खराब डिफेंस का फायदा उठाते हुए गोल कर नार्थईस्ट को 1-0 से आगे कर दिया। यूनान के इस खिलाड़ी ने दाएं कोने से बेहतरीन कोण बना गेंद को पोस्ट को बाएं कोने में डाल दिया।

स्कूलों को तकनीकी मूल्यांकन कर फिटनेस पर रिपोर्ट कार्ड देने का सुझाव

नई दिल्ली। खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को सभी स्कूलों से कहा कि वे अपने छात्रों का तकनीकी मूल्यांकन कर फिटनेस रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। रीजीजू ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के द्वारा शुरु किए गए फिटनेस सप्ताह कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय विद्यालय में आयोजित फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल हुए। रीजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के बाद, फिटनेस गतिविधियों के अवलोकन पर केन्द्रीय विद्यालयों से मुझे जो रिपोर्ट कार्ड मिला है वह सभी स्कूलों में सबसे अधिक उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में फिटनेस के लिए एक तकनीकी मूल्यांकन और एक प्रगतिशील रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए क्योंकि यह एक छात्र के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने बच्चों को फिट देखना चाहते हैं। फिट बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं।

डोपिंग मामले रूस ने जताया खेद सहयोग के लिए तैयार हुआ

एएफपी। मास्को

क्रेमलिन ने डोपिंग मामले में देश के एथलीटों पर चार साल के प्रस्तावित प्रतिबंध पर बुधवार को खेद जताते हुए कहा कि वह सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा कि यह चिंताजनक है। हमें इस पर खेद है। वाडा की समीक्षा समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में रूस पर चार साल के प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। पेस्कोव ने कहा कि रूसी खेल अधिकारी पहले भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और वाडा की मदद के लिए तैयार थे और आगे भी रहेंगे। वाडा प्रमुख अगर समीक्षा समिति के सुझाव मान लेते हैं तो रूस को टोक्यो ओलंपिक 2020 समेत अहम खेल टूर्नामेंटों से बाहर रहना होगा। डोपिंग प्रकरण पिछले पांच साल से रूस की साख पर दाग बना हुआ है। पहले यह खुलासा हुआ था कि सोच्चि में 2014 के शीतकालीन ओलंपिक में रूसी खिलाड़ी सरकार द्वारा प्रायोजित डोपिंग में लिप्त थे।

रूस पर प्रतिबंधों का यूरो और चैम्पियंस लीग पर असर नही पड़ेगा: वाडा

डसेलडोर्फ (जर्मनी)। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) रूस को चार साल के लिए सभी खेलों से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया है लेकिन इस वैश्विक इकाई ने इस बात की पुष्टि की कि रूस में अगले साल यूरोपीय चैम्पियनशिप फुटबाल (यूएफा) की मेजबानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। डोपिंग रिकार्ड के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर वाडा की अनुपालन समीक्षा समिति ने रूस के लिए प्रतिबंधों को एक पैकेज के रूप में प्रस्तावित किया है। वाडा के कार्यकारी बोर्ड की इस सिफारिश पर नौ दिसंबर को मतदान होगा। वाडा के प्रवक्ता जेम्स फिटजेराल्ड ने एपी को ईमेल के बताया कि जहां तक यूएफा या यूरो का संबंध है तो यह बहु-खेल या विश्व चैम्पियनशिप नहीं है। यह एक क्षेत्रीय । महाद्वीपीय एकल-खेल आयोजन है। इसलिए यह इस सिफारिश से प्रभावित नहीं होगा। सेंट पीटर्सबर्ग एक क्वार्टरफाइनल सहित चार मैचों की मेजबानी करने के कारण है। चैंपियंस लीग 2021 का फाइनल भी इसी शहर में खेला जाएगा।

गर्दन में चोट के बाद 'सायना' की शूटिंग को वापस लौटीं परिणीति

मुंबई (भाषा)। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल के जीवन पर आधारित अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करेंगी। गर्दन में चोट के चलते उन्होंने 10 दिनों तक शूटिंग से छुट्टी ली थी। परिणीति को गर्दन और रीढ़ की हड्डी के आसपास दर्द के चलते चिकित्सकों ने कम से कम एक सप्ताह बैडमिंटन नहीं खेलने की सलाह दी थी। अभिनेत्री को बुधवार को फिल्म की शूटिंग करनी थी, जिसमें उन्हें आठ घंटे तक बैडमिंटन खेलना था। परिणीति ने एक बयान में कहा, "हां, यह बात सही है। अब मैं सौ फीसदी स्वस्थ हूं और मैं बैडमिंटन कोर्ट में आने और दोबारा खेलने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपनी फिल्म सायना की पूरी टीम और चिकित्सकों की टीम को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूं, जिनकी वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक होकर कोर्ट में वापस लौट आई।

प्रकाश झा निर्देशित वेब श्रृंखला में नजर आएंगे बॉबी और चंदन सान्याल

मुंबई। अभिनेता चंदन रॉय सान्याल ने बुधवार को घोषणा की कि वह प्रकाश झा द्वारा निर्देशित अगली वेब-श्रृंखला में दिखाई देंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अभिनेता ने बताया है कि इस शो में बॉबी देओल भी होंगे। उन्होंने कहा, वेब अभिनेताओं और निर्देशकों के लिए नए विषय और तरीकों को जानने का बेहतरीन मंच है। इस नई वेब-श्रृंखला के साथ मुझे अपने पसंदीदा निर्देशकों में से एक प्रकाश झा के साथ काम करने का मौका मिलेगा। चंदन ने एक बयान में कहा, शो की कहानी अनूठी और दिलचस्प है। प्रकाश सर और बॉबी देओल के साथ काम करना अद्भुत होगा। मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपको हम सभी का एक अलग पक्ष देखने को मिलेगा। चंदन के हाल ही में फिल्म जबरिया जोड़ी और वेब-सीरीज़ भ्रम और हवा बदले हस्सू में अभिनय किया है।उनकी हालिया बांग्ला फिल्म, उड़ोजहाज उर्फ द फ्लाइट को कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था जिसकी दर्शकों ने सराहना की थी।

एक्शन करने के लिए टॉम क्रूज की उम्र ज्यादा: उपन्यासकार ली चाइल्ड

लॉस एंजेलिस। बेस्टसेलर किताब 'जैक रीचर' सीरीज के उपन्यासकार ली चाइल्ड का मानना है कि एक्शन करने के लिए सुपरस्टार टॉम क्रूज की उम्र अब ज्यादा है। क्रूज अब तक बनी दो जैक रीचर फिल्मों में अपने एक्शन का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने 'नाइट एंड डे', 'टॉप गन', 'एज ऑफ टुमारो' और 'मिशन: इम्पॉसिबल' फिल्मों में भी शानदार एक्शन किए हैं। खबर के मुताबिक, ली ने एक साक्षात्कार में कहा, 'यह काफी निराशानजक लगता है लेकिन मेरा मानना है कि यह उनके लिए अच्छा है। इस काम के लिए उनकी उम्र ज्यादा है। वह 57 साल के हैं। उन्हें आगे बढ़कर एक चरित्र अभिनेता के रूप में खुद को ढालने की जरूरत है।'

'हमारे गानों की कोई सीमा नहीं है'

म्यूज़िक बैंड **'इंडियन ओशन'** के सदस्यों से एक विशेष बातचीत में पायनियर संवाददाता **मुज़्बा हाशमी** ने उनके और उनके संगीत के बारे में विस्तार से जाना। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश–

जब हम इंडियन ओषन का उल्लेख करते हैं तो आपको क्या ध्यान आता है? आपके मस्तिष्क में क्या विष्व के तीसरे सबसे बड़े नीले समुद्र का ध्यान आता है या फिर फ्यूज़न रॉक संगीत विधा के अग्रणी एक बैंड का? जी हां, आपने सही जाना। हम बात कर रहे हैं उस म्यूज़िक बैंड की जो वर्ष 2020 की फरवरी में अपने अस्तित्व के 30 साल पूरे करेगा। आज भी उनके बैंड की भावना उतनी ही युवा है जितनी आज से 30 साल पहले उसकी स्थापना के समय हुआ करती थी।

इसी बैंड ने हमें बंदे, देश मेरा, कंदीसा और तू किसी रेल सी... जैसे गाने हमें दिये हैं जिसे मासूम फिल्म में स्थान नहीं मिल सकता लेकिन स्थिति ये है कि आज इसी गाने को सर्वाधिक सुना जाता है।

इंडियन ओशन के सह संस्थापक राहुल राम हंसते हुए बताने लगते हैं, 'मूल रूप में फिल्म के लिए ये गाना गाने के लिए मुझसे कहा गया था लेकिन फिल्म निर्माताओं को मेरे द्वारा इसे गाने से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें मेरी आयु पर आपत्ति थी क्योंकि वे इसे किसी युवा कलाकार से गवाना चाहते थे। ये भी एक तथ्य है कि इसे गाने वाला गायक मुझसे केवल 4-5 साल ही छोटा होगा। लेकिन मैंने इसे किसी प्रकार से अपने अहं का विषय नहीं बनाया और उन्हें ये कहते हुए गाने दिया 'कि तू यहां गा ले पर स्टेज पर तो मैं ही गाऊंगा।'

यदि आपने कभी इंडियन ओशन की म्यूज़िकल नाइट देखी-सुनी हो तो आपको पता ही होगा कि वो प्रारंभ में ही ऐसा रोचक वातावरण बनाते हैं कि किसी अनिच्छुक दर्षक के लिए भी नाइट छोड़कर वहां से हटना कठिन हो जाए। राजधानी के एनसीयूआई के प्रेक्षागृह में आयोजित उनके नवीनतम शो में भी कुछ ऐसा ही दृष्य देखने को मिला। यहां उन्होंने अपने सह आयोजक एक गैर सरकारी संस्था 'चाइल्ड राइट्स एंड यू' के साथ मिलकर बाल अधिकारों और बच्चों के लिए सुखी बचपन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए जागरूकता के प्रसार के लिए ही म्यूजिकल नाइट में सहभागिता की थी। बैंड ने कई गानों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने दर्शकों की मांग पर कुछ ऐसे गाने भी प्रस्तुत किये जो अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुए हैं जिनमें से एक 'जादू माया, बंदे आदि प्रमुख थे।

राहुल ने बताया, 'हम सदैव ही अपने उन गानों को भी प्रस्तुत करते रहते हैं जो अभी रिलीज़ भी नहीं हुए होते हैं। रिलीज़ न होने से हमारा तात्पर्य ये नहीं होता कि उन्हें इससे पहले प्रस्तुत ही नहीं किया गया।' राम का ये भी कहना है कि वो किसी भी बाचतीत से पहले चॉकलेट अवष्य खिलाते हैं, 'हम तो कुछ भी करने से पहले चॉकलेट अवश्य खिलाते हैं।'

बैंड द्वारा प्रस्तुत किये गए नवीनतम गाने जादू-माया के बारे में उनका कहना था कि उन्होंने अभी तक इसका नामकरण भी नहीं किया है लेकिन इसके बावजूद भी इसे पिछले काफी समय से गाया जाता रहा है।

तो बैंड इतने अद्भुत गाने कैसे बनाता है? के प्रश्न पर उन्होंने बताया, 'यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ये कहेंगे कि ये एक कठिन प्रक्रिया है तो आप भ्रम में हैं। इसकी कोई प्रक्रिया है ही नहीं।' 'हमारे ग्रुप के ही किसी सदस्य ने धुन तो किसी दूसरे सदस्य ने इसे शब्द तथा संगीत आदि से सुसज्जित किया होगा। हां, इसके लिए हमें अधिक मात्रा में चाय की आवष्यकता पड़ती है। हम किसी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं रहते। हम आलसी लोगों का बैंड हैं और आप हमारे उन 60 गानों से ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं जो हमनें पिछले 30 सालों में बनाए हैं। जो प्रतिवर्ष 2 गानों का औसत बनता है', बैंड के ही एक अन्य सदस्य हिमांषु जोषी ने हमें बताया, जबकि राम और निखिल राव उनके समीप ही बैठे बात सुन रहे थे।

कहा जा सकता है कि पिछले 30 सालों के दौरान बैंड में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं, बैंड के सर्वाधिक ऊर्जावान सदस्य राम ने हमें बताया, 'हम संगीत और उपकरणों के मामले में काफी बदल चुके हैं। वर्ष 2009 में असीम चक्रवर्ती की मृत्यु के बाद 2013 में सुष्मित सेन द्वारा भी हमें छोड़ने के बाद कुछ नए सदस्यों का आगमन हुआ है। हमनें कभी हमारे पुरानी रीति को बनाए रखने का प्रयास नहीं किया क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो नए सदस्य की रचनात्मकता के लाभ से हम वंचित हो सकते हैं। हम हर दिन कुछ न कुछ विकसित होते रहना चाहते हैं और साथ ही जीवन की राह में जो मिलने वाली नई चीजों का भी स्वागत करते हैं।'

हम बैंड के किसी सदस्य को खोना नहीं चाहते लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे रोकने में असमर्थ रहे। लेकिन हमें ऐसे हादसों से उबरना होता है। राम ने बताया, 'असीम के देहांत से पहले भी वो कोमा में था और हमारे साथ एक प्रकार से नहीं था। 2009 में उसकी मृत्यु के बाद हम इतने व्यस्त हो गए कि हमारे पास काम के अलावा किसी भी दूसरी बात को सोचने तक का भी समय नहीं था। हम इस दौरान लगातार उसकी पत्नी और बेटे के संपर्क में रहे और अपनी ओर से हमनें जो भी संभव हुआ उनकी मदद की।'

इस बैंड के सभी गाने उत्कृष्ट नहीं थे, राम ने बताया, 'हमनें कई बार गाने बनाए और फिर उनके प्रदर्शन को देखकर लगा कि इन्हें रिलीज़ नहीं किया जा सकता। हमारे स्टोररूम में ऐसे कई गाने हैं जो अधूरे पड़े हैं। हो सकता है कि किसी दिन उन्हें पूरा करना संभव हो।'

अब समय सोशल मीडिया का है। कुछ लोगों को लगता है कि महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए ये बड़े काम का है लेकिन राम इस बारे में कुछ और सोचते हैं, 'अपना सिंगल बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना तो ठीक है और इससे कई लोगों को लाभ भी हो रहा है लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। देखिये 90 प्रतिशत कलाकार तो गंभीर होते ही नहीं। सोशल मीडिया पर तो उनका जमघट लगा रहता है। इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता।'

लेकिन इंडियन ओशन के गानों की कोई सीमा नहीं है क्योंकि हम दिसंबर में पांच या छ: गाने लाने की तैयारी कर रहे हैं, राव ने हमें बताया, 'हम अगले महीने अपने कुछ गाने ऑनलाइन और निषुल्क लाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गाने लोगों तक आसानी से उपलब्ध हों।'

संवेदनशील होना कमजोर होना नहीं: हरलीन सेठी

मुंबई। रोमांटिक वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफूल' में नायिका की भूमिका निभा रहीं अभिनेत्री हरलीन सेठी का कहना है कि संवेदनशील होना, किसी व्यक्ति का कमजोर होना नहीं होता, बल्कि उससे उसकी ताकत का अंदाजा लगता है।

इन दिनों सिनेमा में दिखाए जाने वाले महिलाओं के किरदार में वास्तविकता अधिक होती है। इस बारे में हरलीन ने कहा, 'इन दिनों, मैं महिलाओं को दृढ़ सोच, पेशे के प्रति उन्मुख होने के साथ ही उन्हें अपने संवेदनशील हिस्से को दुनिया से छिपाते हुए देखती हूं। लेकिन वे ऐसा क्यों करती हैं? संवेदनशील होना आपको एक इंसान के तौर पर कमजोर नहीं बनाता है। आपके उस पहलू को प्रदर्शित करना गलत नहीं है। इसमें भी आपकी मजबूती झलकती है। मुझे नहीं लगता कि एक मजबूत महिला की परिभाषा बस इतनी है कि वह अपने लिए आवाज उठाए और जो आपकी आलोचना करते हैं उन्हें जवाब दें। आप एक ही समय में भावुक और मजबूत हो सकते हैं।'

एकता कपूर द्वारा निर्मित इस शो के नए सीजन में विक्रांत मेस्सी, शीतल ठाकुर, मेहरजान माजदा, जितिन गुलाटी भी हैं। शो का नया सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर और ऑल्ट बालाजी पर 27 नवंबर से प्रसारित होगा।

अब फिल्में नाम से नहीं अच्छे काम से चलती हैं

सिनेमा में क्रांतिकारी बदलाव आया है: प्रोसेनजीत

पणजी। बंगाली और हिंदी सिनेमा में अपनी अहम भूमिका के लिए पहचाने जाने वाले बंगाली अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी का कहना है कि पिछले 15 सालों में भारतीय और विशेषकर हिंदी सिनेमा में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और अब फिल्में हीरो हिरोइन के नाम से नहीं बल्कि अच्छे काम और अच्छी कहानी के दम पर चलती हैं।

बंगाली और हिंदी फिल्मों के प्रमुख हस्ताक्षर विश्वजीत चटर्जी के पुत्र और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म छोटो जिज्ञासा से बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत करने वाले प्रोसेनजीत चटर्जी ने यहां 50वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्मोत्सव में मास्टर क्लास सत्र में कहा, हिंदी, बंगाली, मराठी या किसी भी अन्य सिनेमा की बात कर लीजिए, आज हीरो हिरोइन के नाम से नहीं बल्कि अच्छे अभिनेता और अच्छी कहानी के दम पर फिल्म चलती है।

उन्होंने उपस्थित फिल्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 15 साल में भारतीय सिनेमा में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अच्छे हीरो नहीं अच्छे अभिनेता की मांग बढ़ी है। प्रोसेनजीत चटर्जी ने इस सत्र में न्यूआंसेस आफ एक्टिंग में कहा, यही कारण है कि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी भारतीय सिनेमा का चेहरा बन जाता है। यह सब बदलाव देखकर अच्छा लगता है। आज फिल्म नवाजुद्दीन के नाम से बिकती है, उसके लुक से नहीं।

वह कहते हैं, नए कलाकारों के लिए सिनेमा में किस्मत आजमाने के लिए यह सही समय है। बिमल रॉय की दुती पता , डेविड धवन की आंधियां और ऐश्वर्या राय के साथ चोखेर बाली में अभिनय कर चुके प्रोसेनजीत का फिल्मी सफर 30 से 35 सालों के बीच और 300 से अधिक फिल्मों तक फैला हुआ है।

प्रोसेनजीत को रितुपर्णो घोष की दोसार फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विशेष ज्यूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रसिद्ध बांग्ला निर्देशक गौतम घोष की फिल्म मोनेर मानुष में 19वीं सदी के प्रख्यात आध्यात्मिक नेता, गायक और लोक गायक लालोन की भूमिका अदा की थी। इसके साथ ही जातिश्वर में एंटनी फिरंगी की उनकी भूमिका को काफी सराहा गया था जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था।

वह कहते हैं, सिनेमा मेरे लिए जिंदगी है। पिछले 30 सालों में बदलाव केवल इतना आया है कि पहले मैं प्रोडक्शन, डायरेक्टर को देखकर फिल्में साइन करता था लेकिन अब मुख्य फोकस उन भूमिकाओं को अदा करने पर है जो आज तक दर्शकों के सामने नहीं आ पाई हैं।

मॉडरेटर सचिन चेत्ते के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, बेहतर से बेहतर करने की भूख से ही उन्हें अभिनय के लिए उर्जा मिलती है। 30 साल के फिल्मी कैरियर के बाद भी किसी भूमिका को अदा करने की बची इच्छा का खुलासा करते हुए प्रोसेनजीत कहते हैं, जलसाघर जैसी भूमिका का सपना अभी भी मेरे भीतर दबा हुआ है।

स्पॉटलाईट अवॉर्ड से सम्मानित होंगी जेनिफर लोपेज

हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर लोपेज को 31वें वार्षिक पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पॉटलाइट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेत्री को यह अवॉर्ड फिल्म 'हस्टलर्स' के लिए पाम स्प्रिंग्स कॉन्वेंशन सेंटर में 2 जनवरी को दिया जाएगा।

फेस्टिवल के चेयरमैन हेरोल्ड मैटनर ने कहा, 'जेनिफर लोपेज हर मायने में स्टार हैं और उनकी आगामी फिल्म 'हस्टलस' में आप भी महसूस करेंगे।' मैटनर ने आगे कहा, 'जबरदस्त परफॉर्मेंश के लिए उन्हें ये अवॉर्ड मिलना चाहिए, जेनिफर लोपेज को साल का स्पॉटलाइट अवॉर्ड देने को लेकर हम काफी उत्साहित हैं।'

विदेशी भाषाओं में फिल्में यर्थाथवादी और कलात्मक होती हैं: इम्तियाज

पणजी। निर्माता-लेखक इम्तियाज अली का कहना है कि वह विदेशी भाषाओं में फिल्में देखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर ढंग से तैयार किया जाता है और वे कलात्मक और यर्थाथवादी होती हैं। चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई) के 50वें संस्करण में 'द कंटेम्पररी फिल्ममेकर्स ऑफ डिफरेंट जेनरेशंस' पर एक सत्र के दौरान उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उन्हें विदेशी भाषाओं में फिल्में देखना पसंद है।

क्या हिंदी में बनाई जाने वाली फिल्मों की तुलना में वे बेहतर होते हैं? इस पर इम्तियाज ने बताया, 'हां, मुझे लगता है कि विदेशी भाषाओं में फिल्में बेहद यर्थाथवादी और कलात्मक होते हैं और इन्हें बेहतर ढंग से बनाई जाती हैं जिस वजह से इन्हें देखने में मजा आता है। भाषा से ज्यादा मैं निर्देशकों का अनुकरण करता हूं। मैं डेविड लीन की फिल्में देखा करता था।' उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, 'जहां तक हिंदी की बात है तो मुझे बिमल रॉय, विजय आनंद और राज कपूर बेहद पसंद है। फिलहाल (तत्कालीन फिल्मनिर्माता) सभी मेरे दोस्त हैं, तो मैं दोनों अनुराग (बासु और कश्यप), जोया (अख्तर), राजू हिरानी सहित सभी की फिल्में देखता हूं।' इम्तियाज को अपने समकालीन हिंदी फिल्म निर्माताओं पर गर्व भी है क्योंकि वे पहले की अपेक्षा लोगों को कहीं अधिक वास्तविक रूप से चित्रित करने में समर्थ हैं। उन्होंने कहा, 'सिनेमा में लोग, चाहे वे हीरो हो या नहीं, अधिक विश्वसनीय और यर्थाथवादी हैं।'

दुनिया की बेहतरीन फिल्मों को देखने के लिए इफ्फी में बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं दर्शक

भाषा। पणजी

भारत के 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) को इस बार बाई दी ग्रेस आफ गॉड , कमिटमेंट डेनियल , डेविल बिटवीन द लेग्स , गेस्ट ऑफ ऑनर , पेन एंड ग्लोरी तथा दी गोल्डन ग्लव जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए याद किया जाएगा। इस बार इफ्फी में ऐसी ही कुछ बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है जिन्हें देखने के लिए दर्शक अच्छी खासी संख्या में उमड़ रहे हैं। बाई दी ग्रेस आफ गॉड निदेशक फ्रेंकोइस ओजन की फ्रेंच फिल्म है। अपने कथानक के चलते इस फिल्म की इफ्फी में काफी चर्चा हो रही है।

वास्को से फिल्म देखने आईं गृहिणी टीना इस फिल्म के कथानक से काफी प्रभावित हैं और कहती हैं कि इस प्रकार के विषयों पर खुलकर चर्चा किए जाने की जरूरत है। साल 2004 में इफ्फी का आयोजन शुरू होने के बाद से वह लगातार इस फिल्म समारोह में आ रही हैं। हालांकि मुख्य रूप से उनकी पसंद कोंकणी फिल्में हैं लेकिन उन्हें विश्व प्रतिस्पर्धा सिनेमा के तहत दिखाई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय फिल्में और मलयाली फिल्में देखना विशेष तौर पर पसंद है। कहानी का कथानक कुछ इस प्रकार है कि अपने परिवार के साथ लियन में रहने वाले अलेक्जेंडर के साथ बचपन में एक पादरी ने दुराचार किया था। एक दिन उसे पता चलता है कि वह पादरी आज भी वही कर रहा है। अलेकजेंडर इस इंसान के खिलाफ कार्वाई करने की हिम्मत जुटाता है। यह फिल्मफादर बर्नार्ड प्रेनैट के सच्चे केस पर आधारित है जिस पर साल 2016 में लियन में 70 बच्चों के शारीरिक शोषण का आरोप लगा था। इस फिल्म को बर्लिन फिल्मोत्सव 2019 में सिल्वरबीयर ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड से नवाजा गया था।

इफ्फी की बढ़ती लोकप्रियता का हाल यह है कि सभी श्रेणियों में फिल्मों के टिकट बिक चुके हैं और हर स्क्रीनिंग हाल में दर्शकों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इसी श्रेणी की चर्चित फिल्म है रवांडा। फिल्म रिकार्डो सैलवेती द्वारा निर्देशित अंग्रेजी फिल्म है जिसमें इतिहास के एक भयानक नरसंहार को दिखाया गया है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसमें एक महिला, उसका पति और उसके परिवार को दिखाया गया है। इस कहानी में किसी को मरना है तो किसी को मारना है। नरसंहार की भयावहता बयान करती यह सशक्त कथानक वाली सैलवेती की पहली फीचर फिल्म है।

75 साल की सुमिता दासगुप्ता इंदौर की रहने वाली हैं लेकिन वह हर साल इफ्फी समारोह के लिए अपनी गोवा में रहने वाली बेटी नैना के पास आ जाती हैं। पिछले साल इफ्फी के दौरान उन्होंने 22 फिल्में देखी थीं। उनका कहना है कि इफ्फी में विश्व का श्रेष्ठ सिनेमा दिखाया जाता है और इसलिए हर साल वह इसके लिए गोवा आती हैं। इस बार बीमार होने और व्हीलचेयर की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वह फिल्म नहीं देख पाई हैं लेकिन समारोह के अहसास को जीने के लिए अपनी बेटी के साथ इफ्फी समारोह स्थल घूमने के लिए आई हैं।

इसी प्रकार तुर्की के पटकथाकार, फिल्म निर्देशक और निर्माता सेमीड कापलैनोग्लू की फिल्म कमिटमेंट भी अपने कथानक के चलते खूब सराही जा रही है। इसमें असली नामक महिला अपने बच्चे के लिए आया की तलाश में है और उसकी मुलाकात गुलनीहाल से होती है जो खुद एक मां है। इस फिल्मको 92वें अकैडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में तुर्की कीओर से एंट्री मिली थी।

मैक्सिको में जन्में पटकथाकार और निर्देशक आरदुरो रिप्सटीन की स्पेनिश भाषा में बनी फिल्म डेविल बिटवीन दी लेग्स एक बूढ़े इंसान और खूबसूरत बीट्रिज के बीच की कहानी है। उनकी नौकरानी के दोनों के बीच में आने से कहानी किस खूबसूरती से बदलती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। 21साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म टाइम टू डाई बनाने वाले आरदुरो वुमन आफ द पोर्ट , ला रीना दा ना नोशे और डीप क्रिमसन के श्रेष्ठ निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर पिता और बेटी के बीच के जटिल रिश्तों को सुलझाते हुए पुराने राज और पाशविक प्रवृतियों को बेनकाब करती है। कनाडाई रंगकर्मी और फिल्म निर्देशक एटम इगोयान द्वारा निर्देशित इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर इस साल वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इन सभी फिल्मों की स्क्रीनिंग मास्टर फ्रेम श्रेणी में की जा रही है जो कि विश्व की बेहतरीन फिल्मों का संग्रह है। ए फिल्में सीरियल किलर से लेकर मानवता के अस्तित्व के लिए ही खतरा बनने वाले विषयों को समेटे हुए हैं।